खण्ड-159, अंक-5
बुधवार, 27 आश्विन, शक संवत् 1877
(19 अक्टूबर, 1955 ई0)

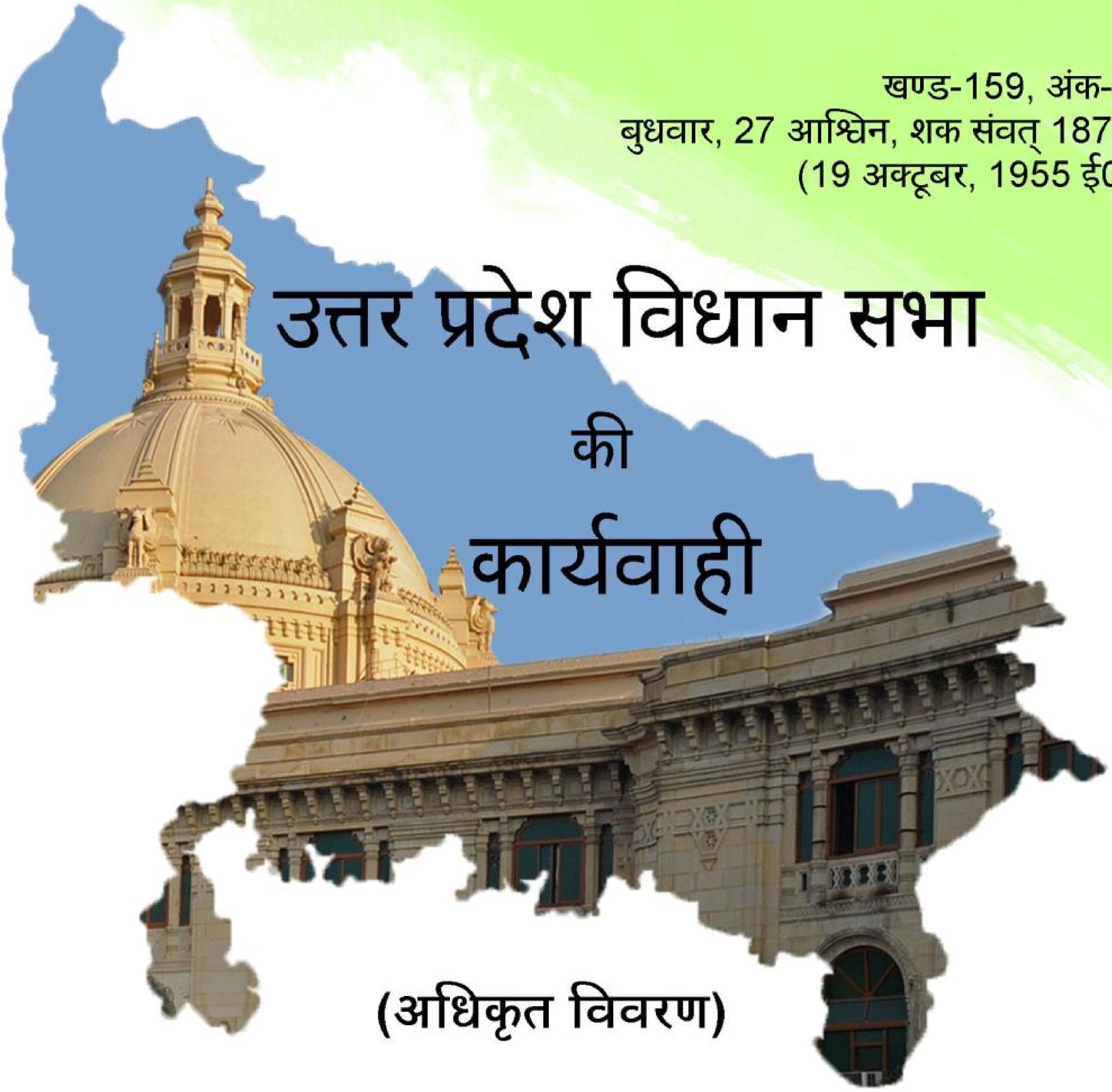

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 159 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ अक्तूबर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमालअहमद रिजवी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्रगुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबक्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

अनुभव प्रदर्शन

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महोलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफतहुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदासधनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वशीनकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री

सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १९ अक्तूबर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रतापगढ़ व इलाहाबाद जिलों में जून-सितम्बर, १९५५ में हुई वर्षा

**१—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ व इलाहाबाद जिलों में १ जून, १९५५ से ३० सितम्बर, सन् १९५५ तक कितनी जल-वृष्टि हुई है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—१ जून से ३० सितम्बर, १९५५ तक, इलाहाबाद जिले में ४८.५६ इंच और प्रतापगढ़ जिले में ५८.३९ इंच वर्षा हुई है।

तारांकित प्रश्न

भलिनगना (टेहरी) के कम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्य में विलम्ब

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भलिनगना (टेहरी) में कम्युनिटी प्रोजेक्ट खोलना अक्तूबर, १९५३ में स्वीकार कर दिया गया था पर मई, १९५४ तक वहां कार्य ठीक तरह से प्रारम्भ नहीं हो सका ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां। इस ब्लाक में मई, १९५४ से कार्य इस वजह से शुरु हुआ कि ब्लाक के आर्थिक व प्रशासकीय कंट्रोल के प्रश्न पर सरकार और सुश्री मीरा बेन में कई बार बातचीत होने पर भी एक मत न हो सका।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि प्रारम्भ में सुश्री मीराबेन की देख-रेख में इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हुआ था और बाद में उन्हें बहुत सी कठिनायां हुई? यदि हां, तो वह क्या थीं और उन्हें दूर करने का क्या प्रयत्न किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सुश्री मीराबेन की बताई हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिये उनसे कई बार मीटिंग हुई। उनमें जो सुझाव तय हुए उसमें उन्होंने फिर बदलाव करना चाहा। शासन की जिम्मेदारी को ध्यान में रखने हुए ये न मानी जा सकीं। इस बीच में वे कश्मीर चली गईं और उन्होंने यिलंगाना से सम्पर्क छोड़ दिया।

*३—श्री सुरेन्द्रदत वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि मार्च, १९५४ में प्रादेशिक सरकार ने कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन को यह सिफारिश की थी कि इस प्रोजेक्ट को प्लानिंग कमीशन की देख-रेख में ले लिया जावे ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---पत्र की प्रतिलिपि देना जनहित में न होगा ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस कार्य में किस कारण देरी हुई कि सरकारी अफसरों का सहयोग सुश्री मीराबेन को प्राप्त नहीं था ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)---जैसा अभी जवाब में बतलाया गया है कि सरकारी अफसरों के संबंध में स्वयं पूज्य पंत जी ने मीराबेन जी से बातचीत की और जो बातें यहां तय हुई थीं मीराबेन जी ने उनको फिर बदलना चाहा, इस वजह से देर हुई ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या यह सत्य है कि सुश्री मीराबेन इस कार्य को गांधियन लाइन्स पर चलाना चाहती थीं ?

श्री फूलसिंह---जी हां ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार इस पर तैयार नहीं हुई कि इस कार्य को गांधियन लाइन्स पर प्रारम्भ किया जाय ?

श्री फूलसिंह---यह सत्य नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सुश्री मीराबेन को जो वहां कठिनाइयां थीं वह कौन-कौन सी थीं ?

श्री फूलसिंह---जैसा उत्तर में बतलाया जा चुका कि कई मर्तबा पूज्य पंत जी ने उनको यहां बुलवा कर स्वयं मीटिंग की और बहुत सारी बातें तय कीं । मीटिंग के बाद मीराबेन जी ने वहां से खत लिख दिया और बहुत सी बातों को बदल दिया । मीराबेन जी का इतना ऊंचा स्तर है कि यह अच्छा नहीं होगा कि उन तमाम बातों की छानबीन यहां की जाय ।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस प्रोजेक्ट की अवधि कब से मानी जायगी और कब खत्म होगी ?

श्री फूलसिंह---जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या यह सही है कि सुश्री मीराबेन उसको एक पाइलट प्रोजेक्ट बनाना चाहती थीं ?

श्री फूलसिंह---यह कम्यूनिटी प्रोजेक्ट है ।

झांसी के सीपरी बाजार व नन्दनपुरा मुहालों में सरकारी अस्पताल खोलने की मांग

*४---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के सीपरी बाजार व नंदनपुरा मुहालों की कितनी आबादी है तथा वहां क्या कोई सरकारी अस्पताल है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)---झांसी के सीपरी बाजार तथा नन्दन पुरा मुहालों की आबादी १९५१ की जनगणना के अनुसार ११,६६८ तथा १,०९७ क्रमशः है । इन मुहालों में सरकारी अस्पताल नहीं हैं ।

*५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आबादियों से सिविल अस्पताल कितनी दूर है ?

श्री बनारसी दास---सिविल अस्पताल सिपरी बाजार से करीब २ मील तथा नन्दनपुरा से तीन मील की दूरी पर है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस दरमियान में उक्त मुहालों की आबादी और भी ज्यादा बढ़ गई है ?

श्री बनारसी दास---जी हां। यह ५१ की मतगणना की संख्या है और तीन चार साल के दरमियान में आबादी जरूर बढ़ी होगी।

श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या माननीय मंत्री जी उक्त मुहालों की लगभग १५ हजार आबादी तथा सिविल अस्पतालों की दूरी को ध्यान में रखते हुये वहां पर और अस्पताल खोलने की कृपा करेंगी ?

श्री बनारसीदास---वहां पर अधिकतर रेलवे कर्मचारियों की आबादी है, वहां से थोड़ी दूर पर रेलवे का अस्पताल भी है। इसके अलावा सीपरी के नजदीक दो मिशन के अस्पताल भी हैं। इसलिये वहां कोई नई डिस्पेंसरी खोलने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*६-७---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---[प्रश्न ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

काशीपुर गन्ना फैक्टरी द्वारा गन्ने की निर्धारित कीमत के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*८---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार के पास काशीपुर क्षेत्र, जिला नैनीताल के गन्ना उत्पादकों तथा फार्मर्स यूनियन द्वारा काशीपुर फैक्टरी द्वारा गन्ना की निर्धारित कीमत कम किये जाने के सिलसिले में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र उद्योग मन्त्री के पास आया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास---जी हां। गन्ने के मूल्य का संबंध केन्द्रीय सरकार से है और इस सिलसिले में प्रदेशीय सरकार अपनी सलाह उनको दे चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में क्या सलाह दी है ?

श्री बनारसीदास---गन्ने के बारे में सलाह यह दी है--चूंकि वहां पर शुगर का कंटेंट कम होता है इसलिये दो आने प्रतिमन वहां पर गन्ने की कीमत कम की जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---यह जो सलाह सरकार ने दी है कि तराई एरिया में शुगर कंटेंट कम होता है वह सलाह सरकार ने किस आधार पर दी है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---हमारे सलाहकार जो इस विषय में जांच करते हैं उन्होंने हमें इस बात की सलाह दी है और हमें उन व्यक्तियों से भी पता चला है जो इस व्यापार को वहां चलाते हैं, उनका कहना भी है कि वहां के गन्ने में शुगर कंटेंट कम होता है।

श्री गेंदासिंह---जिन एडवाइजर्स ने ऐसी सलाह दी है उन्होंने किन-किन मिलों के लिये ऐसी सलाह दी है और सूबे में किन-किन और जगहों पर शुगर कंटेंट कम होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---तराई के गन्ने में शुगर कंटेंट कम होता है इसका सवाल वर्षों से चला आ रहा है और प्रत्येक व्यक्ति जिसने वहां गन्ने का रोजगार किया है वह भी इस बात को मानता है कि वहां के गन्ने में शुगर कंटेंट कम रहता है। और जहां तक प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का संबंध है, उसके विषय में इस समय सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सरकार ने जो सलाह केन्द्रीय सरकार को दी है क्या शुगर कंट्रोल बोर्ड के सामने भी वह यह सलाह देने को तैयार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी आवश्यकता नहीं है। जो इतनी अधिक मात्रा में गन्ना उत्पन्न होता है उसका ठीक तरह से उपयोग हो जाय और वहां के जो उत्पादक हैं उन्हें अधिक से अधिक फायदा गन्ने से रोजगार के मिल सके इसलिये सरकार ने जो व्यावहारिक बात ठीक समझी उसे केन्द्रीय सरकार के समक्ष सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर दी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्टेट फार्म का भी गन्ना इस फैक्टरी में जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, और उसका भी शुगर कंटेंट कम है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो एडवायजर्स हैं, उनके नाम क्या है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो शुगर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर में हैं उन्हीं से हम इन बातों के सिलसिले में सलाह करते हैं और वे जो हमें सलाह देते हैं, उसकी बुनियाद पर हम अपनी राय बनाते हैं और उस राय को केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रकट करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि चीनी की रिकवरी गन्ने की क्वालिटी की वजह से कम नहीं होती है बल्कि मशीनरी की खराबी की वजह से होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ हिस्सा इस रिकवरी का मशीन की खराबी की वजह से भी कम हो सकता है लेकिन वास्तविक बात यह है कि गन्ने की क्वालिटी इन क्षेत्रों में बहुत कमजोर है और उसके सुधार और विकास के लिये सरकार प्रयास कर रही है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इस कीमत के मसले को और कंटेंट के जितने भी पार्टिकुलर्स आये हैं उनको शुगर केन बोर्ड के सामने रखने की मेहरबानी करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसकी इस वक्त कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर शुगर केन बोर्ड कुछ और अधिक जानकारी जानने की कोशिश करेगा या प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो अवश्य इस पर विचार किया जा सकता है। इस विषय में मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि बार-बार यह सवाल इस तरह से उठाया जाता है तो मैं सदन से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि उस क्षेत्र के गन्ने के रोजगार को बताना है तो मैं समझता हूं कि बारबार इस तरह के प्रश्न को उठाकर वे साथी जो गन्ने के रोजगार को चलाने के पक्षपाती हैं वे हमें कुछ सहायता या सहयोग प्रदान नहीं करते हैं बल्कि उन लोगों को रोकते हैं, जो इस प्रकार का रोजगार लगाने के लिये हमें सहयोग प्रदान करते हैं।

श्री गेंदासिंह—सरकार इस बात का ख्याल करके कि सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके कोई इस तरह की कमेटी बनाने की मेहरबानी करेगी जो इन सारी चीजों को छानबीन करके जो गलतफहमी पैदा हो रही है, उसको दूर करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गलतफहमी तो उन लोगों को है नहीं जो रोजगार को चला रहे हैं। गलतफहमी ऐसे व्यक्तियों को हो सकती है जो गलतफहमी पैदा करने की चेष्टा करना चाहते हैं।

देवरिया जिले में कोल्हुओं का वितरण

*६—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में किन-किन क्षेत्रों में कितने कोल्हू अब तक दिये गये हैं ?

श्री बनारसी दास—सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में ४२८ कोल्हू वितरण किये गये :—

देवरिया क्षेत्र में	..	..	१८९
पडरौना क्षेत्र में	..	..	१४५
सलीमपुर क्षेत्र में	..	..	४८
हाटा क्षेत्र में	..	..	४६

*१०—श्री रामसुभग वर्मा—कोल्हू की कुल कीमत कितनी है और वह किस हिसाब से वितरण किया जाता है ?

श्री बनारसी दास—समय-समय पर कोल्हू का मूल्य बदलता रहता है और उसी के अनुसार वह वितरण किया जाता है। इस समय मूल्य ३३५ रुपया प्रति कोल्हू है। कोल्हू के मूल्य में रेल भाड़ा ठेला आदि के खरचे भी शामिल रहते हैं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोल्हुओं की अधिक मांग होते हुये भी पर्याप्त मात्रा में कोल्हू वहां नहीं पहुंच सके ?

श्री बनारसीदास—बात यह है कि नाहन कोल्हूओं का जहां तक सवाल है जो कि अच्छे किस्म के कोल्हू होते हैं वहां उनका उत्पादन कम होता है और मांग अधिक होती है। लेकिन इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि वहां पर कोल्हू ज्यादा मांगे गये और उनकी सप्लाई नहीं की जा सकी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने कम कोल्हू क्यों बटे ?

श्री बनारसी दास—जितने लोगों ने कोल्हू मांगे, उतने दे दिये गये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—सरकार को यह पता है कि कोल्हू के लिये हजारों दरख्वास्तें किसानों की पड़ी थीं ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की तो कोई सूचना नहीं। और जितने भी कोल्हू दिये गये हैं ज्यादातर तकावी पर दिये गये हैं। नकद तो बहुत ही कम गये हैं।

बदायूं जिलान्तर्गत सहसवान में कपड़ा बुनने के ट्रेनिंग स्कूल का बन्द होना

*११—श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि सहसवान, जिला बदायूं में जो कपड़ा बुनने का स्कूल था वह क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री बनारसी दास—पर्याप्त संख्या में शिक्षार्थी नहीं मिल रहे थे। इस कारण यह केंद्र बन्द कर दिया गया।

श्री मुश्ताक अली खां—क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि इस स्कूल कितने के इंस्ट्रक्टर सिखाने का काम करते थे ?

श्री बनारसी दास—यह तो १९५१ में बन्द कर दिया गया। इस वक्त तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन जहां तक शिक्षार्थियों का सवाल है जब यह बन्द किया गया उनकी तादाद सिर्फ दो रह गयी थी।

श्री मुश्ताक अली खां—क्या यह वाकया नहीं है कि जो इंस्ट्रक्टर वहां सिखाते थे, उन्होंने उसमें कुछ रुपया और कपड़ा अलहदा कर लिया ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की तो कोई खबर नहीं है।

बदायूं जिले में नाजायज शराब के मुकदमे

*१२—श्री मुश्ताक अली खां—क्या सरकार मेहरबानी क के बतलायेगी कि जिला बदायूं में नाजायज शराब बनाने के सिलसिले में सन् १९५३–५४ ई० में कितने मुकदमात चालान किये गये ?

माल-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—बदायूं जिले में सन् १९५३–५४ ई० में नाजायज शराब बनाने के सिलसिले में ३४ मुकदमों का चालान किया गया।

श्री मुश्ताक अली खां—जो मुकदमे चालान किये गये उनमें से कितने सजायाब हुये ?

श्री गिरधारी लाल—इसमें १४ मुकदमों में कनविक्शन किया गया और २० मुकदमों को डिस्चार्ज किया गया।

आजमगढ़ जिले में छोटी सरयू नदी पर चांद पट्टी के पुल पर अनुमानित व्यय

*१३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की छोटी सरयू नदी पर चांद पट्टी में जो पुल बन रहा है, सरकार उसके लिये कितना धन खर्च करने जा रही है और वह कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस पुल पर कुल साठ हजार रुपया खर्च होगा। २१ हजार रुपया जनता द्वारा जमा किया गया है और बाकी ३९ हजार रुपया सरकार खर्च करेगी। सन् १९५६ की बरसात से पहिले पुल के तैयार हो जाने की आशा की जाती है।

श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह पुल किस विभाग के इंजीनियर द्वारा बनाया जायगा और जो २१ हजार रुपया चन्दा का इकट्ठा किया गया है वह रुपया अब तक इंजीनियर के पास पहुंचा है या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह पुल सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जायगा और जो २१ हजार रुपया जनता द्वारा एकत्रित हुआ है वह अभी जिलाधीश ने इर्रीगेशन विभाग को नहीं दिया है। जैसे ही वह दिया जायगा वैसे ही कार्य प्रारम्भ कर दिय जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या इस पुल के संबंध में जिला बोर्ड और प्लानिंग कमेटी ने भी कुछ सहायता दी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिला बोर्ड की सहायता का तो पता नहीं, दी है या नहीं किन्तु यह जो ४९ हजार रुपया खर्च करेगी सरकार, वह तो नियोजन समिति द्वारा ही खर्च होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार बतायेगी कि जिलाधीश ने यह रुपया इर्रीगेशन विभाग को क्यों नहीं दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यहां से उसके सिलसिले में उनको लिख दिया गया है लेकिन अभी रुपया आया नहीं। यह आशा की जाती है कि अगले महीने तक आ जायगा और फिर इर्रीगेशन विभाग उस कार्य का सम्पादन करना शुरू कर देगा जिसके लिये यह रुपया वहां की जनता ने देने के लिये इकट्ठा किया है।

श्री राजनारायण—क्या यह सत्य है कि जिलाधीश द्वारा शीघ्रातिशीघ्र रुपया इर्रीगेशन विभाग को न देने से योजना में विलम्ब हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इर्रीगेशन विभाग ने यह निर्णय किया था कि बरसात के बाद इस कार्य को प्रारम्भ करेंगे अभी तो बरसात चल ही रही है जब रुपया आ जायगा तभी कार्य शुरू हो जायगा। यह नहीं है कि रुपया नहीं आया इसलिये कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

नैनीताल स्थित खेल-कूद निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र के संबंध में पूछताछ

*१४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि नैनी ाल स्थित खेल-कूद निर्माण प्रशिक्षण के द्र से ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षार्थियों को भविष्य में काम देने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री बनारसीदास—सरकार की कोई योजना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस खेल-कूद सामग्री निर्माण प्रशिक्षण के द्र से ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग देने के लिये सरकार का उद्देश्य क्या है, इनको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है ?

श्री बनारसीदास—शिक्षार्थियों को आधुनिक किस्म की शिक्षा दे कर उनको स्वावलम्बी बनाना।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षार्थियों द्वारा अगर स्वावलम्बी आधार पर कोई कार्य शुरू किया गया तो सरकार सहायता देगी ?

श्री बनारसीदास—जी हां। उनको ऋण और अनुदान के रूप में। अगर प्रार्थना-पत्र आयेंगे तो अवश्य उनको दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने इस कार्य के लिये यानी अनुदान आदि के संबंध में कोई धनराशि निर्धारित की है।

श्री बनारसी दास—जी हां, धनराशि है और आवश्यकता पड़ने पर उसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिये एक कमेटी होती है अ र इसके अतिरिक्त यह लोग शिक्षा समा त होने के बाद औद्योगिक समिति बना सकते हैं फिर उनको और सहायता दी जाती है।

आगरा मेडिकल कालेज के लिये प्राप्त भूमि खण्ड

*१५—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आग ा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बत ने की कृपा करेंगे कि आगरा मेडिकल कालेज के लिये १,००० शैय्या वाला अस्पताल बनाने के लिये जो भूमिखंड लिया गया था उसे सार्वजनिक प्रयत्न द्वारा क्षय के लिये कोई सेनिटोरियम खोलने के लिये दे देने का विचार वे रखते हैं ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस भूमिखंड को प्राप्त करने के लिये कितना व्यय हुआ था और अब उसका क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री बनारसीदास—इस वक्त मुझे ठीक रकम तो मालूम नहीं है कि कितने में यह जमीन ली गयी थी, लेकिन जहां तक इसके उपयोग क सवाल है यह जमीन, इस वक्त वहां जो मेंटल अस्पताल है उसक दे दी गयी है और इसकी योजना यह है कि सौ बेड्स वहां पर ढा दिये जायं और वहां पर बाकी जमीन में खेती-बाड़ी की जाय। रोगी लोग करें, जिससे थोड़ा कमा भी सकें।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह भूमिखंड कितना है और उसमें से कितना मेंटल हास्पिटल को दिया गया ?

श्री बनारसीदास—यह कुल ५० एकड़ था और सभी दे दिया गया है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बत ाने की कृपा करेगी कि सरकार ने आगरे में कोई ऐसी योजना बना ली है जिस से रोगी खेती कर सकें ?

श्री बनारसीदास—जैसा बतलाया गया है मेंटल अस्पताल को ५० एकड़ भूमि दे दी गयी है। तार खिचवाने की व्यवस्था की है, ट्यूबवेल के लिये भी स्वीकृति दे दी गयी है जिसमें कि ऐसी शैय्यायें बन सकें। बाकी में खेती होगी जिसमें कि रोगी लोग स्वयं ही अपना काम करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मेंटल हास्पिटल में कितने आदमी ऐसे हैं जो उस खेती पर काम करते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह अस्पताल तो ६००–७०० बेड्स का रहा है और जैसा कि कहा गया है बढ़ाया जाने वाला है। मेंटल केसेज के इलाज के सिलसिले में जो नये तरीके निकले हैं उसमें आकुपेशनल थेरापी का बहुत बड़ा स्थान है, इसीलिये इस अस्पताल में भी आकुपेशनल थेरापी का प्रमुख स्थान रखा गया है। इसलिये जो जगह मेडिकल कालिज के लिये ली गयी थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसमें इस्तेमाल किया जायगा। उसमें मरीजों के काम करने के लिये विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग-धंधे चलाये जायेंगे। आधुनिक मेंटल हास्पिटल में आकुपेशनल थेरापी का मेंटल डिजीजेज के इलाज में बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिये हम भी अपने प्रदेश में आकुपेशनल थेरापी को मेंटल डिजीजेज के लिये प्राथमिकता और एक प्रमुख स्थान देना चाहते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सौ बेड्स बन जाने के बाद आने वाले ५ सालों में इस रोग से पीड़ित संख्या के लिये पूरे तौर से आगरे का अस्पताल इन्तजाम कर लेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने कल अपनी रिपोर्ट को उपस्थित करते हुये बताया था कि मेंटल केसेज के बेड्स के लिये प्रदेशीय सरकार की जो योजना बनी थी उसके तत्वावधान में सौ बेड्स की संख्या इस अस्पताल में और सौ बेड्स की बरेली के अस्पताल में और दो सौ बेड्स का एक अस्पताल किसी पूर्वी जिले में स्थापित किया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिस भूमि को मेडिकल कालेज के लिये लिया गया था और उसको उस काम में नहीं लिया गया, क्या उसको वापस करने के लिये उनके पास दरख्वास्तें आई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे तो इसकी सूचना नहीं है। मुमकिन है कि नीचे कोई अर्जियां आई हों।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी उन अर्जियों पर गौर करेंगे और किसानों को कुछ भूमि उसमें से लौटाने का प्रबन्ध करेंगे?

श्री अध्यक्ष—यह उत्पन्न नहीं होता। उनको इतना ब्योरा मालूम ही नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिस एक हजार शय्या वाले अस्पताल के लिये ये भूमिखंड प्राप्त किया गया था उसमें अब जो शय्यायें कम हैं जिसकी वजह से जनता को बहुत कष्ट है, उसको दूर करने के लिये वह क्या उपाय सोच रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस अस्पताल को तो बहुत बड़ा बना रहे हैं और शय्यायें भी वहां बढ़ा रहे हैं। अभी योजना में, जो कि चालू है, उसमें ही उस अस्पताल को परिवर्द्धित करने के लिये धनराशि रखी गयी थी। दुर्भाग्य से उसका अनाटामी और सर्जिकल वार्ड तैयार नहीं हो सका। अस्पताल तैयार हो जायगा तो दो सौ बेड्स और बढ़ जायेंगे। अभी शायद साढ़े चार सौ हैं। तो फिर ६००–७०० हो जायंगी और उससे भी अधिक आवश्यकता होगी तो जो मौजूदा इमारतें हैं उन्हीं में उनको-दो मंजिल करा के बेड्स बढ़ा दी जायंगी।

क्वालिटी मार्किंग योजना का कार्यान्वित होना

*१६—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्वालिटी मार्किंग योजना कब चालू हुई और प्रत्येक वर्ष कुल उत्पादन के किस अनुपात पर क्वालिटी मार्क लगाया गया ?

श्री बनारसीदास—(अ) यह योजना सन् १९४९ में चालू की गई।

(ब) यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस योजना में अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री बनारसीदास—इस वक्त यह तो मालूम नहीं है क्योंकि यह योजना सन् १९४९ से चालू की गयी और बराबर इसमें वृद्धि होती गयी। यदि माननीय सदस्य चाहें तो बाद में इसकी सूचना उपलब्ध की जा सकेगी।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी इसके आंकड़े उपलब्ध करके इस पर विचार करेंगे कि इसे किस तरह से अधिक इफेक्टिव बनाया जाय ?

श्री बनारसीदास—जी हां। यह तो वैसे काफी प्रिय होती चली जा रही है और कई उद्योगों पर इसका अभी विस्तार भी किया जा चुका है।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि विदेशों में भी इसके प्रचार पर रुपया खर्च किया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—विदेशों के अन्दर यह क्वालिटी मार्क्ड माल जरूर जाता है लेकिन वहां तो पहले ही केन्द्रीय सरकार की तरफ से उनके विभाग वगैरह हैं जो इसमें सहायता करते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी उन उद्योगों का नाम बताने की कृपा करेंगे कि जो क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं ?

श्री बनारसी दास—हैंडलूम, आगरे के जूते, अलीगढ़ के ताले, फर्रुखाबाद की छींटें, बनारस का रेशमी सामान, मेरठ की कैंचियां और खेल-कूद का सामान और मिर्जापुर के कालीन।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी भारतीय सरकार के साथ इस प्रश्न पर परामर्श करेंगे कि जो भी सामान इस प्रदेश से बाहर भेजने की इजाजत दी जाय वह वही हो, जो क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्तर्गत आ चुका हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक हमारी इस योजना का सम्बन्ध है अवश्य हम केन्द्रीय सरकार के समक्ष ऐसा सुझाव समय-समय पर रखते रहे हैं कि प्रदेश के इन उद्योगों को चलाने और बढ़ाने के लिये ऐसा माल विदेशों में जाय जो हमारी क्वालिटी मार्किंग स्कीम की तहत में आता हो, क्योंकि अगर विदेशों में अपने माल को चलवाना है और प्रसारित करवाना है तो इस बात की आवश्यकता है कि जो विदेशों में खरीदार हैं वे इस प्रकार का विश्वास हमारे माल के बारे में कर सकें कि जो माल जिस तरह का और जिस क्वालिटी का हम भेजते हैं वह उसी प्रकार का है जैसा कि वह होना चाहिये। लेकिन अभी हमने केन्द्रीय सरकार से ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाने के लिये तो कहा नहीं कि दूसरों का माल न जाने दें। लेकिन हमारे माल के भेजे जाने से अवश्य ऐसी बात है कि क्वालिटी मार्किंग स्कीम के अन्तर्गत आया हुआ माल अधिक मात्रा में अब विदेशों में जा सकेगा और वह अपनी जगह विदेशों के मार्केट में बना सकेगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह मिर्जापुर और उन्नाव जिले के भगवन्त नगर के पीतल के बर्तनों को भी क्वालिटी मार्किंग स्कीम के अन्तर्गत लेने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—अभी तो ऐसा प्रश्न कोई सरकार के सामने नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि भदोही के कालीनों पर क्वालिटी मार्क क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्योंकि उनके बहुत से साथी अभी तक इस योजना में कुछ अड़चनें डालते रहे हैं या उसमें शामिल नहीं हुये हैं ?

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि वे कौन से साथी हैं जो इस योजना में बाधा या अड़चन डाल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे आपके और उस जिले के सब साथियों के नाम तो मालूम नहीं हैं, लेकिन जो इस व्यापार में लगे हुये हैं वे यह समझते हैं कि शायद इस क्वालिटी मार्किंग स्कीम की आवश्यकता नहीं है और इसलिये वे इस योजना में उस प्रकार का सहयोग नहीं दे रहे हैं जैसी कि इस योजना की मंशा है और जिस तरह से उन्हें इसको कामयाब बनाने में सहायता और सहयोग देना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे कि जिससे इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा हो सकें कि उत्पादन के किस अनुपात पर क्वालिटी मार्किंग लगाया गया है ?

श्री बनारसीदास—इसमें बड़ी कठिनाई होगी कि तमाम प्रदेश के उत्पादन का हिसाब लगाया जाय और अन्दाजा लगाया जाय कि किस प्रकार से क्वालिटी मार्किंग हुआ है और इसमें व्यय भी काफी होगा और जिन पर क्वालिटी मार्किंग होता है वह आंकड़े तो सरकार के पास हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुरादाबाद के बर्तन के कारोबार को इस क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्तर्गत लाया गया है ?

श्री बनारसीदास—अभी तो नहीं, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को मुरादाबाद में कब तक लागू किया जायगा ?

श्री बनारसीदास—अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्तर्गत टैक्सटाइल, हैन्ड लूम, कालीन और मुरादाबाद के बर्तन आदि प्रदेश के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध उद्योग हैं उन पर कम्पलसरी तौर पर क्वालिटी मार्किंग करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी प्रदेश के उद्योग-धंधों पर कम्पलसरी क्वालिटी मार्किंग के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि जब इस प्रकार का निर्णय करेंगे तो हमें टोटल कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता जब हम इस प्रकार से कार्य करना प्रारम्भ करेंगे तो कितना सहयोग सदन के माननीय सदस्यों से तथा बाहर से हमें मिलेगा।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या यह बात सही है कि मिर्जापुर जिले में कालीन के ऊपर क्वालिटी मार्किंग में जो संस्थायें सम्मिलित हुई हैं, वह कोआपरेटिव संस्थायें हैं और सरकार से उनको सहायता दी जाती है?

श्री बनारसीदास—नहीं। इसमें जो संस्थायें हैं उनको सहायता देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे मिर्जापुर और मुरादाबाद जिलों का सामान बतलाया गया है, उसी प्रकार से नगीना के आबनूस की लकड़ी का काम मशहूर है उसपर विचार करने का प्रयत्न करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो हमने उन रोजगारों और उद्योगों को लिया है जिनमें घटिया किस्म की चीजें और घटिया तरीके से अपने देश में चलने लगी थीं, जिनकी वजह से इन उद्योगों की बदनामी थी और इस कारण वे उद्योग इस तरह से नहीं चल रहे थे जिस तरीके से कि चलने चाहिये थे। जिन उद्योगों में घटिया किस्म की चीजें इस्तेमाल होने लगेंगी धीरे-धीरे उनको क्वालिटी मार्किंग योजना के तहत में लाने का प्रयत्न करेंगे।

*१७-१८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[स्थगित किये गये।]

*१९-२१—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये।]

*२२-२३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा व्यय तथा उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन

*२४—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा कुल कितना रुपया १९५४ ई० में किस-किस मद पर खर्च किया गया और कितना-कितना रुपया किस-किस मद में बच रहा है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६४ पर)

*२५—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा किन-किन तहसीलों में घरेलू उद्योग चालू किये गये और कहां कहां?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६५ पर)

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मद १ और ११ में आधे से अधिक रकम क्यों बची हुई है और मद १२ में एक लाख साठ हजार में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसका कारण तो यह है कि जो जो काम नियोजन समिति ने स्वीकृत किये थे, उनके लिये ठीक समय पर मैटीरियल नहीं मिल सका, इस कारण से यह रकम छूट गई और खर्च नहीं हो सकी और दूसरा कारण यह है कि यह रकम देर से स्वीकृत होकर गई।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बस्ती जिले की ६ तहसीलों में से केवल एक तहसील में उद्योग-धंधे का कार्य प्रारम्भ किया गया और पांच तहसीलों में क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ?

श्री फूलसिंह--जिस तहसील में किया है उसमें कम्युनिटी प्राजेक्ट है और बाकी कामों के लिये जिला प्लानिंग कमेटी स्वतंत्र है। जहां-जहां वह चाहेगी, काम शुरू किया जायगा।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची में आंकड़े दिये गये हैं, वह वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के हैं या कलेन्डर इयर १९५४ के ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--वे १९५४-५५ के आंकड़े हैं।

श्री शिवनारायण---क्या यह सही है कि जो अनुदान हरिजनों को उनको कुटीर उद्योग के लिये और पानी पीने के लिये दिया गया था, उसमें से ६५ परसेंट रुपया बच गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---आप जो कह रहे हैं, वह बात सही है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से घरेलू उद्योग चलाये गये थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--बहादुरपुर तहसील, जिला बस्ती में रंगाई छपाई की ट्रेनिंग और उत्पादन केन्द्र और नगर तहसील, बस्ती में सिलाई की ट्रेनिंग और उत्पादन केन्द्र और दूसरा चमड़े का काम और उसका उत्पादन का केन्द्र है।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया यह बचा हुआ है, इसका क्या कारण है और बहुत सी स्कीमें जो मंजूर हुई हैं उनको रुपया अभी तक नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---इसका कारण बता दिया गया। आप दुबारा पूछ रहे हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि वह कौन सी मद है कि जिस पर जो प्लानिंग को रुपया दिया गया था उसमें से एक पाई भी खर्च नहीं हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह जो विभिन्न कार्यों के लिये मद नं० १२ है वह १,६०,६२७ रुपये की रकम है, इसमें से खर्च नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष---वह किस कार्य के लिये है, यह वह पूछ रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वह सेंक्शन्ड वर्क्स के लिये है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास जो रुपया जाता है वह लोकल डेवलपमेंट के लिये जाता है और उसमें कोई भी रुपया विलेज इंडस्ट्रीज के लिये नहीं दिया जा सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---विलेज इंडस्ट्रीज के लिये तो जो हमारी सामुदायिक विकास योजनायें हैं उनमें कुछ रकम निर्धारित है और उस रकम में से वह रुपया व्यय किया जाता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया जो काटेज इंडस्ट्रीज के लिये दिया जाता है वह किस बेसिस पर दिया जाता है, यानी कांट्रीब्यूटरी बेसिस है या अनुदान दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अनुदान भी दिया जा सकता है या वहां कोई कोआपरेटिव सोसाइटी या अन्य कोई व्यक्ति अगर कोई रोजगार चलाना चाहता है तो उसके लिये भी रुपया दिया जा सकता है या जो आपके जिले की नियोजन समिति है वह उसके लिये निर्धारित करती है कि किन किन चीजों में यह धन लगाया जाय।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में जो यह सरकारी सहायता प्राप्त घरेलू उद्योग-धंधे थे उनसे जो माल तैयार हुआ उसकी बिक्री का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक सामान का प्रश्न है, हमारे पास यह इत्तिला नहीं है कि वहां कितना सामान तैयार हुआ लेकिन अभी तक वहां ट्रेनिंग इन चीजों के बनाने की दी जा रही है। सामान कितना बना और कहां गया, इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभासचिव के समान ही विधायकों को चिकित्सा-सुविधायें देने की मांग

*२६---श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Ministers, Deputy Ministers तथा Parliamentary Secretaries के वास्ते लखनऊ में किन Medical facilities का प्रबन्ध है ?

श्री बनारसीदास---मंत्रियों, उपमंत्रियों एवं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को सरकारी आदेश दिनांक ९ जनवरी, सन् १९५० के अधीन वह सब चिकित्सकीय सुविधायें दी गई थीं जो कि सेक्रेटरी आफ स्टेट्स सर्विसेज चिकित्सा सम्बन्धी नियमों में दी हुई हैं। परन्तु ५ फरवरी, सन् १९५५ को उत्तर प्रदेश के एकाउन्टेन्ट जनरल ने यह एतराज किया कि जब तक उत्तर प्रदेश के मंत्रियों, उपमंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के ऐक्ट सन् ५२, में इसकी व्यवस्था न की जाय उक्त नियमों के अधीन उनको चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। इस एतराज के बाद किसी मंत्री या उपमंत्री को चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की भरपाई नहीं की गई है। मेडिकल मैनुअल के अनुच्छेद ९० के अधीन मंत्रियों को लखनऊ का सिविल सर्जन निःशुल्क देखता है।

*२७---श्री भगवान सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सदस्य, विधान मंडल के वास्ते लखनऊ में किन Medical facilities का प्रबन्ध है ?

श्री बनारसीदास---लखनऊ के नये काउन्सलर्स रेजीडेंस में एक पार्ट टाइम चिकित्सक का प्रबन्ध है जो कि रोगी सदस्यों व उनके परिवार के लोगों की चिकित्सा करता है। सदस्यों को वे दवाइयां जो सिविल डिसपेंसरी, हजरतगंज में उपलब्ध नहीं हैं, स्वयं बाजार से खरीदनी पड़ती हैं।

श्री भगवानसहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की तकलीफ फरमायेंगे कि अगर कोई विधायक बीमार हो जाय और उसको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़े, तो उस हालत में भर्ती करने के लिये सरकार के क्या नियम हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन सब नियमों पर सरकार विचार कर रही है और विचार करके नियमों में जिन परिवर्तनों के करने की आवश्यकता होगी उन नियमों में परिवर्तन किया जायगा। अब भी मौजूदा हालत में यदि कोई विधायक बीमार पड़ता है तो उसके लिये मेडिकल कालेज में या बलरामपुर अस्पताल में भर्ती होने की व्यवस्था कर दी जाती है।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की तकलीफ फरमायेंगे कि बलरामपुर अस्पताल में या मेडिकल कालेज में जो भर्ती का इन्तजाम किया जाता है, वह जनरल वार्ड में किया जाता है या कोई और विशेष सुविधा भी उनको दी जाती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां, जिस स्थान पर और जिस प्रकार से जगह मिलती है उसमें इन्तजाम कर दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी महोदय भी जब बीमार पड़े तो उनको भी और मरीजों के साथ रखा गया क्योंकि वहां पर जगह खाली नहीं थी और कभी-कभी माननीय मेम्बरों को भी ऐसी हालत से गुजरना पड़ा है। जब कभी प्राइवेट वार्ड खाली होते हैं उनमें रखने का प्रबन्ध हो जाता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि हमारे मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को सिविल सर्जन निःशुल्क देख सकता है और हमारे लेजिस्लेचर के जो मेम्बर हैं उनको निःशुल्क जब वह लखनऊ में ड्यूटी पर रहते हैं, वह नहीं देखता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरा ख्याल है कि जब-जब ऐसे अवसर आये हैं तो सिविल सर्जन या एडीशनल सिविल सर्जन मेम्बरों को देखने आये हैं और उनको निःशुल्क ही देखा है?

श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार इस बात की आवश्यकता को देखते हुये कि विधान मंडल के सदस्य विभिन्न स्थानों में रहते हैं, अटेंडिंग फिजिशियन की संख्या बढ़ायेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी बताया कि उन सारे नियमों पर अभी सरकार विचार कर रही है और सदस्यों से सलाह लेकर और विचार करके उनमें जिस परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होगी उनमें परिवर्तन किया जायगा और वह सुविधा प्रदान की जायगी जो आपस में बातचीत करके निर्णय किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जितना रुपया मंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज पर खर्च हुआ और जिसके बारे में आडिटर ने आब्जेक्शन किया, वह उन सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूल कर लिया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वसूल करने का तो सवाल नहीं उठता है क्योंकि जो नियम लागू थे उनके तहत में उनका इलाज हुआ और किसी मंत्री या उपमंत्री ने कोई रिइम्बर्समेंट नहीं किया है। जो उनका इलाज हुआ वह बलरामपुर अस्पताल में डाक्टर ने किया जैसे कि और व्यक्तियों का होता है। यह अवश्य है कि मंत्री और उपमंत्री को यह सुविधा रहती है कि डाक्टर या सिविल सर्जन उनके घर देखने अवश्य चला आता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सुविधायें मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और सभासचिवों को दी जाती हैं, क्या वही सुविधायें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी दी जाती हैं?

श्री बनारसीदास—जी हां।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि विधायक निवास में इन डाक्टर साहेब के लिये कोई खास काम नहीं है इस बात पर गौर करने की कृपा करेंगे कि मौजूदा प्रबन्ध को खत्म कर दें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रबन्ध विधायकों के सुझाव पर और सलाह पर किया गया था। यदि वे समझते हैं कि डाक्टर की यहां आवश्यकता नहीं है, तो सरकार अवश्य इस बात पर विचार करने के लिये उद्यत होगी कि वहां डाक्टर को न रखा जाय।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी, मंत्री, उपमंत्री और सभासचिवों को जो सुविधायें मिलती हैं, वही सदस्यों को भी देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो बातें सरकार के विचार करने की हैं, जैसा मैंने अभी बताया सदस्यों से बातचीत करके सरकार उन पर निर्णय लेगी। मैं यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि मंत्री, उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तो होलटाइम के सर्वेन्ट हैं इस मानी में कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में वे अपना सारा समय लगावें। लेकिन किसी भी असेम्बली या काउन्सिल में जो सदस्य काम करते हैं, वे कानून की दृष्टि में होलटाइम सर्वेन्ट नहीं समझे जाते हैं। केन्द्रीय सरकार में भी उसके पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिये कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं है। ताहम जैसा मैंने बताया, मेम्बरों से सलाह करके सरकार उन तमाम बातों पर निर्णय लेगी जिनको माननीय सदस्य स्वयं तमाम बातों को समझ कर सरकार को बतावेंगे।

रेल के डिब्बे बनाने के कारखाने खोलने के लिये प्रदेशीय सरकार का केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार

*२८—श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार से रेल के यात्री डिब्बे, माल गाड़ी के डिब्बे आदि अन्य सामग्रियों को बनाने की लिये कारखाने खोलने की स्वीकृति के लिये पत्र-व्यवहार किया है ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या माननीय नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कारखाने को खोलने के लिये भारत सरकार से कब से पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

श्री बनारसीदास—काफी समय से है और अब भी चल रहा है और विशेषकर इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये कारखाने किन किन स्थानों पर खुलेंगे ?

श्री बनारसीदास—यह पता नहीं है कि कहां-कहां खोले जावेंगे। केंद्रीय सरकार ने एक उपसमिति इस काम के लिये बनाई थी जिसे सिफारिशें दी गई हैं और उन्होंने लिखा है कि बरेली में इंडियन बाबिन कम्पनी और हमारे सिंचाई विभाग को बरेली, रुड़की और लखनऊ में वर्कशापों में भी फैक्ट्रीज खुल सकती हैं और काम हो सकता है। इसके अलावा हमारे प्रदेश के कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने लिखा है कि उनको भी इजाजत दी जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी सरकार की ओर से होने वाली उन तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे जिनके द्वारा उन्होंने केंद्रीय सरकार से अपने सुझाव की मान्यता के लिये बात पेश की है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो अभी बतला दिया गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री बतलावेंगे कि केंद्रीय सरकार ने उनके इस प्रस्ताव पर अभी क्या निर्णय लिया है ?

श्री बनारसीदास—अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और न अभी तक उन्होंने इसकी कोई घोषणा ही की है कि कहां-कहां इस प्रकार के कारखाने खोलेंगे ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—कोचेज के कारखाने बनाने की जगहों में क्या लगड़ी और घोसी भी शामिल किये जा सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी उन प्राइवेट सैक्टर वालों के नाम और पते बताने की कृपा करेंगे कि जिन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि उनके यहां इस प्रकार के कारखाने खुलें ?

श्री बनारसीदास—इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ऐंड फाउन्डर्स, हरदोई, कंसल कम्पनी, कानपुर, जन स्टील रोलिंग मिल्स, कानपुर, राधेलाल स्टील रोलिंग मिल्स, कानपुर । जहां तक इन फर्मों का सवाल है, अभी तक उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है । इसके अलावा मेसर्स जे० के० आयरन ऐन्ड स्टील कम्पनी, मोतीलाल वर्मा ऐण्ड कम्पनी भी चाहते हैं कि रेलवे के वैगन बनाने के कारखाने लगावें । इन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया को डेवलपमेंट रेगूलेशन ऐक्ट, १९५१ के मातहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं ।

*२९-३०—श्री भगवानसहाय—[स्थान तरित किये गये ।]

मथुरा जिले के लिये कोयला, टीन तथा सीमेन्ट का कोटा

*३१—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४ में मथुरा जिले को कोयला, टीन तथा सीमेंट का कितना कोटा दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मथुरा जिले को १९५३ और ५४ में कोयला, टीन तथा सीमेंट की प्राप्ति के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

१—कोयला	..	३५८६ टन
२—लोहा तथा इस्पात (टीन की चद्दर)		५९५ टन
३—सीमेंट	..	६७१० टन

श्री रामहेत सिंह—माननीय मंत्री कृपा कर के बतलावेंगे कि मथुरा जिले में ५३-५४ से जो सीमेंट की कमी अब तक मौजूद है उसका क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सीमेंट की कमी की वजह से वहां भी कमी हुई है ।

श्री रामहेत सिंह—क्या सीमेंट लोहे का कोटा आबादी व आवश्यकता को देखते हुये तय किया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक सीमेंट के कोटे का विषय है वह तो प्रदेश को भी उसकी आबादी के अनुपात से नहीं मिलता है । हमारी मेटीरियल रिसोर्सेज कमेटी कोटे के निर्माण पर विचार करती है और उसमें हमारे सारे विभागों के अधिकारी और सेक्रेटरीज बैठते हैं और वह आवश्यकता और योजनाओं को देखते हुये कोटा इत्यादि के निर्णय पर अपने फैसले लेते हैं । उसी के अनुसार कोटे वितरित होते हैं और कभी-कभी उसके निर्णय के अनुसार केंद्रीय सरकार से कोटा न आने पर उसके द्वारा निर्धारित मात्रा में कोटा नहीं पहुंच पाता है ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार प्रांत को किस आधार पर कोटा निर्धारित करती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन्होंने कुछ आधार तो बताया नहीं है। वे एडहाक कोटा निर्धारित करते हैं। हमारा अवश्य यह आग्रह और प्रार्थना रहती है कि हमारे प्रदेश की आवश्यकता और आबादी को देखते हुए हमारा कोटा और अधिक बढ़ाया जाय।

*३२-३४—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—[स्थगित किये गये।]

*३५-३६—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—[स्थानान्तरित किये गये।]

गाजीपुर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के संबंध में पूछताछ

*३७—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के टेक्निकल इन्स्टीट्यूट में क्या-क्या कार्य होता है?

श्री बनारसीदास—इस इंस्टीट्यूट में निम्नलिखित ट्रेड्स (Trades) में शिक्षा दी जाती है:

१—मिलराइट
२—मेशीनिस्ट
३—मोल्डिंग
४—इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर
५—वेल्डिंग
६—ब्लैकस्मिथी
७—वायरमैन

*३८—श्री कमलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस प्रकार की कितनी मशीनें उपयुक्त इन्स्टीट्यूट में हैं और कितनी चालू हैं?

श्री बनारसी दास—इस इंस्टीट्यूट में कुल ४५ मशीनें हैं जिनमें से ३९ चालू हैं।

*३९—श्री कमलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट में इस वक्त कितने शिक्षक हैं?

श्री बनारसीदास—प्रिंसिपल को मिला कर कुल ९ शिक्षक हैं।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस इंस्टीट्यूट के छात्रों के जरिये बाल्टी और लालटेन आदि लोहे का अच्छा सामान बनाया जाता है?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह सही है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार इस सामान को बाजार में बेंचने का प्रबन्ध करेगी?

श्री बनारसीदास—जो सामान बनता है, उसको बेंचने की व्यवस्था भी की जायगी।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि ६ मशीनें जो वहां बेकार पड़ी हुई हैं, उनका कारण क्या है?

श्री बनारसीदास—इन मशीनों में से ३ मशीनें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट टेकनीकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ में सरप्लस थीं। यह मशीनें काफी पुरानी हैं और ठीक अवस्था में नहीं हैं इसलिये उनकी मरम्मत हो रही है। बाकी तीन मशीनें टाइप कास्टिंग की हैं। जब उनकी फाउन्डेशन तैयार हो जायगी तो वह फिट कर दी जायेंगी।

नोट—तारांकित प्रश्न ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं कि जो लड़के इन इंस्टीट्यूट्स से पढ़ कर निकलते हैं वे कहीं कारबार पर लग जाते हैं ?

श्री बनारसी दास—यह इंस्टीट्यूट ज्यादा पुराना नहीं है। जहां तक टेक्नीकल विद्यार्थियों का सवाल है सरकार के पास उनकी सूचना नहीं है कि वे बेरोजगार हों बल्कि उनकी काफी मांग है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इस टेकनिकल इंस्टीट्यूट में शिक्षार्थियों की संख्या निश्चित है ? यदि हां, तो कितने शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—इस वक्त यह तो मालूम नहीं है कि कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं लेकिन प्रत्येक ट्रेड में उनकी संख्या निर्धारित रहती है। करीब-करीब १०-१२ प्रत्येक में होते हैं।

*४०—श्री शिवराजसिंह यादव—[स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में छोटी गंडक पर नदावर घाट का कथित पुल

*४१—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सलेमपुर, देवरिया में नदावर घाट पर छोटी गंडक में कोई पुल सलेमपुर विकास विभाग की तरफ से बना था जो बाढ़ में बह गया है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च हुआ था और फिर दुबारा बनाने में कितना खर्च होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। सलेमपुर विकास विभाग की तरफ से कोई पुल नहीं बना था।

प्रश्न का दूसरा हिस्सा नहीं उठता।

सलेमपुर तहसील के कार्यालय के सामने नाली का निर्माण

*४२—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या यह सत्य है कि सलेमपुर तहसील के कार्यालय के सामने से एक नाली एक फरलांग लम्बी बनाई गई जो दूसरे दिन ही बह गई ? यदि हां, तो वह किस विभाग के रुपये से बनी और उस पर कितना खर्चा हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। नाली जगह-जगह पर टूट गई है। यह कार्य गांव सभा, इचौना बाजार के द्वारा हो रहा है। रुपया कार्य समाप्त होने पर दिया जायगा।

लखनऊ का आयुर्वेदिक कालेज

*४३—श्री बलवन्तसिंह—क्या यह सही है कि सरकार आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को बन्द करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, यह प्रश्न नहीं उठता।

*४४-४५—श्री चिरंजीलाल यादव (जिला एटा)—[स्थगित किये गये।]

ब्लाक डेवलपमेण्ट अफसरों को दौरे के लिये सुविधायें

*४६—श्री रामस्वरूप गुप्त—(जिला कानपुर) क्या सरकार Block Development Officer को कोई ऐसी सवारी साधन अथवा भत्ता देने पर विचार करेगी कि जिससे प्रत्येक गांव में पहुंचा जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों के लिये सवारी तथा भत्ता दोनों का प्रबन्ध कर दिया गया है।

एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक औषधालयों पर व्यय

*४७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एलोपैथिक औषधालयों तथा आयुर्वेदिक औषधालयों पर औसतन सरकार प्रति वर्ष कितने रुपये दवा पर व्यय करती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सम्भवतः सदस्य महोदय देहाती क्षेत्रों के एलोपैथिक व आयुर्वेदिक औषधालयों के दवाओं का खर्च जानना चाहते हैं। वह इस प्रकार हैं :

१—एलोपैथिक अस्पताल (प्रति अस्पताल पर) पचास बड़े स्थानों के अस्पतालों पर ३,५०० रु० वार्षिक बाकी ज्यादातर में २,५०० रु० ।

२—आयुर्वेदिक औषधालय (प्रति औषधालय पर) ५२ बड़े-बड़े औषधालयों में ७८६ रु० तथा अन्य औषधालयों पर ५३६ रु० ।

बस्ती जिले के बाढ़ क्षेत्रों में चालू किये गये उद्योग-धंधे

*४८—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बाढ़ क्षेत्रों में कौन-कौन सा उद्योग चालू करने के लिये आदेश दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बस्ती जिले के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में खादी, गुड़, चमड़ा, बुनाई आदि के शिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। सरकार ने राज्य के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में खादी केंद्र खोलने तथा ३०,००० चर्खे मुफ्त बांटने के लिये आदेश दिये हैं। इन केंद्रों में से सात खादी केंद्र बस्ती जिले में खुल चुके हैं। उपरोक्त चरखों में से कुछ चर्खे बस्ती जिले में भी बांटे जायेंगे।

*४९-५१—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—[स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले में उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये जांच की आवश्यकता

*५२—श्री रामचन्द विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में छोटे और बड़े उद्योग धंधे चालू किये जाने के विषय में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

*५३-५४—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित) [स्थगित किये गये।]

विधूना तहसील, जिला इटावा में जनाने अस्पताल की आवश्यकता

*५५—श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने जनाने अस्पताल सरकारी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला इटावा में इस समय तीन सरकारी महिला अस्पताल हैं।

*५६—श्री गजेन्द्रसिंह—क्या विधूना तहसील (इटावा) में सरकार कोई जनाना अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*५७-५८—श्री बलवन्तसिंह—[स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स द्वारा गबन

*५९—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार को विदित है कि जिला जालौन के एक डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स ने लगभग ७,००० रुपये का गबन किया, जो रकम जिला नियोजन कमेटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को सहायतार्थ दी गई थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उनको ८,८५० रुपये की धनराशि जिला नियोजन कमेटी द्वारा दी गई थी। इस बात की जांच की जा रही है कि इस रकम में से कितने का गबन हुआ।

*६०—राजा वीरेन्द्रशाह—यदि यह सही है, तो क्या सरकार विवरण सहित बतायेगी कि किस स्कूल को कितना रुपया जिला नियोजन कमेटी द्वारा मंजूर हुआ और कितना उनको मिला?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला नियोजन कमेटी द्वारा जो रुपया मंजूर हुआ उसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है। किस स्कूल को कितना मिला इस की जांच की जा रही है किन्तु स्थानीय जांच से जो स्थिति पाई जाती है उसकी भी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६६–३६७ पर)

*६१—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिन डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स ने यह गबन किया, वह पाकिस्तान चले गये? यदि हां, तो उन्हें पाकिस्तान जाने की क्यों आज्ञा मिली?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलाधीश जालौन, ने पाकिस्तान जाने की आज्ञा नहीं दी। यह आज्ञा किसने दी, इस बात की जांच की जा रही है।

*६२-६३—श्री महीलाल—[स्थगित किये गये।]

यात्री-पर्यटन योजना पर विचार

*६४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के पर्वतीय भागों, तीर्थस्थानों एवं ऐतिहासिक स्थलों व नगरों में यात्री पर्यटन (टूरिस्ट ट्रैफिक) बढ़ाने के सम्बन्ध में वह क्या योजना कार्यान्वित कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—योजना सरकार के विचाराधीन है।

अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल जिलों के लिये पर्वतीय ऊन योजना

*६५—श्री जोरावर वर्मा—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल के पर्वतीय जिलों के लिये उद्योग सम्बन्धी कोई योजना चालू है? यदि हां, तो क्या?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(अ) जी हां।

(ब) पर्वतीय ऊन योजना।

*६६—श्री जोरावर वर्मा—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस योजना के सम्बन्ध में कितने स्थान किस-किस वेतन के निर्माण किये गये हैं और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की क्या क्या योग्यतायें हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस योजना के सम्बन्ध में कुल १९० स्थान निर्माण किये गये हैं जिनका वेतन-क्रम संलग्न तालिका में दिया हुआ है। उनमें नियुक्त

व्यक्तियों की योग्यतायें भिन्न-भिन्न हैं जिनको माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६८ पर)

टेक्निकल स्थानों पर नान-टेक्निशियनों की कथित नियुक्ति

*६७—श्री जोरावर वर्मा—क्या किन्हीं टेक्निकल स्थानों के लिये बिना टेक्निकल योग्यता वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

हमीरपुर जिले में अम्बर चरखा योजना चालू करने का विचार

*६८—श्री श्रीपतिसहाय (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला हमीरपुर में राठ खादी उद्योग का प्रसिद्ध उत्पत्ति केन्द्र है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*६९—श्री श्रीपतिसहाय—क्या सरकार राठ, जिला हमीरपुर के ग्रामीण उद्योग विकास के लिये अम्बर चरखा वितरित करने की योजना पर विचार कर रही है जैसा कि मगरौठ में गांधी निधि द्वारा दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अम्बर चर्खा योजना फिलहाल अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के विचाराधीन है। योजना बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही कार्यान्वित की जा सकेगी।

*७०—श्री श्रीपतिसहाय—क्या सरकार राठ में अम्बर चरखा की कताई की ट्रेनिंग बुनकरों के बच्चों को देने का विचार रखती है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(अ) जी हां।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

आयल तथा स्टीम इंजिन से चलने वाले दाल के कारखाने

*७१—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दालों (अरहर, उर्द, मूंग, मसूर, कसारी) के बनाये जाने के कितने कारखाने ऐसे हैं जो बिजली, आयल इंजन तथा स्टीम इंजन से चलते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य में बिजली, आयल इंजन तथा स्टीम इंजन से चलने वाले इस प्रकार के ५६ कारखाने रजिस्टर्ड हैं। बिना रजिस्ट्री शुदा कारखानों की संख्या ज्ञात नहीं है।

*७२—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों (पुरुष और स्त्री) की संख्या कितनी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपरोक्त ५६ रजिस्टर्ड कारखानों में ८६९ मजदूर काम करते हैं। इनमें से स्त्री और पुरुषों की अलग-अलग संख्या ज्ञात नहीं है। बिना रजिस्ट्रीशुदा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की भी संख्या ज्ञात नहीं है।

गोंडा जिले के उत्तर राप्ती भाग में ऊनी उद्योगों को बढ़ाने का विचार

*७३---श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि गोंडा जिले के उत्तर राप्ती भाग में ऊनी कालीन, कम्बल तथा चमड़े का गृह उद्योग और उतरौला में ताड़ के पंखे का उद्योग खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गोंडा जिले के उत्तर राप्ती भाग में ऊनी कालीन तथा कम्बलों के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार वहां कम्बल बुनकरों की सहकारी समिति बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस क्षेत्र में चमड़े के उद्योग अथवा अतरौला क्षेत्र में ताड़ के पंखे के उद्योग खोलने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*७४-७५---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---[स्थगित किये गये।]

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पी० एम० एस० श्रेणी में चुने गये डाक्टरों का वेतन

*७६---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३ में पब्लिक सर्विस कमीशन ने कितने डाक्टरों को पी० एम० एस० की श्रेणी दो में चुना था व इन लोगों का Probation period कब प्रारम्भ तथा समाप्त हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सन् १९५३ में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पी० एम० एस० (द्वितीय श्रेणी) के लिये १५५ डाक्टर चुने गये थे। स्वास्थ्य एवं चरित्र इत्यादि की आवश्यक जांच के पश्चात् १२७ डाक्टर जो कार्यभार ग्रहण करने के लिये आये, उन्हें परीक्षणकाल पर रखा गया। उनके परीक्षणकाल का प्रारम्भ व समाप्ति के दिनांक नत्थी किये विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६९-३७२ पर)

*७७---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या यह सत्य है कि उक्त डाक्टरों को अप्रैल, सन् १९५५ से वेतन नहीं मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका कारण बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश को सभी परीक्षणकाल पर नियुक्त डाक्टरों को ३१ अगस्त, १९५५ तक अन्तरिम वेतन पत्र देने का आदेश दिया गया था। सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिसमें किसी को वेतन न मिला हो।

पिनहट, जिला आगरा में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्वीकृति

*७८---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिनहट, तहसील बाह, जिला आगरा के लिये एक सरकारी अस्पताल स्वीकृत है ? यदि हां, तो वह कब तक बनने वाला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पिनहट में एक एलोपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत है। भवन के उपलब्ध न होने के कारण इस साल न खुल सकेगा। नया भवन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन के डिप्लोमा की मान्यता

*७९---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन के डिप्लोमा को उसने अभी तक मान्यता प्रदान की है या नहीं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(अ) जी हां।

(ब) सन् १९५१ से।

*८०—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को विदित है कि इस संस्था से पास हुए विद्यार्थी डिप्लोमा को मान्यता न प्राप्त होने के कारण, सरकारी तथा अन्य नौकरियों से अलाहदा किये जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कुछ शिकायतें सरकार के पास आई हैं कि जिन विद्यार्थियों ने इस संस्था का डिप्लोमा १९५१ से पहले प्राप्त किया था उनको नौकरियों से अलहदा किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—[स्थगित किया गया।]

श्री अवधशरण शर्मा की हत्या से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री राजनारायण जी ने एक 'कामरोको' प्रस्ताव भेजा है, वह इस प्रकार है—

"गत १६ अक्टूबर को बाराबंकी जिला के अन्तर्गत गांव बद्दू में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा पूर्व नियोजित ग्राम सभा में पुलिस की उपस्थिति में जिस प्रकार दिन दहाड़े सर्वश्री अवधशरण वर्मा, एम० एल० ए० तथा सियाराम जी की नृशंस हत्या स्थानीय गुंडों द्वारा की गयी और बाद में जिस प्रकार अमानवीय ढंग पर मृतक शरीर को जलाया गया उससे सारे प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध हो गया है।

अतः सदन इस आवश्यक तथा जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

कुछ दूसरे शब्दों में माननीय तिवारी जी ने कल एक 'कामरोको' प्रस्ताव इसी के बारे में उपस्थित किया था और इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जो वाकयात हुये हैं उनके संबंध में निश्चित जानकारी हासिल कर वे सदन के सामने २–१ दिन में रखेंगे। इस लिये वाकयात के संबंध में अनिश्चिता को देखते हुये और वाकयात के संबंध में बहुत कुछ बातों की जानकारी हासिल करने के पहले कोई विवाद अनुपयुक्त होगा, इस कारण मैंने इसकी इजाजत नहीं दी थी। वही निश्चय आज भी लागू रहेगा और इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, एक निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि अनिश्चितता किस विषय की है ?

श्री अध्यक्ष—आप यह जानना चाहते हैं ? आपने इसमें लिखा है "पुलिस के वहां उपस्थित रहने पर" और दूसरे "जिस प्रकार के अमानवीय ढंग से मृतक शरीर को जलाया गया" इसकी कोई डिटेल्स नहीं आयी हैं यह भी आपने लिखा है "और सारे प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध हो गया है" इन सारी चीजों में कोई निश्चित बात नहीं है, दो तीन बातें इसमें दी गई हैं इसलिये मैंने कहा कि जब तक वाकये की पूरी तहकीकात गवर्नमेंट की तरफ से न हो जाय तब तक कोई निश्चित बात नहीं हो सकती, यह एकतरफा बात हो जायगी।

श्री राजनारायण—जो मेरी जानकारी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं।

श्री अध्यक्ष—जो अधूरी तथा एकतरफा जानकारी है वह मैं नहीं चाहता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक बात मैं आपके द्वारा निवेदन कर दूं कि २१ तारीख को यह सदन उठ रहा है और फिर एक महीने या दो महीने बाद बैठे, तो मैं आपके द्वारा सरकार को जरूर बतला देना चाहता हूं कि प्रान्त में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि शायद सदन जब फिर मिले तब तक कुछ और एम० एल० ए० की भी यही हालत हो। तो मैं चाहता हूं कि जब तक यह सदन चल रहा है २१ तारीख के पहले ही सरकार कोशिश करे कि जिससे पूरी जानकारी मालूम हो जाय और उससे इस सदन को अवगत करे।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि कल मैं सदन के सामने जो पूरी सूचना होगी वह रख सकूंगा।

प्रश्न संख्या ५९-६० को स्थगित करने के लिये प्रार्थना

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मेरी प्रार्थना जो मेरे नाम ५९-६० नं० का सवाल है उसके मुताल्लिक यह कहना है कि उनका उत्तर मुझे ११ बजे आज मिला। तो श्रीमन्, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर सका कि आज सवाल न लिया जाय क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं कल ले लिया जाय। तो मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि इसकी अहमियत को देखते हुये इसे कल के लिये पोस्पोन करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---यह तो नहीं हो सकता। बात यह है कि उन प्रश्नों तक मैं पहुंच गया होता तो उसी समय यह सुझाव स्वीकार कर लेता लेकिन वहां तक पहुंचा ही नहीं तो मैं अब कुछ इस संबंध में नहीं कर सकता।

प्रलयंकारिणी वर्षा से हुई हानि की जानकारी के लिये प्रार्थना

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इसकी सूचना चाहता हूं और मेरा ख्याल है कि शायद सारा सदन इस सूचना को जानने की कोशिश करेगा कि जो पिछले सप्ताह में प्रलयंकारिणी वर्षा हुई है और उससे दर्जनों आदमियों के मरने की खबर मिली है तथा लाखों चाहे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति के हानि होने के सूचना मिली है उसकी प्रमाणिक जो कुछ भी सूचना सरकार को मिली हो तो मेहरबानी करके उसे हम लोगों को दे दी जाय तो मैं समझता हूं कि एक प्रमाणिक सूत्र से यह खबर मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष---(मुख्य मंत्री से) मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी आप कल दे देंगे।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कोशिश करूंगा और जो कुछ भी सूचना कल तक मौजूद होगी वह सदन को दे दी जायगी।

प्रश्नों के उत्तरों पर सम्बद्ध मन्त्री के हस्ताक्षर न होने पर आपत्ति

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मेरे प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया है उस पर कोई दस्तखत नहीं है.....।

श्री अध्यक्ष---प्रश्नों का समय तो समाप्त हो चुका है।

श्री शिवनारायण---श्रीमन्, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब इस पर दस्तखत नहीं है तो कोई भी आदमी छाप कर दे दे और कह सकता है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर है, इस तरह से कैसे पता लग सकता है कि असली जवाब कौन है.....।

श्री अध्यक्ष---मैंने कल निर्णय दे दिया था कि दस्तखत होने चाहिये।

श्री शिवनारायण---लेकिन, श्रीमन्, आज भी दस्तखत नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मंत्रिगण इस बात को सुन लेंगे और आइन्दा इसका खयाल रखेंगे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विवाद (क्रमागत)

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, कल अपने भाषण के आरम्भ में ही मित्र गेंदासिंह ने प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में भाषण देते समय शब्द "शेपलेस" का प्रयोग किया था। वैसे तो यह शब्द कुछ असंगत सा प्रतीत हुआ किन्तु माननीय गेंदासिंह सरीखे ठंडे दिमाग के एक व्यक्ति और सदस्य के मुख से ऐसे शब्द का निकलना उसको कुछ महत्व देता है और मैं समझता हूं कि उसका अवश्यमेव कुछ कारण रहा होगा जिसके जोर से उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया।

जहां तक कि योजना में प्रगति के संबंध में कुछ विचार प्रकट होने का प्रश्न है या जहां तक यह प्रश्न है कि आया, माननीय गेंदासिंह के विचार या उनके दल के विचार इन योजनाओं में स्थान पाते हैं या नहीं, यह संभव हो सकता है कि वह स्थान उन में न पाते हों, किन्तु मैं यह भी समझता हूं कि केवल इतने ही कारण से मित्र गेंदासिंह इन योजनाओं को "शेपलेस" न कहते। अध्यक्ष महोदय, आखिर फिर यह भी सोचना पड़ेगा कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में १६६ करोड़ से अधिक व्यय कर के काम किया जा रहा है और किया जा चुका है और जब कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३६७ करोड़ रुपया से अधिक रुपया खर्च करने का इरादा रखती है तो फिर आखिर वह योजना शेपलेस कैसे रहेगी, उसका कुछ न कुछ आकार तो अवश्य ही चित्रित हो जायगा और विशेषकर मैं समझता हूं माननीय गेंदासिंह जी का मतभेद इसमें रहे कि जो चित्र उनके सामने प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा आया वह उसको वास्तव में एक उचित या उत्तम प्रगति का चित्र न समझें और न समझते हैं। यह मतभेद का प्रश्न है और उसमें बहुत हद तक मैं भी अपने मित्र गेंदासिंह जी के साथ हूं और मेरा भी व्यक्तिगत विचार यही है और दूसरे भी बहुत से लोगों का होगा कि इन दोनों योजनाओं में बहुत-सी कमियां रह गई हैं लेकिन जनतंत्र राज्य प्रणाली की एक आवश्यक बात है कि बहुमत की जो राय हो वह सदैव ऊपर रहे इसलिये मुझे, माननीय गेंदा सिंह को या किसी भी विरोधी दल के सदस्य को यह कहना उचित न होगा कि क्योंकि हमारे विचार इन योजनाओं में स्थान नहीं पाते इसलिये योजना 'शेपलेस' है।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि प्रगति से सरकार का क्या अर्थ है? प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में जो पुस्तिका दी गई है, यदि सरकार का कहना यह है कि वास्तव में विभिन्न दिशाओं में सफलता प्राप्त करना है, प्रगति करना है तो प्रश्न यह होता है कि इन योजनाओं की कार्यशीलता द्वारा किये गये महान् परिवर्तन में कोई प्रगति का स्थान पाया जाता है या यह प्रश्न निकल सकता है कि क्या भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति या आर्थिक स्थिति में सुधार पाया जाता है, यही प्रगति के एकमात्र लक्ष्य हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति में की गई चेष्टा और उस से जो परिणाम निकले और कर्त्तव्य को पूरा करने में जो कोशिश हुई उस पर भी बहस हो सकती है किन्तु मैं इतना अवश्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

कहूंगा कि यदि इन भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने की प्रगति की ओर चलना है और जैसा कि बताया गया है कि सन् ५०–५१ की बनिस्बत ५४–५५ में ९६ लाख टन के स्थान पर १ करोड़ ११ लाख टन उत्पादन हुआ, माननीय गेंदा सिंह इसको भी स्वीकार करते हैं कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं जिससे मैं निश्चित राय कायम कर पाऊं। किन्तु मैं यह विश्वास रखता हूं कि जो कुछ आंकड़े सदन के सामने आवेंगे वे झूठे नहीं होंगे इसलिये इन सब लक्ष्यों की जहां पूर्ति हुई है उसके लिये मैं शुरू में ही सरकार को निस्संकोच भाव से बधाई देता हूं। अगर वास्तव में लक्ष्यों की प्रगति हुई है चाहे वे लक्ष्य सही रूप में निर्धारित न हुये हों या गलत स्थानों पर निर्धारित हुये हों वह प्रश्न इस समय उठता नहीं है। जो भी सरकार ने उचित लक्ष्य समझे यदि उनकी पूर्ति प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई तो मैं समझता हूं कि वह उसके लिये बधाई की पात्र अवश्य है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे जो एक विशेष कठिनाई हो रही है वह यह है कि हालांकि मैं मानता हूं कि इन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हर एक योजना के संबंध में योजना को कार्यान्वित करते समय सफलतापूर्वक करने के लिये यह आवश्यक होता है कि लक्ष्य बनाकर उन लक्ष्यों की ओर प्रगति की जाय किन्तु मैं समझता हूं कि केवलमात्र चन्द लक्ष्यों की प्राप्ति में ही यह कहना कि हमारी पूरी प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल हुई मैं समझता हूं कि एक गलत विचार होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि काफी हद तक हमारी खाद्यान्न की समस्या हल हुई, यह भी मानने के लिये तैयार हूं कि जहां बिजली की कमी थी वहां बिजली देने का प्रबन्ध किया गया है और किया जा रहा है, सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करने की चेष्टा की जा रही है और इसी प्रकार हर एक विभाग में प्रगति अवश्यमेव की जा रही है मगर मेरी समझ में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह विभिन्न विभागीय प्रगति पारस्परिक सम्बन्ध रखे हैं। मेरी दृष्टि में बहुत कम पारस्परिक सम्बन्ध इन में है। इन सब को इकट्ठा करके हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में सब बातों में प्रगति हुई है लेकिन मैं विशेषकर उस प्रश्न को लेता हूं कि कुछ रूप से पूर्ण रूप से नहीं तो हमारी सरकार का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि मनुष्य और मनुष्य में पारस्परिक प्रेम की भावना बढ़ावे और इसी दृष्टि से मैं इस अवसर पर दोनों पंचवर्षीय योजनाओं को देखना चाहता हूं। १६७ करोड़ रु० खर्च करने के बाद क्या इन पांच सालों में मंत्री महोदय कह सकते हैं कि जो परिस्थिति आज प्रदेश में पाई जाती है क्या वह यह कह सकते हैं कि आज मनुष्य मनुष्य में प्रेमभाव, सद्भावना और सहानुभूति है? मैं एक बार यहां हाल ही में हुई बाराबंकी जिले की हत्या का उदाहरण पेश करता हूं। अधिक डिटेल्स में न जाकर मैं केवल मात्र यही कहूंगा कि इसी प्रकार की घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि चाहे और जिस दिशा में भी यह हमारी योजनायें सफल रही हों भले ही खाने के लिये पहले से ही हमें ज्यादा मिले और भले ही आज गांव गांव बिजली पाने की संभावना हो फिर भी मैं समझता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है कि जनता के बीच में एक संतोष की भावना और पारस्परिक प्रेम की भावना उत्पन्न कर उसमें सरकार सफल न हो पाई है। कुछ दिन पहले अध्यक्ष महोदय मुझे इलाहाबाद जाने का अवसर हुआ और वहां इलाहाबाद स्टेशन पर दो स्थानों में एक नोटिस लगा हुआ था और उसमें यह चेतावनी दी गई थी कि अनजान के हाथ से कुछ भोजन, पान या सिगरेट न लें, कहीं कुछ विष न मिलाया गया हो। मैं पूछता हूं क्या इन योजनाओं का सर्वप्रथम कर्त्तव्य यह नहीं होना चाहिये कि ऐसी संभावनाओं को दूर किया जाय। बांध बांधने से और बिजली देने से और नये नये स्कूल खोलने से, मैं पूछता हूं क्या लाभ, जबकि अन्त में वही एक बात हमारे सामने बारम्बार आती है।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में इतना कह कर मैं अब सरकार का विशेषकर अपने नियोजन मंत्री का ध्यान दोनों प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की उन त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि मैं समझ गया हूं। पहली बात जो मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने

रखना चाहता हूं वह यह है कि यह जितना पैसा खर्च किया जा रहा है और जो एसेट्स इस पैसे से पैदा किये जा रहे हैं वे चाहे सड़कों के रूप में हों, चाहे बांध के रूप में हों चाहे किसी भी रूप में हों उन एसेट्स की मेनटिनेंस के लिये दुख की बात है कोई भी प्रबन्ध नहीं हो रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में,मैं अथारिटी के साथ अपने जिले के संबंध में कह सकता हूं, कि मेरे जिले में काफी सड़कें बनीं और दो सड़कें विशेषकर श्रमदान द्वारा बनीं और उन सड़कों पर सौभाग्य की बात थी कि माननीय मुख्य मंत्री का भी जाना हुआ लेकिन आज उन सड़कों की गति जो है वह एक शोकनीय परिस्थिति में है। अध्यक्ष महोदय, लगभग सढ़े तीन लाख रुपया खर्च हुआ और इस प्रकार और भी स्थानों में और चीजों में भी पैसा खर्च हुआ। किन्तु यदि आज उन सड़कों को चालू करने की इच्छा हो, मैं समझता हूं मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूं, किन्तु कमसे कम इतना ही पैसा एक बार फिर व्यय करना पड़ेगा। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैं समझता हूं कि तीन हजार या पांच हजार नये प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था कर रक्खी है मैं उनसें पूछना चाहता हूं कि उन स्कूलों के बारे में क्या होगा जो कि बन चुके हैं, जो काफी वर्ष पहले बने थे और अब खंडर की हालत में पहुंच रहे हैं। मेनटिनेंस या रिपेयर्स के बारे में सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। एक प्रकार का मैं कुछ डेस्परेट सा एटीट्यूड देखता हूं जो कुछ हो सके कर दिया जाय किसी को प्रभावित किसी दृष्टिकोण से करने के लिये, मैं समझता हूं कि सरकार का ऐसा रुख होना या रहना उचित नहीं जो चीज एक बार उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें सरकारी या जनता का पैसा खर्च कर दिया गया है उसकी मेनटिनेंस के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है। इस दिशा में जहां तक मैं देख पाया हूं आंकड़ों में कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम उत्पन्न करने का क्या तरीका है उसके संबंध में यह उत्तर मिल सकता है कि जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट सरकार चला रही है वे बहुत हद तक उनका लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि ब्लाक एरियाज के जो लोग हों वे आपस में मिल कर अपनी कठिनाइयां एक साथ कंधे से कंधा मिला कर दूर करने की कोशिश करें। जहां तक कि यह उद्देश्य इन प्राजेक्ट्स का है उसके संबंध में उसके विरोध में, मैं कुछ नहीं कह सकता? किन्तु अध्यक्ष महोदय दुख की बात यह है कि इस उद्देश्य से यह कम्युनिटी प्राजेक्ट्स अब कुछ बदल गये हैं। चाहे जानबूझ कर के बदले हों किन्तु यह स्वाभाविक है कि जहां कुछ फिजिकल टार्गेट्स रखे जायं किसी कम्युनिटी प्राजेक्ट ब्लाक में या एरिया में यह कहा जाय कि इस दौरान में इतनी चीजें बननी हैं तो जो मारल या स्प्रिचुअल बातें हैं उनके ऊपर ध्यान कम रहता है। शुरू में चेष्टा यही होती है कि यदि कहीं सड़क बनानी हो तो जहां तक हो सके सहकारिता के सिद्धांतों को अपना कर वहां की जानता को साथ ले कर उस जनता द्वारा ही वह काम किया जाय। किन्तु जब कि वर्ष प्रति वर्ष एक रिपोर्ट आनी है और हर एक जिले की प्रगति की रिपोर्ट आनी है तो उस समय जिले का अधिकारी न थियरिटिकल सिद्धांतों को भूल जाता है। आखिर उसको भी कागजों में अच्छा सर्टिफिकेट लेना है और वह निर्भर है प्राग्रेस पर। अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह बता रहा था कि यह एक मुख्य दिक्कत है जिसके कारण कम्युनिटी प्राजेक्ट्स का जो शुरू में सिद्धांत था, "एक ऐसी चीज है कि वहां के लोगों को एक इंसेंटिव दे कि आपस में मिल कर आपस की कठिनाइयों को सब साथ मिल कर दूर करे वह अब इन कम्युनिटी प्राजेक्ट में नहीं है। मैं अपने ही जिले से जनरलाइ-जेशन कर सकता हूं और आशा करता हूं कि और जिलों में यह बात न पायी जाती हो। किन्तु मेरे जिले में मैं कह सकता है हालांकि हमारे यहां एक ही कम्युनिटी प्राजेक्ट है, किन्तु वहां यह भावना नहीं पायी जाती कि हमको मिल कर आपस में काम करना है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वास्तव में यही चाहिये था जो कि सरकार ने स्वीकार करके इस को करवाने के लिये अवसर दिया है। यह भावना वहां नहीं पायी जाती। भावना यह है कि हमारे एक स्थान में एक पुल की कमी थी, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये एक सड़क की कमी थी सरकार ने हमारी इस कमी को महसूस किया, सरकार इसको दूर करने के लिये कदम उठा रही है। होना तो

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

यह चाहिये था कि कम से कम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीपुल्स प्लान बने। मित्र गेंदासिंह जी ने भी इस संबंध में कहा और मैं उनसे सहमत हूं। किन्हीं कारणों से चाहे शुरू में यह भले ही रहा हो लेकिन यह अब पीपुल्स प्लान नहीं रहा। एक बार फिर सरकार और मंत्री महोदय की चेष्टा से यह फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स के द्वारा तैयार किया और उनके द्वारा इसमें प्रगति लाने की जो चेष्टा की जायगी यह उनका प्लान जो है कि जनता स्वीकार करने के लिये तैयार है जनता में इस के लिये उतना कोई उत्साह नहीं। एक दृष्टि से अवश्य उत्साह है आखिर लाभ उनका होगा, लेकिन यह कहना ठीक न होगा कि जनता की राय एक विषय में ली गयी या यह कहना ठीक न होगा कि जो कुछ भी किया जायगा वह जनता की इच्छा को प्राथमिकता दे कर ही निश्चय और निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हर एक विभाग के संबंध में कहना अवश्यक नहीं। काफी सदस्यगण बोलना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। इस भवन में कई बार पहले भी इस विषय पर मुझे अपने विचार प्रगट करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आज एक बार वही विचार प्रगट करूंगा कि यदि सरकार जिस वर्तमान ढील के साथ इस सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ा रही है उसी ढील को कायम रखती है तो इससे अच्छा यह होगा कि यह सहकारिता का जो विभाग है उसको बन्द कर दिया जाय। यहां भवन में भाषण देते समय किसी स्थान पर उद्घाटन करते समय वेलफेयर स्टेट के सिद्धान्त के बारे में भाषण देते समय हमेशा सहकारिता की प्रशंसा की जाती है, हमेशा यह कहा जाता है कि सहकारिता ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा वेस्टेड इंटररेस्ट्स का खात्मा किया जा सकता है और यह बात सही भी है कि यदि आज जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में लड़ाई है जिसका केन्द्रीय सरकार भी पूर्णतया सामना नहीं कर पायी यदि उसके किसी भविष्य के सम्बन्ध में उसका खात्मा करना है तो वह सहकारिता के ही द्वारा किया जा सकता है। मगर अध्यक्ष महोदय, इस समय सहकारिता के सम्बन्ध में जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि सरकार निश्चय रूप से यह न कह देती है कि जहां भी हो सके और जिस कार्य में भी सहकारिता या सहकारी संघ सामने आते हैं उनको सरकार आंख मूंद कर के उनका साथ देने के लिये तैयार नहीं, तब तक सहकारिता का आन्दोलन सफल नहीं होगा। पिछली बार मैंने बताया था कि कन्ट्रोल के जमाने में जो कन्ज्यूमर्स रिटेल शौप्स थीं वे बहुत सफलतापूर्वक चलीं। भाग्यवश अब कंट्रोल अनावश्यक चीज रही, साथ ही दुर्भाग्यवश सहकारिता का जो एक सफलतापूर्वक चलाने का जो एक साधन था वह भी उनके हाथों से दूर हो गया। अब मैं फिर एक बार अपनी लाचारी प्रकट करता हूं कि मैं अपने ही जिले के उदाहरण से जनरेलाइज कर रहा हूं अब सहकारिता केवल नाममात्र के लिये हैं। मैं मानता हूं कि प्रति वर्ष नई-नई कोआपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर होती हैं मैं यह भी मानता हूं कि उनमें कुछ हद तक पूंजी, हालांकि काफी रकम नहीं, फिर भी पूंजी आती रहती है किन्तु यह कहना कि लोगों की दिलचस्पी इन संघों की ओर बढ़ गई है मैं समझता हूं यह एक गलत बात होगी। यह तो स्पष्ट ही कर दिया गया है कि दोनों योजनाओं में और विशेषकर अब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की जायगी उसमें सहकारिता को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से यह कहूंगा कि सरकार हर एक विषय को सहकारी संघों के हाथ में दे और जहां जहां नियोजन के कार्य हों जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज की खरीद की चीज हों या गल्ले का बंटवारा हो और इस प्रकार के जो भी कार्य हों वे एक नियमानुसार सहकारी संघों द्वारा ही किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं केवल मंत्री महोदय को संकेत के रूप में बता देना चाहता हूं कि उनके ध्यान में वह बात होगी जो कि हाल में हमारे जिले में बीती, जिस सम्बन्ध में कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इन्क्वायरी भी हुई। उसमें भी यही बात आयी है कि चन्द व्यक्ति स्वार्थ के कारण हो चाहे पुराने ठेकेदारी के कारण हो, उन्होंने हमारी

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को माल सप्लाई करने का एक प्रकार ठेका ले लिया था। उसको दूर करने का यही एक तरीका है। एक व्यक्ति से छीन कर दूसरे को दिया नहीं जा सकता किन्तु एक व्यक्ति से छीन कर सहकारी संघ को देने में कोई भी गलत बात न होगी।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में भी मैं मंत्री महोदय से कुछ कहना चाहूंगा और इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर तो आकर्षित कर ही लिया है जहां कि नये स्कूलों के बनाने का प्रबन्ध किया जा रहा है और पुराने स्कूलों की देखभाल के लिये कोई भी प्रबन्ध नहीं है। इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं में जो खर्चा होगा उसका ब्योरा दिया गया है चीजों का मेंटिनेंस सरकार का जो रेवेन्यु एकाउन्ट का ऐनुअल बजट होता है, उसमें देखना असम्भव होगा। मैं शिक्षा के सम्बन्ध में विशेषकर इसलिए बतलाता हूं कि यह अन्य विभागों में भी पाया जाता है मगर चूंकि शिक्षा के सम्बन्ध में २२ पेज पर जो यह दिया गया है कि ५,००० नयी प्रारम्भिक पाठशालाएं खोली जायंगी, तो इस सम्बन्ध में यह बात उत्पन्न होती है। जहां तक कि शिक्षा की नीति का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, जितना कम कहा जाय उतना ही अच्छा है। मैं मंत्री महोदय ने जो हमारे पास पुस्तकें भेजी हैं उनमें शिक्षा के सम्बन्ध में जो "चतुर्थ वर्ष की प्रगति" है जूनियर हाई स्कूलों के सम्बन्ध में कहते हैं कि "इन स्कूलों को ऐसे प्रभावशाली सामुदायिक स्कूलों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय ताकि शिक्षा छात्रों के दिमागों में जबरदस्ती ठूंस दिये जाने वाले नीरस एवं औपचारिक पाठों की वह श्रृंखला न होकर समाज के आर्थिक सिद्धान्तों तथा उनकी संस्कृति, परम्परा और भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप जीवनदायिनी सिद्ध हो।" अध्यक्ष महोदय, प्रगति का अर्थ परिवर्तन नहीं है और न ही परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन प्रगति की दिशा में हो सकता है। मंत्री महोदय ने जो परिवर्तन करने का इरादा किया, उसके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में मैं केवल कुछ न कहूंगा, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हालांकि उन्होंने छात्रों के ऊपर यह मेहरबानी की कि "जबरदस्ती ठूंस दिये जाने वाले नीरस पाठों" को अब हटा दिया, किन्तु साथ ही साथ मैं यह पूछूंगा कि क्या हमारे मंत्री महोदय इस प्रदेश में जो आज शिक्षा दी जाती है वास्तव में वे उससे सन्तुष्ट हैं? क्या आज जो सुपरफ़िश्यल एजूकेशन हमारे लड़के पाते हैं, क्या वही इस प्रदेश का और इस देश का भविष्य उन्हीं लड़कों के हाथ में रहेगा जो कि "बैंक आफ आल ट्रेड्स" के नाम से भी नहीं चल पायेंगे। हर एक विषय में थोड़ी-थोड़ी सी सुपर फिश्यल नालिज जो आज स्कूलों में दी जा रही है, मैं समझता हूं कि अगली पंचवर्षीय योजना में इसके सम्बन्ध में, इस नीति के सम्बन्ध में, कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। हमारे विश्वविद्यालयों में एक नया ढांचा-सा बदला जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी में दंगा-फसाद होकर शिक्षा ही नहीं दी जाती, न देने के लिए उचित वातावरण पाया जाता है। दूसरे विश्वविद्यालयों में जब चाहें हमारे वाइस चांसलर साहब वहां का करीकुलम बदल देते हैं। आखिर में पूछता हूं, अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा पाने के बाद विद्यार्थी यहीं इस प्रदेश में या देश में काम करेगा और यही एक लक्ष्य था कि उसके लिये भविष्य में देश सेवा करने की एक योजना बने। अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के ऊपर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ऐसी बातें इनमें से हो सकती हैं कि प्रादेशिक सरकार के हाथ में न हों, फिर भी प्रादशिक सरकार की जिम्मेदारी इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में नहीं छटती। अध्यक्ष महोदय, जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके लिए तो हम सब धन्यवाद देते हैं, किन्तु इतना हम अवश्य करना चाहेंगे कि यह भी लोगों में शिकायत है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय भी कुछ हद तक स्वीकार करेंगे कि जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना आउटपुट नहीं पाया जा रहा

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

है। १६६ करोड़ की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, यह भविष्य में पता लगेगा यदि लग सका किसी रूप से—कि क्या १६६ करोड़ की बराबरी के असेट्स की प्राप्ति हुई या नहीं। मैं तो फिर अपने ही जिले के सम्बन्ध में कहूंगा कि यह बात नहीं पायी जा रही है और वास्तव में पैसा इधर-उधर बहुत बह जाता है और जिस काम के लिये वह दिया जाता है उस काम में उसके आधे से कुछ ही ज्यादा मिलता होगा। तो इस ओर भी सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान देना चाहिये और इसका कुछ उपाय निकालना चाहिये। आखिर इतने पैसे की रोकथाम और निरीक्षण करना आवश्यक है। मैं यह जानता नहीं कि क्या आडिट और एकाउन्ट्स को अलग-अलग करने से इसमें कुछ आसानी पड़ेगी मगर इतना मैं जरूर जानता हूं कि जो एक से अधिक कंट्रोलिंग आफिसर्स पाये जाते हैं वह एक कारण है कि पैसे के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिये वह नहीं रहता। अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं उस विषय के सम्बन्ध में थोड़ा ही कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

फ़ाइनेन्सेज के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई और मंत्री महोदय से पूछा गया था कि पैसा कहां से आयेगा। यह तो हमारे मित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के दौरान में स्पष्ट ही कर दिया था कि हमें इस बात का फैसला करना है कि हमारी प्रगति क्या रहे। यदि हम धीमी गति से प्रगति करने के लिये तैयार हैं तो पैसे के लिये उतनी जल्दी और उसे इकट्ठा करने में उतनी कठिनाई न होगी। उस समय यह निश्चित हो ही चुका था कि प्रगति की जाय और जिस तेज रफ्तार से हो सके उस रफ्तार से होनी चाहिये। जब एक बार यह निश्चय हो चुका है चाहे हमारे पास साधन हों या न हों हमें प्रगति करनी ही है, जब यह निश्चित कर ही लिया कि कर्ज में डूब कर भी हम प्रगति करेंगे तो फिर इसके बाद और क्या उपाय है कि कर्ज में जो हम अभी डूबे हैं उससे अधिक और डूब कर भी पैसा इकट्ठा किया जायगा। जब कर्ज में और अधिक डूब कर भी पैसा इकट्ठा न हो सके तो यह और साधन रह जाता है कि टैक्स द्वारा इकट्ठा किया जाय। और यह भी वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि जनता को और त्याग के लिये तैयार रहना चाहिये। कहां तक और त्याग के लिये जनता तैयार हो सकेगी यह कर वसूली के समय ही पता लगेगा।

प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो फ़िजिकल टार्गेट्स सरकार ने बनाये हैं यदि वे प्राप्त हो जायं तो उनके लिये सरकार बधाई की पात्र अवश्य है। अगर साथ ही उस बड़े विषय को न छेड़ कर जो कि केन्द्रीय सरकार में चल रहा है कि आया प्रोफेसर मलोनाबिस का जो नया सिद्धान्त है वह सही है या गलत इतना मैं अवश्य कहूंगा कि फ़िजिकल प्लानिंग का यही दुष्परिणाम है कि एक तरफ़ तो उन मदों के ऊपर कंसेन्ट्रेशन रहेगा जिसके सम्बन्ध में टारगेट्स स्थापित कर लिये गये हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी थी और अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रीज को दी जा रही है। इसका यही एक परिणाम होगा कि कुछ हद तक एक अनबैलेन्सिंग एफेक्ट रहेगा। ओवरआल डेवलपमेंट यदि हो सके तो मैं समझता हूं कि वही सर्वोत्तम होता है और उसमें सब चीजों के ऊपर निगरानी रह सकती है। इतना कह कर मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया और उनसे यही आशा करूंगा कि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्र से अभी और लेने की चेष्टा करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिये इस पर १५ मिनट का समय निश्चित कर दिया जाय वैसे और लोग हैं जिनको आप उचित समझें ज्यादा समय दे दें और आम तौर से १५ मिनट का समय निश्चित कर दिया जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह अधिकार आप स्वतः अपने पास रखें और लोगों को आप समय स्वयं दे दें क्योंकि सम्भवतः इतने समय में यानी १५ मिनट में कोई ठीक तरह से इस विषय पर नहीं कह सकता है।

श्री अध्यक्ष---ऐसा करना मेरे लिये मुश्किल है। एक मैक्जीमम समय और मिनीमम समय फिक्स कर दें आप लोग तो मैं काम चला सकता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, परिपूर्णानन्द जी ने जो सुझाव रखा है हम उनके साथ हैं और मैं जरूर यह चाहता हूं और यह बड़ा विशद और व्यापक प्रश्न है और सरकार की ओर से भी लोग समुचित रूप में बातचीत करें और विरोधी पक्ष के लोग हैं वह और अन्य पार्टी के लोग किस तरह से अपने राष्ट्र और प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं और किस तरह से सही माने में विकास होगा।

श्री अध्यक्ष---१५ से २५ मिनट रख दिया जाय इसको आप ठीक समझते हैं ?

श्री राजनारायण---जी हां, हम तो आपको और अधिकार देना चाहते हैं। परिपूर्णानन्द जी बाहर से आये हैं और उनको कुछ मुल्कों की जानकारी है कि वह वहां किस तरह से उन्नति होती है।

श्री अध्यक्ष---वह तो मुझे अन्दाजा लग सकता है लेकिन क्या आप इस तरह का अधिकार देना चाहते हैं।

श्री राजनारायण---आप ४५ मिनट कर दें तो ठीक है।

राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि १५ से ३० मिनट हो।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, हाउस के मेम्बरों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम सिर्फ १५ मिनट के अन्दर लिमिट नहीं करना चाहते हैं। यदि आप चाहें तो किसी को १५ मिनट न सही १६ मिनट दे दें लेकिन अमूमन १५ मिनट रखा जाय।

श्री अध्यक्ष ---आप यह देख लें, जितने बोलने वाले हैं, मुझे अन्दाजा हो गया है क्योंकि मेरे पास नाम आ चुके हैं इसलिये मैं अधिक मारजिन नहीं रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि १५ मिनट और ३० मिनट के बीच में भाषण का समय रखने की कोशिश करूंगा। कुछ नियंत्रण तो होना ही चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्य का आरम्भ करने के लिये यहां पर आज श्रीगणेश करने के लिये बैठे हैं। मैं आपके द्वारा सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कुछ भी उसका स्वरूप था, जहां तक हमारी नियोजन सम्बन्धी जानकारी थी, जो हमारे उस वक्त के सम्भावित मापदन्ड और आंकड़े थे उन प्रश्नों के जिनका समन्वय करके हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूरा करने का प्रयास करने वाले थे जो कुछ हमने उस सम्बन्ध में सोचा और विचारा था, उससे यद्यपि हम समयानुकूल अपनी बात को बढाते रहे। अपने आधार पर पूर्ण होती नजर आ रही है।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

उसी अनुभव के आधार पर ,जानकारी के आधार पर अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिये यहां पर अपना समय लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि जो बुनियादी बात प्रदेश के लिये है वह यह है कि यद्यपि हमारे प्रदेश में प्लानिंग के जमाने को, नियोजन के जमाने को शुरू हुये आज चार साढ़े चार साल हो गये हैं लेकिन नियोजन और उसके पीछे जो विचार धारा है उसे शायद पूरी तरह हम नहीं अपना पाये। आवश्यकता उनकी है विचारों के क्षेत्र में, अतः हम अपने विचारों में समन्वय करने की कोशिश करें। मेरा मतलब यह नहीं है कि हम नियोजन का कार्य तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे प्रदेश के लोगों के विचार एक से न हो जायं लेकिन फिर भी यदि नियोजन जैसी प्रणाली को प्रजातंत्र में जीवित रहना है और प्रजातंत्र में उसको फलना-फूलना है और यदि इसका समन्वय प्रजातंत्र के साथ किया जाना है तो नियोजन के प्रश्न को दलगत राजनीतिक प्रश्नों से ऊपर हर प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले आदमी को रखना होगा।

अतः जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिये एकत्रित हुए हैं तो मैं अपने माननीय मित्रों से जो विरोधी पक्ष में भी बैठे हुए हैं, उनसे और जो हमारी सवा छः करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं उनसे भी, आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि नियोजन की प्रणाली दलगत राजनीति से ऊपर रख कर ही सम्भव और सफल होने वाली है। अतः इस प्रश्न को इसी स्वरूप में लिया जाय और इसी विचार को सामने रखते हुये मैं अपने विचारों को आपके सामने रखूंगा। यद्यपि मैं उस दल का एक सदस्य हूं कि जो दल आज नियोजन का कार्य करने में लगा हुआ है, जो दल आज सरकार का भार वहन कर रहा है, लेकिन इस कार्य में जो त्रुटियां मुझे दिखाई पड़ेंगी उनको मैं सरकार के सामने आपके द्वारा रखूंगा। साथ ही जिन-जिन बातों के लिये सरकार प्रशंसा की पात्र है उसकी प्रशंसा करूंगा और मैं सदन से आशा करता हूं कि वह मेरे इस उद्देश्य से सहमत होगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इसी परम्परा को सामने रख कर प्रजातंत्र में नियोजन सफल हो सकेगा।

श्रीमान सबसे बड़ा प्रश्न जो देश के सामने आता है नियोजन के संबंध में, वह यह देखने का है और उस प्रश्न को आज से कई साल पहले हमारे प्रदेश के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने सरकारी कर्मचारियों के साथ वार्तालाप करते हुए कहा था

"हम नियोजन फाइलों से करते हैं। फाइलों के बीच और उनके पीछे इन्सान होते हैं और इसलिये नियोजन की परंपरा को यदि बलवती बनाना है, यदि नियोजन को पूरे तौर से, सफलता से संभावित करना है तो हर उस आदमी को जो नियोजन के कार्य से संबद्ध है उसे याद रखना होगा कि उसका काम इंसानों के लिये है। वह इंसान फिजिकल पर्सन्स केवल मांस के लोथड़े नहीं, बल्कि उनके हृदय है, मन है और इसलिये हमें नियोजन को न केवल वाह्य क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, न केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाना होगा ,जिन शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये आज सारा देश सचेष्ट है और जिनसे आज देश के आर्थिक ढांचे को ऊपर उठाने की कोशिश हो रही है लेकिन इसके साथ ही साथ हमें मनुष्यों के मन, स्वभाव बुद्धि विवेचना आदि पर ध्यान रखते हुए इस योजन के कामों को इस रूप में कार्यान्वित करना होगा कि हम उनके मनों को, जिन के लिये हम उस काम को कर रहे हैं, नियोजन की ओर लगा सकें ताकि हम इस प्लान को, इस आम आदमियों के प्लान को उन आम आदमियों के द्वारा ही कार्यान्वित करा सकें।"

हम जो प्लान करते हैं उसमें हम सड़कों की बात करते हैं, हम शिक्षा के प्रसार की बात करते हैं, हम अधिक अस्पतालों की बात करते हैं। जाहिर बात है कि यह सब काम हमारे प्रदेश के जो रहने वाले सवा छः करोड़ व्यक्ति हैं, जो गरीब किसान, मजदूर और जो तमाम तबके हैं उनकी भलाई, बहबूदी के लिये होने जा रहे हैं। लेकिन आज तक जो कमी रही है हमारे नियोजन की वह सबसे बड़ी बुनियादी कमी यह रही है कि हमने अपने नियोजन के कामों में उन आदमियों का ख्याल कम रखा जिन के सुख और समृद्धि के लिये हम इस नियोजन को करने जा रहे हैं उन आदमियों के ख्याल से मेरा मतलब यह नहीं है कि उन आदमियों की फजिकल नीडस का ख्याल हमने नहीं रखा लेकिन जो उनकी मेंटल नीडस है जो उनके मनोभाव हैं उनका ख्याल हमारे प्लान में नहीं रखा गया है। कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनका स्वरूपीकरण किया जा सकता था। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह शिक्षा के प्रश्न को ही ले लें। शिक्षा मनुष्य के जीवन में सब से बड़ा स्थान रखती है। अंग्रेज आये भी और गये भी। हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं ने कहा कि वर्तमान शिक्षा अंग्रेजों की दी हुई है, यह केवल बाबू तबके को ही बनाती है। लेकिन आज आप देखें तो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जहां हमें इस बात का गर्व है कि हमने इतने स्कूल खोले इतनी पाठशालायें खोलीं हमारे नये कालेज, स्कूल और हाईस्कूल बनाये गये और हर साल एक एक स्कूल नहीं सैकड़ों हाई स्कूल हमारे प्रान्त में बढ रहे हैं सरकार के प्रयास से, प्राइवेट लोगों के प्रयास से और आम लोगों के प्रयास से लेकिन हमारे यहां इन नयी व पुरानी शिक्षा संस्थाओं की संख्या तो बढी पर इनमें वही पुरानी शिक्षा और वही पुरानी शिक्षा की पद्धति चालू है। इस प्लानिंग के बावजूद भी, इस नियोजन के बावजूद भी नियोजन के इस युग के होने के बावजूद भी जो चार वर्ष से हमारे यहां चल रहा है, वही पद्धति चली आ रही है। और यदि मैं यह कहूं, और बड़े अदब के साथ यह कहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कोई योजना सिवाय शिक्षा बढाने के और कोई नहीं है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो क्या यह शिक्षा हमारी गलत नहीं होगी जब तक कि हम इस बुनियादी प्रश्न को शिक्षा के संबंध में, हल नहीं करते और कोई योजना इस प्रकार से नहीं बनाते है कि शिक्षा हमारी कैसी हो। शिक्षा किसके लिये हो, शिक्षक कौन हो, शिक्षार्थी कौन हो और शिक्षार्थी अपने कालेज से निकलकर क्या करें। तब तक आम तौर पर समाज खतरे से बाहर नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है। जिसे हमको बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। अभी हमारे सामने विद्यार्थियों का, स्कूलों के मास्टरों का जब तरह-तरह का नकशा आता है तो सब के सामने ही यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। विद्यार्थियों के इस प्रश्न को कौन खड़ा करता है और मास्टरों के प्रश्न कैसे खडे होते हैं। और क्यों यह विद्यार्थी बहकावे में चले जाते हैं. इन सारे प्रश्नों का हल हमारी प्रादेशीय सरकार को और भारत सरकार को निकालना होगा यदि इस प्रश्न का हल नहीं निकाला गया तो बावजूद सड़कों के बनाने के, बावजूद बिजली की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ाने के और बावजूद अस्पतालों में और पागलखानों में मरीजों की सुविधा बढ़ाने के हमारे देश के लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होने वाली है और न हमारा कल्याण ही होने वाला है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि हमारी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा वे ठोस कदम उठायें जिससे विद्यार्थी जिस रोज शिक्षा लेने जाता है और जिस दिन उसकी शिक्षा पूरी होती है उसके पूरी होने के बाद उसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था हो जाय कि उसको जगह-जगह भटकना न पडे और इधर-उधर जाना न पडे। उनको स्थायी जीवन में लगने का मौका मिले हमारे शिक्षा केन्द्रों में जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा के पूरा होने पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अभी जब प्रश्नों का समय था तो एक प्रश्न हुआ कि जो अमुक जगह पर जो विद्यार्थी है इनके प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद उनके लिये निश्चित योजना सरकार ने बनायी है

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

उत्तर मिला स्वालम्बी बनाने की योजना है, पर मैं आपसे निवेदन बहुत अदब के साथ करना चाहता हूं कि हमारे इलाहाबाद में भी एक सरकारी ट्रेनिंग स्कूल है जो वोकेशनल स्कूल है। वहां पर बहुत से लड़के पढ़ते हैं और सरकार उनको स्टाइपेन्ड देती है लेकिन जब वह लड़के वहां से पढ़कर निकलते हैं तो वे काम पर नहीं लग पाते हैं। एक ओर हमारे यहीं, टैक्नीकल आदमियों की कमी है जिनकेद्वारा हमें प्लानिंग को पूरा करना है। उदाहरण के लिये कल या परसों प्रश्नों के समय सदन में यह मालूम हुआ कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक डिवीजन में ११ लाख ७५ हजार रुपया वित्तीय वर्ष ५४–५५ में इसलिये खर्च नहीं हो सका कि उनके पास उचित आदमी नहीं थे। एक ओर जिसके द्वारा काम पूरा कराना था वे आदमी हमारे पास नहीं है और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि जगह जगह से इतने आदमी पढ़कर निकलते हैं कि उनको काम कहीं नहीं मिल पाता है। मैं इस पंचवर्षीय योजना की किताब में जो कुछ भी इसमें है उसमें मैंने कुछ इस सम्बन्ध के आंकड़ों को जानने की कोशिश की मगर मुझे कहीं भी पता नहीं चला कि सरकार को इन आने वाले ५ वर्षों में कितने इंजीनियरों की जरूरत होगी, कितने ओवरसियरों की जरूरत होगी, कितने सर्वेयर की जरूरत होगी, कितने कारपेन्टर की जरूरत होगी कितने फिटर की जरूरत होगी आदि जो हमारे भिन्न भिन्न ट्रेड हैं उनके लिये कितने टैक्नीकल आदमियों की जरूरत हो जिनसे हमारे देश का उद्योग बढ़ सकता है और जिससे हम अपने देश का औद्योगिक ढांचा खड़ा कर सकते हैं। जिनसे बेकारी दूर हो सकती है। किस उद्योग या काम में कितने आदमियों को हम खपा सकेंगे। और कितने काम हमारे पास होंगे। यदि यह जानकारी होती तो निश्चय ही उतने आदमियों की ट्रेनिंग का इन्तजाम हम कर सकते और उसकी योजना बनाते और उनके प्रशिक्षण के लिये उतना ही अधिक रुपया रखने का प्रयत्न करते जितनी कि इन ट्रेड्स के लिये आवश्यकता है। यह सब शिक्षा के अंग में आते हैं और इस प्रसंग में यह बात इसलिये कह रहा हूं कि उन लोगों की भी जो हमारे स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों से आते हैं वही स्थिति है जो लोगों की है जो कि लार्ड मैकोले की बनायी शिक्षा योजना के अन्तर्गत कालेजों से पढ़कर निकलकर आते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार से विनम्र शब्दों में यह प्रार्थना करूं कि हमारे प्रशिक्षण केन्द्रों में जितने लड़के पढ़ने के लिये जांय जिस दिन भर्ती किये जांय तो उनसे पूछ लिया जाय कि वह प्रशिक्षण के बाद स्वयं कारोबार करना चाहते हैं या वह किसी जगह पर सर्विस में काम करना चाहते हैं। जो कुछ भी वह बतलाये उस प्रशिक्षण केन्द्र में उस विद्यार्थी को उसी प्रकार की शिक्षा दी जाय। यदि कोई किसी नौकरी में जाता है तो उसका वैसा ही कोर्स रखा जाय जिससे वह दूसरे के मातहत होकर बेहतर काम कर सके और यदि वह स्वयं कोई अपना काम करना चाहता है तो उसके कोर्स में कुछ फर्क रखना होगा। उदाहरण के लिये लीजिये टर्नर आपको बनाना है यह अगर वह काम सीखता है तो वह बाजार में अकेला कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि अकेला टर्नर कोई मायने नहीं रखता है उसका काम एक टीम के साथ हो सकता है।

मोल्डिंग, टर्निंग और फिटर का काम तीनों अलग-अलग हैं। पर सम्मिलित और सम्बन्धित है एक दूसरे से, यही कारण है कि जिसको टर्नर की शिक्षा मिली है वह टर्नर तो बन जायगा लेकिन स्वावलंबी नहीं बन सकता। जो रोजगार का काम है वह भी उसको वहां सिखाया जाना चाहिये। बिजनैस का जो मैनेजमेन्ट है वह भी एक स्किल है। वह एक अलहदा चीज है आज कोई भी ट्रेड कोर्स हो उसके कैरीकुलम में यह चीज हमें दिखायी नहीं देती। अतः यदि प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थी स्वावलंबी न हो पाये तो हमारे सामने जो समस्या है वह पूरी तरह से सुलझ नहीं सकती और बजाय

उसके एक भंयकर स्थिति ही पैदा हो जायगी । हम जितना रुपया खर्च कर रहे हैं जितनी तेजी से ट्रेनिंग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं अधिक हम सफल हो सकते हैं अगर इन छोटी-मोटी बातों पर विचार करने के बाद कोई बुनियादी कदम उठायें । मैं यह मानता हूं कि हमने खाद्यान्नों की कमी को पूरा किया है और ऐनीमल हस्बैन्डरी के काम में भी काफी तरक्की की है । आस्ट्रेलिया से भेड़ मंगा कर उनकी नस्लों में सुधार किया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ने की रिकवरी में पिछले १० सालों में क्या परिवर्तन हुआ है । हम एक एकड़ से सन् ४६ में कितना गन्ना पैदा करते थे और आज कितना करते हैं । और यह कि १०० मन गन्ना पेरने पर कितनी मन चीनी उस वक्त निकलती थी और कितनी आज है । उस गन्ने की हालत यह है कि ८·६ से लेकर ९·८ के वेरियेशन में हर साल कुछ कभी बेशी के साथ में चीनी निकलती है । अगर आप उसका लेखा चित्र (graph) बनायें तो जो लाइन उससे बनेगी वह उधर नीचे जाने वाले कर्व में घूमती हुई दिखायी देगी । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह ठीक है कि नहरें आपने बढाई, पानी बढ़ाया, गन्ने के क्षेत्रफल में बढोतरी हुई लेकिन गन्ने की रिकवरी तो नहीं बढी । यह भी ठीक है कि मकान अधिक बने ज्यादा से ज्यादा जगहों पर मकान बनाने की कोशिश की गयी लेकिन मकान बनाने के दामों में किस प्रकार नये साधनों से कमी हो सकती है और सस्ते मकान बनाये जा सकते हैं इस ओर कोई काम हम पूरा नहीं कर सके हैं। एक इस बात से संकटमय स्थिति हमारे प्रदेश में पैदा हो गयी है कि केन्द्रीय सरकार एक के बाद एक शुगर फैक्टरी को इस प्रदेश से बाहर जाने की इजाजत देती जा रही है और मलाबार तथा हैदराबाद दक्षिण को यहां की शुगर फैक्टरियां जा रही हैं क्योंकि वहां रिकवरी अधिक है । अगर यही अवस्था कायम रही तो हमारे प्रदेश के हजारों मजदूर मर जायेंगे और व्यापार नष्ट हो जायगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे । मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि बडे कामों को करने के साथ-साथ ऐसी बुनियादी बातों के ऊपर अपनी निगाह रक्खें तथा इस पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के पूर्व डिटेल में सम्बन्धित आकड़े इकट्ठे किये जायं और उसमें इस तरफ भी ध्यान रक्खा जाय कि उसको पूरा करने के लिये कितने और किस किस्म के आदमियों की आवश्यकता होगी और कितने और किस प्रकार के औजारों की आवश्यकता होगी । ऐसा न हो कि कहीं अस्पताल की बिल्डिंग बन गयी और वहां डाक्टर नहीं है, कहीं सड़कें बनने की बात हो लेकिन उसके लिये सर्वेयर न हो ।

यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी ७०० करोड़ रुपये की योजना तैयार हुई और उसमें ३३० करोड़ मंजूर भी हो गया है कुछ छोटी-छोटी मदों में और भी हो जायगा । मैं समझता हूं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते वह योजना करीब ५०० करोड़ के अवश्य हो जायगी ऐसी मैं समझ रहा हूं, क्योंकि अभी हाउसिंग में, वाटर वर्क्स में अभी काफी स्कोप है और मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी को उसके लिये प्लानिंग कमीशन ने विश्वास भी दिलाया है कि अगर वे ऐसे काम करेंगे तो और भी रुपया मिल सकेगा । लेकिन इन सब कामों को करने के पहले विचार कर लेना होगा कि उतने आदमी उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के हमारे पास मौजूद हैं या नहीं । अगर नहीं है, तो वह काम पूरा नहीं हो सकता और अगर है तो निश्चय ही पूरा होगा । इन बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि हाईस्कूल की स्टेज में जो शिक्षा पा रहे हैं उनको एडवाईजरी कौंसिल के जरिये से ऐसा किया जाय कि उन लड़कों को यह ज्ञात हो जाय कि इस वर्ष इतने सर्वेयस लगने वाले हैं । उदाहरण के लिये सर्वेयर्स का कोर्स तय कर लें इसकी सूचना आम विद्यार्थियों को आम लोगों को एक साल पहले से होनी चाहिये कि आने

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

वाले वर्ष में हमें इतने आदमियों की जरूरत पड़ेगी ताकि मां-बाप गार्जियन और विद्यार्थी मिल कर अपने जीवन को उसी ढांचे में बनाने की चेष्टा करें और सरकार को आवश्यकतानुसार आदमी वक्त पर, समय पर मिल जाय ।

हमारे प्रदेश में उद्योग की बड़ी चर्चा है और मुझे इस बात की खुशी है कि उद्योग के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की की है । मैं यह जानना चाहता था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के इन पिछले चार सालों में हैंडलूम के कितने करोड़ के कपड़े बने कितने रुपये के बिके और कितने रुपये का माल उत्पादकों के पास बाकी है लेकिन यह आंकड़े सरकार के पास नहीं है । हम हैंडलूम की इंडस्टीज को बढाना चाहते हैं हम मिर्जापुर की कारपेट इंडस्ट्रीज को बढाना चाहते हैं और हम इलाहाबाद के स्टील ट्रंक के कारबार को बढाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास यह जानकारी नहीं है कि जिस काम को हम बढाना चाहते हैं कि उसकी मारकेट में कितनी खपत है और मारकेट में क्या गैप है जिसको हमें आने वाले वर्ष में पूरा करना है। हमारे देश की ऐसी भावना है कि जो काम देखा उसी को करने के पीछे पड़ जाते हैं। मैं आपको एक मोटी मिसाल दूं कि एक जमाने में चक्की लगाने की ऐसी धुन सवार हुई जिसको देखो वही चक्की लगा रहा है और उस चक्की लगाने की धुन का नतीजा यह हुआ कि आज चक्की वाले सब रो रहे हैं । वैसे ही आजकल सुनाई देता है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये सरकार के पास बहुत रुपया है अब जिसको देखिये वही कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर सरकार के पास पहुंचता है कि हमें मदद की जाय। अगर नहीं मदद की जाय तो यह भी कहते हैं कि मदद नहीं की जाती । सरकार सहकारिता का कोई ख्याल नहीं रखती । फिर भी सरकार को चाहिये कि वह इस बात की पूरी जानकारी करे । क्या कार्य जो सोचा जा रहा है उपयुक्त है उसके बाद यदि सहकारिता के आधार पर कोई काम करना चाहे तो उसकी मदद करे । (श्रीमन चूंकि लाल बत्ती हो गयी है इसलिये मैं सिर्फ दो तीन मिनट ही चाहता हूं) आज कल प्लानिंग का जमाना ऐसा है कि जिस तरह से बाढ आती है तो उसके साथ ही कीचड़ और पत्थर भी बह कर आ जाते हैं उसी तरह से इस प्लानिंग युग की भी हालत हो गयी है । हमारी कुछ बहनें यहां बैठी हैं शायद उनको बुरा लगे । महिला मंगल योजना के काम को आप देखें और वह मंगल ऐसा है जिसके सामने यह उद्देश्य नहीं है कि कल्लू किसान लड़का जिसका व्याह किसी नत्थू किसान की लड़की के साथ होगा तो उनको जीवन की किन-किन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ेगा और उन्हें किस प्रकार पूरा किया जाय। महिला मंगल केन्द्र से ग्राम सेविकायें जब गावों में जाती हैं तो वहां की स्त्रियों को सिखाती हैं कि साबुन कैसे इस्तेमाल किया जाता है बाल कैसे बनाये जाते हैं कपड़े कैसे बनाये जाते हैं बलाउज भी एक चीज होती है जिसको पहना जाता है मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के मंगल की जो बातें हैं उसे करावें लेकिन गांव की रहने वाली महिलाएं जो उस आदर्श से अनभिज्ञ हैं जिन्हें हम उनके लिये आवश्यक समझते हैं । उनको उस ढांचे में ढालें जिस आदर्श को वे समझते हैं कि उनके द्वारा वे ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकती हैं। यह स्थिति आज हमारे सामने है । इस तरह की और भी बहुत सी खराबियां हैं जिनका जिक्र मैं इस वक्त नहीं करना चाहता लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं अपनी छोटी अक्ल के मुताबिक मंत्रियों के बीच जो भिन्न-भिन्न विभागों का बंटवारा है वह इस तरह से है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सिंचाई विभाग किसी के अन्तर्गत है तो विद्युत विभाग जिसका सिंचाई से सम्बन्ध है वह किसी दूसरे के अन्तर्गत है । सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग में तो एक तरह की

प्रतिस्पर्द्धा भी चल रही है। विद्युत विभाग वाले कहते हैं कि सिंचाई विभाग वालों की गलती से ही हम इतना किलोवाट बिजली जो देना चाहते थे नहीं दे सके और सिंचाई विभाग वाले कहते हैं कि विद्युत विभाग वाले जल्दी करके अपना काम गलत कर लेते हैं लेकिन हम तो गलत काम करेंगे नहीं हम तो सही काम ही करेंगे। इस तरह से विभागों का जो विभाजन हुआ है वह ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि कौन विभाग किसमें रहेगा। समाज कल्याण मंत्रणालय का मैं उदाहरण के लिये कहता हूं। अब जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरंभ करने जा रहे हैं तो हरिजन कल्याण विभाग शिक्षा मंत्री जी के पास है। श्रमिकों को कल्याण श्रम मंत्री जी करेंगे, पिछड़ी जातियों का कल्याण शिक्षा मंत्री जी करेंगे और पता नहीं कि महिलायें का कल्याण कौन करेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्रणालय का विभाजन कुछ ऐसे किया जाय कि नियोजन का काम ठीक से चल सके। इस तरह से नतीजा यह होता है कि अफसर बढ़ते जाते हैं और उनका एक सेन्ट्रल ब्रादरहुड-सी और एक सेना-सी बनना शुरू हो जाती है। इसलिये अन्त में मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि विभागों को फिर से बांटकर इस तरह से बनाया जाय कि उनकी मशीन जल्द से जल्द काम को आगे बढ़ाने में और माननीय नियोजन मंत्री की योजनाओं को सफल बनाने में सहायक हो सकें।

*श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नियोजन मंत्री का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने यहां पिछली पंचवर्षीय योजना के कार्य की प्रगति का वर्णन किया और अगली पंचवर्षीय योजना के विषय में जो उनका लम्बा भाषण हुआ उस को सुनने के बाद और जो पुस्तिका इस सम्बन्ध में हमारे सामने रखी गयी है उसको पढ़ने के बाद मुझे इस बात का सन्तोष हुआ कि जो कार्य हमने अपनी पिछली योजना में रखा था उसको हमने पूरा किया। कोई प्लान बनाना मुश्किल नहीं है लेकिन उसके मुताबिक काम करना बहुत ही श्रेय की चीज है और अधिक श्रेय तभी होता है कि जब प्लान बने और उसके टार्गेट से आगे काम हो जाय। आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि पिछली पंचवर्षीय योजना में ८८ करोड़ रुपया खर्च करने की बात थी लेकिन ५ साल में कुल १६६ करोड़ रुपया खर्च होने की योजना बनी और हमने उसका बहुत कुछ भाग पूरा किया। यह तो हमारे लिये बहुत ही संतोष की बात है लेकिन देखना यह चाहिये कि आगे जो योजना बन रही है उसमें हम किधर जा रहे हैं। मैंने बहुत ध्यान से माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को सुना और उसको समझने की कोशिश की। जैसा कि हमें विश्वास था कि माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से हमें कुछ रचनात्मक सुझाव दिखलाई पड़ेंगे। उसको देखते हुये हमें उनका भाषण सुनकर बड़ी निराशा-सी हुयी कि उन पर भी कुर्सी का असर पड़ गया और गौर करने के बाद मुझे वही पुरानी अलाप और पुरानी बातों के सिवा कोई नयी बात को देखने नहीं मिली। माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात पर आक्षेप किया था कि यह प्लानिंग नीचे से नहीं किया जा रहा है, मुझे खुशी हुयी कि वह इस ओर कुछ कहना चाहते थे लेकिन सिवा आलोचना के उन्होंने कोई ऐसी बात जनता के या इस सदन के सामने नहीं रखी जिससे हमें उनके सुझाव से कुछ मदद मिलती। पता नहीं, प्लान को नीचे से बनाने का उनका आशय क्या था। जहां तक मैं समझता हूं यह कभी सम्भव नहीं है कि प्लान गांव या जिला स्तर पर या यहां बने। जब प्लान बनती है तो प्लान के माने यह होते हैं कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं को सामने रखकर प्लान बनती है, यह सम्भव नहीं है कि हम उस पर ध्यान न दें। माननीय नियोजन मंत्री जी के भाषण से मालूम हुआ कि इस द्वितीय प्लान में जो पहले की प्लान में कमी थी वह दूर की गयी है। मैं यह तो नहीं मानता कि यह प्लान पूर्ण रूप से नीचे से बनी है लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधामोहन सिंह]

इस बात की कोशिश की गयी है कि उसको नीचे से बनाया जाय, नीचे से बनाने का मतलब यह है कि जनता की आवश्यकताओं को आगे रखकर प्लान बने और इसको देखने से मालूम होता है कि इसकी चेष्टा की गयी है। ऐसा समझने से मतलब यह है कि यहां कई हजार मील सड़कें बन जाय, स्कूल खुल जायं, अच्छे अस्पताल बन जायं, हाउसिंग स्कीम्स बढ़ा दी जायं या लाखों एकड़ जमीन खेती में ला दी जाय, यही प्लानिंग नहीं है, इससे इतना तो हो सकता है कि हमें कुछ प्रसन्नता हो कि हमने प्रगति की, लेकिन प्लान इसी को नहीं कहते। प्लान के लिये आवश्यक है कि हमारे सामने लक्ष्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति का और उपलब्ध साधनों के एकीकरण का होना चाहिये और उसके बाद देखना होगा कि हम उनका प्रयोग करके कहां तक अपनी प्रगति कर सकते हैं। ठीक यही है कि जो काम हम स्कीम्स में रखें उनको पूरा करें बजाय इसके कि हम हवा में महल बनावें और बड़ी प्लान बनाकर उनको पूरा न कर सकें। इसलिये इस प्लान को हम राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर बेस करने जा रहे हैं और मुझे इसमें इसकी झलक दीख पड़ती है। दूसरी बात जो इसमें है वह यह है कि इस बात की कोशिश की गयी है कि यहां की बेकारी की समस्या हल की जाय और यह बेकारी की समस्या जो नया रूप धारण करने जा रही है उसको भी हल करने का प्रयत्न किया गया है।

सब मानते हैं कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिये उद्योग-धंधों के विकास के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बेकारी का बिस्तार क्या है उसका रूप क्या है तब हम समझ सकते कि इस प्लान में उसको कैसे पूरा किया जायगा। हमें इस बात को सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारे मुल्क में बेकारी है। जहां पर लाखों आदमी खाली पेट पड़े रहते हैं, जहां लाखों लोगों के पास उचित रूप से पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं, जहां पर लाखों आदमी पढ़े-लिखे नहीं हैं, जहां पर बहुत से आदमियों को दवादारू नहीं मिलती और मौत के वह शिकार होते हैं वहां यह कहा जाय कि हमारे यहां बेकारी है। मैं समझता हूं कि जहां इतने घर बनने हैं, इतने आदमियों को शिक्षा देनी है, इतने आदमियों को पढ़ाने का प्रबंध करना है वहां बेकारी कैसे रह सकती है? काम तो हमारे बहुत से हैं लेकिन क्या वास्तविक स्थिति है। बात यही है कि हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी इस प्लान के अन्दर समय है। जो रुपया रखा गया है उससे बहुत बड़े-बड़े काम हो सकते हैं। समय कम होने की वजह से मैं नियोजन मंत्री जी के सामने तीन-चार सुझाव छोटे-छोटे रखना चाहता हूं और मैं आशा करूंगा कि उन सुझावों पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स से रायलें गे और देखेंगे कि कहां तक उनकी पूर्ति कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि नियोजन के लक्ष्य की पूर्ति आवश्यक है और उसकी पूर्ति के लिये हमें साधन एकत्र करने पड़ेंगे और साथ ही हमें देखना पड़ेगा कि हम कोई चीज ऐसी न कर बैठें कि हमारे साधनों का दुरुपयोग हो। हो सकता है कि हम पूरा न कर पावें लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि सबसे जरूरी बात जो हो उसको प्रायरिटी मिले। अगर हमारे पास रुपया कम है और आवश्यकताएं हमारी अधिक हैं तो हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि किन बातों को हम पहले लें। यह सम्भव नहीं है कि तमाम कमियां राष्ट्र की एकाएक पूरी हो जावें इसलिये हमें देखना पड़ेगा कि किन को हम पहले लें। अगर कोई भूखा है तो उसके सामने ४ धोतियां रख दें या अच्छी-अच्छी दवायें रख दें तो क्या होगा? क्या उसकी भूख दूर हो जायगी? इसलिये पहले उसकी भूख का इलाज करना है। इसलिये हमें सबसे पहले यह देखना चाहिये कि राष्ट्र को सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है। हमारे विरोधी दल के माननीय नेता महोदय यह समझते हैं कि जमीन का बटवारा होना बहुत जरूरी है लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात उतनी जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब इस वक्त समाप्त कीजिये। आप सात मिनट बोल चुके हैं। अब आपका १५ मिनट समय और रहेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राधामोहन सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रीय प्रगति में और राष्ट्रीय नियोजन में अन्तर होता है। जब हमारे यहां प्लानिंग नहीं थी तो बहुत से स्कूल, अस्पताल, नहरें और सड़कें बनीं, लेकिन प्लानिंग से अन्तर यह होता कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते। आज हमने यह तय कर रखा है कि हमारी सोसाइटी का रूप सोशलिस्ट पैटर्न होगा और उसके अनुसार हमें अपना प्लान भी बनाना है। इसी से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। सोशलिस्ट पैटर्न में उत्पादन और वितरण में समता होती है और राष्ट्रीय स्तर पर सबको खाने, पहनने और रहने की व्यवस्था होती है साथ ही राष्ट्रीय उत्थान का द्वारा खुला होता है। प्लानिंग का जो नकशा हमारे सामने रखा गया है वह बहुत बड़ा है और किसी भी माननीय सदस्य के लिये यह सम्भव नहीं है कि पूरे-पूरे नक्शे को सामने रखकर उस पर आलोचना कर सके। यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि हम कुछ भी नहीं कह पायेंगे। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से २,३ बातों पर ही अपने निवेदन को सीमित रखूंगा।

मैं पहले शिक्षा को लेता हूं क्योंकि यह बुनियादी चीज है। हमें सोचना होगा कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या है और क्या होना चाहिये। हमारे बहुत से नवयुवक लिख-पढ़ गये हैं और एम०एस०सी० पास करके सेक्रेटरियेट में नौकरी क्लर्की की करते हैं। ऐग्रीकल्चर के बी०एस०सी० हैं वे भी छोटी-मोटी नौकरियां में मारे-मारे फिरते हैं। यह एक सामाजिक अव्यवस्था है। अगर हम प्लानिंग से काम करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। शिक्षा का लक्ष्य जीवन पर ही आधारित हो सकता है। हमारे जीवन की बहुत-सी आवश्यकताएं हैं। यह आवश्यक है कि सबको पढ़ना लिखना चाहिये और उसके बाद ऐसी योग्यता होनी चाहिये कि हम अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अपना भरण-पोषण ठीक तरह से कर सकें। साथ ही मानवसमाज को उन्नति करनी है। हमको यह निश्चय करना होगा कि हमारे विश्व-विद्यालयों में जो आज अनियंत्रित ढंग से भर्ती होती है वह कैसे बन्द हो। यह तब ही होगा जबकि जितनी नौकरियां और व्यवसाय इत्यादि हैं हम उन सबका हिसाब लगाकर यह देखें कि हमारी आवश्यकता क्या है। कितने इंजीनियर, डाक्टर, ओवरसियर, इत्यादि हमें चाहियें, यह देखकर शिक्षा देनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई इंजीनियरी पास करके घर में बैठा रहे या डाक्टरी पास करके बेकार रहे। हमें वोकेश्नल स्कूल खोलने की अधिक आवश्यकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अपने लक्ष्य का निर्धारण करके बड़े पैमाने पर उसका प्रसार किया जाय और साथ ही लोगों को उसे समझाया जाय। इससे हमारे राष्ट्र की धन और बल की हानि होने से रुकेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में हमें नियोजन से काम लेना चाहिये। हमें जल्दी से जल्दी एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिये जो यह देखे कि हमारी आवश्यकता क्या है और किस प्रकार ऐसे लोग ट्रेन किये जावें। उसके मुताबिक हमें स्कूल खोलने चाहिये। यदि हमने स्कूल सब जगह खोल दिये और पढ़ने वाले नहीं मिले तो यह भी राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग है। जो प्लान यहां रखा गया है इसके अन्दर केवल यही दर्शाया गया है कि किन-किन मदों में हम रुपया खर्च करने जा रहे हैं लेकिन किस प्रकार खर्च करेंगे यह नहीं है। मुझे जानकर खुशी हुई कि शिक्षकों की दशा सुधारने के लिये कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय पैमाने पर हमें निश्चय करना होगा कि भिन्न-भिन्न नौकरियों के लिये हमें क्या करना चाहिये। यह तय करना होगा कि आई०ए०एस० की नौकरी इतना पढ़ने के बाद मिलेगी और डिप्टी कलेक्टर के लिये इतना पढ़ना जरूरी है। यदि एक में हम ५ वर्ष रखते हैं तो दूसरे में यह रखना होगा कि ४ साल में वह मिल सकेगी। राष्ट्रीय जरूरत को

[श्री राधामोहन सिंह]

मुताबिक स्कूल खोले जावें और आवश्यकता के अनुसार उनमें भर्ती हो। कोई ऐसा आदमी न रहे कि लॉ पास करने के बाद या इंजीनियरिंग पास करने के बाद वह बेकार रहे या अपने जीवनयापन के लिये आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहे।

हर एक नागरिक राष्ट्रीय सेवा में लगा है चाहे वह इंजीनियर हो, डाक्टर या प्रोफेसर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो। उसके जीवनयापन और जिम्मेदारी के मुताबिक उसका वेतन होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि बी०ए० पास कोई तो २,३ हजार रुपये कमाये और कोई २०,३० रुपये पर ही पड़ा हो। शिक्षा को एक नियोजित ढंग से चलाना होगा कि हमारे यहां समाज में न्याय हो। समाज में सामाजिक न्याय हो, इंसाफ हो और हर एक आदमी को अवसर मिले आगे बढ़ने का।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह कृषि के सम्बन्ध में है। हमको तय करना होगा कि कृषि के सम्बन्ध में हम क्या करना चाहते हैं? अभी नेता विरोधी दल ने बतलाया कि वे जमीन का बटवारा चाहते हैं। यह पुराना स्लोगन है और सुनते-सुनते कान पक गये हैं। समझ में नहीं आता कि उनका उद्देश्य क्या है? बटवारा करने का क्या यह लक्ष्य है कि हर एक आदमी के पास जमीन हो जाय, या यह लक्ष्य है कि सबके पास साधन हों, उत्पादन बढ़े जिससे राष्ट्रीय आय का स्तर ऊंचा हो सके? अगर दूसरा लक्ष्य है तब तो बात दूसरी है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि उत्पादन कैसे बढ़े? अगर बटवारा करते हैं और साधन न हों तो हम उत्पादन बढ़ा नहीं सकते। मैं कहता हूं कि हमको इस बात पर बड़े गौर से विचार करना चाहिये कि हमारा लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं कि सबको खाना पूरा मिले। हमारी एकोनामी जो है वह ज्यादा पैमाने पर कृषि पर ही निर्भर करती है। हमको संतोष नहीं है जैसा कि माननीय नियोजन मंत्री जी ने कहा कि हमने अपना फूड टार्गेट पूरा कर लिया। मैं इसे पूरा नहीं समझता कि हमने अपने खाने लायक, जरूरत के मुताबिक पूरा कर लिया। जब तक सब लोगों के खाने के बाद उनकी और जो आवश्यकतायें हैं वे पूरी न हो जायं तब तक हम इसको पूरा होना नहीं कह सकते। अगर किसान अनाज इतना ही पैदा करता है कि वह खुद खा जाय तो यह ठीक नहीं है, बल्कि ठीक यह होगा कि वह इतना पैदा करे कि खा सकने के बाद इतनी अधिक उपज हो जिसे बेंच कर वह अपने लड़कों को पढ़ा सके, अच्छा खाना खिला सके, दवा-दारू का इन्तजाम कर सके और अच्छा कपड़ा पहना सके। अगर ऐग्रीकल्चर के उत्पादन से वह इतना कर सके तभी हमें संतोष होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि कृषि के सम्बन्ध में जो लक्ष्य है वह इतना बड़ा होना चाहिये कि उसके जरिये से हम अपने खाने की ही जरूरत को पूरा न करें बल्कि उसके जरिये से हम अपनी एकोनामी को उठायें। अगर ऐसा होगा तो शीघ्र ही जमीन की भूख खत्म हो जायगी और जमीन के बटवारे का जो नारा लगाया जा रहा है यह नारा बेकार साबित होगा। प्लान के अन्दर जो हम औद्योगीकरण को देखते हैं अगर उसे हम आगे बढ़ाते हैं तो जो जमीन की भूख है, जिसके लिये आज सब जान देने के लिये तैयार हो गये हैं वह भूख खत्म हो जायगी। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन करें। यह तभी संभव होगा जब हम यह निश्चय करेंगे कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय? मुझे इस बात का संतोष है कि अच्छी खाद, अच्छे बीजों और पानी का प्रबंध इस प्लान के अन्दर किया जाने वाला है। उससे हम इस समस्या को हल कर पायेंगे।

साथ ही एक बात की कमी है। ऐसा मौका आ सकता है कि हमारे नवयुवक नौकरियों की तरफ या उद्योग व्यवसाय की तरफ अधिक खिंच जायं और किसानों की तरफ न खिंचें। इसलिये उन्हें किसान बनाना पड़ेगा। यह तभी हो सकता है जबकि गवर्नमेंट हर जिले में दो बातों का प्रबंध करे। एक बहुत बड़ा फार्म हो और एक बहुत बड़ा औद्योगिक आश्रम हो। ऐसा करने से आजकल जो पढ़े-लिखे लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, और जो हमारे मिनिस्टर साहबान और एम०एल०एज० को तंग करते हैं, उनसे कहा जा सकता है कि अगर तुम काम चाहते हो तो हमारे उस फार्म पर जाओ। वहां पर उनके खाने-पीने की व्यवस्था हो, अच्छे स्तर पर वे वहां रह सकें। वहां वे काम करें। वहां उन्हें अगर मजदूरी करनी पड़ेगी तो

काम करने से उन्हें प्रेम उत्पन्न होगा और उसमें वे लग जायेंगे। आज जो टेंडेंसी है, जो प्रेरणा उनमें है उससे ऐसा मालूम होता है कि हमारे नवयुवक देहातों से भाग कर शहरों में आकर सेक्रेटेरियट में पंखे के नीचे बैठ कर क्लर्की करना पसन्द करते हैं, और इसके बाद उद्योग-धंधों में जायेंगे, लेकिन खेती की तरफ उनका आकर्षण नहीं है। जिस तरह जापान में खेती की तरफ प्रोत्साहन दिया जाता है, हमारे छोटे-छोटे फार्म वाले हैं, किसान हैं उनको हम प्रोत्साहन दें। इस बात की योजना बनायें कि किसानी में रहते हुये वह इतना पैदा कर सकें कि अच्छे स्तर पर अपना जीवन बसर कर सकें। जापान के अन्दर मैंने सुना है कि जिसके पास सात एकड़ जमीन होती है वह पक्के मकान में रहता है, अपने लड़कों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, और जो खाना हमारे यहां के ऊंचे स्तर के लोग खाते हैं वह खा सकता है। वह रेडियो और मोटर रखता है। अगर ये चीजें देहात के रहने वाले लोगों को उपलब्ध हो सकें तो हमारे जमींन के उद्देश्य की प्राप्ति हो जायगी।

तीसरी बात यह है जो मैं औद्योगीकरण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे एक बात की खुशी है कि उद्योग मंत्री जी ने बताया कि इस प्लान में इसका समावेश है कि उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। लेकिन मैं चाहता हूं कि खेती और करघा ये दो ऐसे उद्योग हैं जो कम रुपयों में बहुत कुछ शिक्षा के न होते हुये भी उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने देखा है कि बाढ़ के क्षेत्रों में जहां कि बहुत से लोग बे घर-बार हो गये हैं, जिनको जल्दी में हम कुछ नहीं दे सकते सिवा इसके कि १५, २० रोज तक वे अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन इसमें एक डिमारेलाइजेशन का प्रश्न होता है। बिना काम लिये हुये अगर खाना दें तो कुछ दिन में हमारा नैतिक स्तर नीचा हो जाता है। जिस गांव में हमने १२ सौ रुपया खर्च किया और बहुत से घरों में चर्खा दिये गये, उसका नतीजा यह हुआ १३ सौ रुपये महीना उस गांव में चरखे के जरिये से आमदनी हो गयी। अगर हम इस तरह से आगे इस उद्योग को गांव-गांव फैलायें और प्रोत्साहन दें तो हमारे यहां जो समस्या है वह हल हो जायेगी। हमारे यहां मैन-पावर की कमी नहीं है, लेकिन हम उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि बड़े कारखाने न खोले जायं, खोले जायं लेकिन जल्द से जल्द कम रुपयों में, जिससे किसानों के घर में चार पैसे आ सकते हैं, वह गृह उद्योग और चरखा करघा ही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से हर जिले में बड़े-बड़े फार्म रखे जायं जहां पर बेकार लोगों को भेज सकें, ऐसे ही उद्योग आश्रम खोलें जिससे उद्योग-धंधों की ट्रेनिंग दी जा सके। इस तरह से हम देखेंगे कि चन्द महीनों के बाद कोई ऐसा आदमी नहीं दिखलायी पड़ेगा जो किसी मिनिस्टर से कहे कि हमें नौकरी दो। नौकरी की मांग कम हो जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो बातें अगर हम कर दें तो उस जगह पर हम कम से कम एक इज्जत के साथ में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करते हुये उनके लिये रहने और खाने का प्रबंध कर पायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्लान का जो फ्रेम है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उससे हमारे राष्ट्र की प्रगति होगी।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या आपने कोई वक्त मुकर्रर कर दिया है, तकरीर करने के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि १५ मिनट लें। बात यह है कि आपकी तबियत भी बहुत अच्छी नहीं है।

*श्री सुल्तान आलम खां---जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल से हमारे फर्स्ट फाइव इयर प्लान और सेकेंड फाइव इयर प्लान पर जो तकरीरें होती रही हैं, मेरी बदनसीबी है कि मैं उनमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

से बहुत सी तकरीरों को नहीं सुन सका, मैं मौजूद नहीं था। लेकिन माननीय नियोजन मंत्री का जो भाषण इस सिलसिले में हुआ वह ऐसा था जिससे हमको बहुत कुछ मालूमात मिल सकती हैं और उससे पता चल सकता है कि हमारे सूबे के अन्दर इस पिछली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ ?

जनाबवाला, यह सही है कि पंचवर्षीय योजना और मुल्कों में भी बनीं। रूस में बनीं, चीन में बनीं और दूसरे मुल्कों ने भी अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनायीं। लेकिन एक बैकवर्ड देश होने की हैसियत से हम सबसे ज्यादा मुस्तहक थे कि हमारे सामने एक पंचवर्षीय योजना हो और उसके मुताबिक हम इस मुल्क में तरक्की कर सकें। जो पहली योजना हमारे मुल्क में आयी है सही है कि वह योजना इस तरीके पर नहीं आ पायी जैसी कि आनी चाहिये थी या जैसी कि अब दूसरी योजना का इंतजाम किया जा रहा है। वक्त गुजर गया और इसलिये उस योजना को ज्यादा-तर उन लोगों के हाथों से बनाया गया जो लोग बहुत ज्यादा पब्लिक के साथ सम्बन्ध नहीं रखते थे, और शायद यही वजह है कि बावजूद इसके कि हम इस बात को फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे योजना के बहुत से टार्गेट्स वक्त से पहले पूरे हुए लेकिन फिर भी शायद इसमें और भी ज्यादा कामयाबी होती। लेकिन उसकी यह वजह हो सकती है कि उन लोगों की जिनकी कि आवाज इसमें पूरे तरीके से शामिल होनी चाहिये थी वह इस वजह से न हो सकी और जो योजना हमने इस मुल्क के अन्दर चलायी और हमने सूबे के अन्दर चलायी यह नहीं कहा जा सकता कि वह नाकायमयाब रही। हो सकता है कि बहुत से लोगों की तवोक्कोवात बहुत ज्यादा हों और उन तवक्कोवात की कसौटी पर उसको कसा जाय तो वह पूरी न निकलती हो लेकिन अगर फिर भी ऐतराज करने की कोशिश हो सकती है तो यह सही है कि इसके जरिये से हमने अपने देश में और परदेश में बहुत से अचीवमेंट्स किये और उन अचीवमेन्ट्स को भुलाना या उनकी अहमियत को कम करके दिखाना मुनासिब बात नहीं होगी। यह सही है कि योजना के जरिये से हर चीज पर तवज्जह दी गयी, खासतौर पर मैं एक बात का जिक्र करूंगा कि हमारे सूबे के अन्दर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और नेशनल ऐक्सटेंशन ब्लाक्स के बहुत से सेंटर्स कायम किये गये और उनके अन्दर हम भी गये, और हम इस बात को कह सकते हैं कि वाकई इनके जरिये से मुल्क सही रास्ते पर पड़ रहा है। इनके जरिये से मुल्क तरक्की के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और शायद वह दिन दूर नहीं है कि जब १० साल गुजर जाने के बाद इस मुल्क के हर गोशे गोशे में हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट होंगे और उनके जरिये से हम जितनी हमारी सर्विसेज हैं, ऐग्रीकल्चर है, ऐनीमल हस्बेंडरी है, इंडस्ट्रीज में, उन सबको तरक्की दे सकेंगे। यह जनाब-वाला सही है कि इस योजना में ऐग्रीकल्चर और इरिगेशन के ऊपर काफी तवज्जह दी गयी और दूसरों पर उतनी तवज्जह नहीं दी जा सकी जितनी कि इन दो आइटम्स पर दी गयी। यह सही भी था और इसलिये सही था कि उस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत बड़े कहत से गुजरा था जिसने हमारे सामने खाने का बड़ा मुश्किल मसला पेश कर दिया था। लेकिन आज हम फख्र कर सकते हैं कि हम अपने उस टार्गेट से कहीं आगे बढ़ गये हैं जो हमने तय किया था और और हमारा मुल्क न आज सेल्फ सफिशियेंटी हो गया बल्कि हम सरप्लस भी हो गये कि हम दूसरों को गल्ला दे सकते हैं।

जहां तक कपड़े का सवाल है उसमें भी हम आज महसूस कर सकते हैं कि हमारी जो दुश्वारियां थीं पहले, वे अब नहीं रहीं। आज वह दिन है जिस दिन हम इस बात का जायजा लगाने के लिये बैठे हैं कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में क्या बात रह गयी और जो आइन्दा हम चलाने वाले हैं उसके लिये हमें देश में क्या बन्दोबस्त करना है ? खुद प्लानिंग कमीशन ने कहा कि पंचवर्षीय योजना बिल्कुल एक प्रीपरेटरी चीज है, हम इस पर यह भरोसा नहीं कर सकते हैं कि इसके जरिये से हमारी तमाम मुश्किलात रफा हो जायंगी हमारी गरीबी दूर हो जायगी। यह कोई छू मन्तर नहीं है। बल्कि यह सही है कि यह एक कदम है हमारी बेहतरी के लिये, हमारे सही रास्ते पर जाने के लिये। और इस पंचवर्षीय योजना के बाद न सिर्फ सेकेंड

फाइव ईयर प्लान ही हमको चलानी पड़ेगी बल्कि न मालूम कितनी प्लान चलानी पड़ेंगी जबकि हम उन लोगों के बराबर आ सकेंगे जिनके मुकाबिले में हम बहुत पिछड़े हुये हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का तजुर्बा हमारे सामने हैं, हमने साढ़े चार साल तक काम किया। आइन्दा मार्च में ५ साल भी पूरे हो जायेंगे, और अब यह वक्त आया है कि हम इसके तजुर्बे की रोशनी में अपने लिये एक प्लान बनायें, प्रोग्राम बनायें कि हम आइन्दा क्या करने वाले हैं? मुझे इसकी खुशी है कि इस बात की कोशिश की गयी है कि इस प्लान का ऐसा प्लान बनाया जाय कि इस प्लान में हर शख्श की आवाज हो। यह तो सही है कि जो भी फाइव ईयर प्लान मुल्क के अन्दर बनायी जाय वह किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि वह तो कौम की प्लान है। और इसी वजह से इस बात की जरूरत है कि उसके साथ में सब लोगों का सहयोग हो।

अब जब कि इस वक्त सेकेंड फाइव ईयर प्लान का खाका हमारे सामने है उसको बनाने के लिये सिर्फ यही कोशिश नहीं की गयी है कि उसको इस सूबे के अन्दर बनाया जाय या उसको प्लानिंग कमीशन दिल्ली में बैठकर बनाये, बल्कि इस बात की कोशिश की गयी है कि हर आदमी इस प्लान में अपना सजेशन दे ताकि सब लोगों की आवाज इसमें हो और यह कहा जा सके कि हमारा प्लान नेशनल प्लान है और इसके जरिये से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना है कि कोई भी प्लान, जो हम इस सूबे और मुल्क के लिये बनायें, उसके लिये हमें दो चीजों की सब से सख्त जरूरत होगी। एक तो हमें जनता का ज्यादा से ज्यादा कोआपरेशन, सहयोग हासिल कर सकें, और दूसरे यह कि हमें किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी हद तक अपनी जिन्दगी को एक रेगुलेशन के अन्दर,एक कंट्रोल के अन्दर रखना पड़ेगा। जहां तक कि कोआपरेशन की बात है, मैं इस बात को मानता हूं कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में हमें उतना कोआपरेशन जनता की तरफ से नहीं मिल सका जितना हम एक्सपेक्ट करते थे या जितने कि हमें जरूरत थी हमें इस बात को देखना है, अपने दिल को टटोलना है कि आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह शायद यही है कि पब्लिक में जनता में, उतना ऐंथूजियाज्म नहीं कर पाया जितना कि इस प्लान को अपनाने के लिये उनके दिल में पैदा होना चाहिये था। मैंने एक किस्सा सुना है कि एक मर्तबा हमारे यहां के एक मुअज्जिज शख्स चीन के दौरे पर गये। चीन में वह कोई प्लान का काम, जो बड़े जोर से हो रहा था, देखने गये। तो उन्होंने वहां के मजदूरों से और पास खड़े आदमियों से जो इकट्ठा थे बात की और पूछा कि बतलाओ यह क्या हो रहा है, इसमें क्या चीज हो रही है, इससे क्या नफा होगा? इसमें तुम्हारा क्या हिस्सा है? तो उनमें का हर शख्स और हर मजदूर जो काम कर रहा था उसने प्लान का पूरा नकशा बतलाया, जो उसके डिटेल्स थे बतलाये, और यह भी कहा कि इस प्लान के बन जाने से हमारे मुल्क को नफा होगा, उसके साथ हमको भी नफा होगा और इसी वजह से हम यह करते हैं कि जितना वक्त काम करने का हमारे लिये दिया गया है उससे कुछ ज्यादा वक्त निकाल करके हफ्ते में एक दो घंटे ज्यादा काम करते हैं और यह हमारा वालेन्टरी वर्क है, श्रमदान है जिसमें हम उस काम के तकमिले में हिस्सा लेना चाहते हैं जिसके तकमिले के बाद हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर जायगा। लेकिन एक ऐसा मौका आया कि एक हमारे यहां के जिम्मेदार शख्स तुंगभद्रा प्रोजेक्ट का काम देखने के लिये गये। उन्होंने जाकर यहां के मजदूरों से पूछा कि यहां जो काम हो रहा है उसका क्या मतलब है, क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ इस कदर जानते हैं कि हम सुबह यहां आते हैं। हमें ओवरसियर जिस काम पर लगाता है, उसको करते हैं। सुबह ८ बजे आ जाते हैं ५ बजे रुखसत हो जाते हैं। हमें नहीं मालूम क्या मकसद है इसका और क्या इससे नफा या नुकसान होगा? तो यह फर्क है उस भावना का, दिलचस्पी का, उस ऐंथुजियाज्म का जो वहां चीन के मुल्क में मिला, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नहीं मिल सका।

तो मैं अर्ज करूंगा कि अगर हमें प्लान को पूरे तरीके से कामयाब बनाना है तो हमें लोगों के अन्दर ऐंथ्युजियाज्म पैदा करना होगा और बगैर इस चीज के फर्क के कि इस तरफ

[श्री सुल्तान आलम खां]

के बैठने वाले हों या उस तरफ के बैठने वाले हों, हमारा फर्ज़ है कि उसको पब्लिसिटी दें और उसको एक मुनासिब तरीके से लोगों तक पहुंचायें जिससे यह उनको मालूम हो कि यह काम उनके लिये बहुत ज़रूरी है और इसको उन्हें पूरा करना है, और इसके ऊपर उनकी मौत जिन्दगी का दारोमदार है। और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अन्दर गुड-विल की कमी नहीं। अगर हम सही तौर से लोगों तक ऐसी तफसील पहुंचा दें तो उनके अन्दर इस बात की भावना पैदा हो सकती है और वह काम करने के लिये तैयार हो सकते हैं। बहरहाल हमारे सामने एक मिसाल हमारे मुल्क में और सूबे में जो श्रमदान होता है, वह मौजूद है। हिन्दुस्तान की तवारीख में इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया कि लोग श्रमदान के तौर पर काम करने के लिये आये। हां, ऐसे इल्जामात रहे कि उनकी मर्जी के खिलाफ काम उनसे लिया गया। लेकिन श्रमदान और वालंटरी लेबर का इतने बड़े पैमाने पर काम कभी नहीं हुआ जिसको कि हम सब जानते हैं और जिसको दोहराने की मुझको कोई ज़रूरत नहीं है।

लेकिन अब भी हमारा काम इस सिलसिले में कम नहीं हुआ है। हमें इसमें पब्लिसिटी देना है, इसको और ज्यादा ऊंचे ले जाना है। कल से जो तकरीरें हुयी उनके दरमियान बाज बातें कही गयीं, बहुत सजेशन अच्छे-अच्छे आये, लेकिन एक आध बात ऐसी भी आयी कि जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका? एक जगह से यह भी कहा गया कि इस मौके पर कि जब हम सेकेंड फाइव ईयर प्लान का खाका पढ़ रहे हैं, हमको इस बात को भी तय कर लेना चाहिये कि हम जमीनों को रिडिस्ट्रिब्यूट करें, हम उनके ऊपर सीलिंग मुकर्रर कर दें। मैं यह अर्ज़ करूंगा कि अगर हम उस कमेटी की रिपोर्ट देखें कि जिस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जमींदारी का एबालिशन हुआ था तो हमें मालूम यह होगा कि हमारे यहां इकानामिक होल्डिंग की बहुत कमी है। तो ऐसी सूरत में अगर हम फर्ज़ कीजिये ज़मीन का फिर से बटवारा करें तो यह बात एक मर्तबा नहीं बहुत मर्तबा कही जा चुकी है और इस पर बहस हो चुकी है कि इससे हमारे दर्द का इलाज नहीं हो सकता। हमारे दर्द का इलाज अगर हो सकता है तो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि हम कोशिश करें इस बात की कि हमारी ज़मीन के ऊपर जितना प्रेशर है वह कम हो, और वह सिर्फ इसी सूरत से हो सकता है कि अगर हम मुल्क के अन्दर इंडस्ट्री का एक जाल फैला दें। हमारे मुल्क के अन्दर एक ऐसी इंडस्ट्री हो, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। मेरा मतलब काटेज इंडस्ट्री से है। काटेज इंडस्ट्री की तरफ हमें तवज्जह देना है ताकि उसके जरिये से हम रीजनल किस्म की इंडस्ट्री बना सकें और उसके जरिये ज़मीन के ऊपर प्रेशर को हम दूर कर सकें। जनाबवाला, मुझे यह भी सुनकर इत्मीनान हुआ कि हमारी सेकेंड फाइव ईयर प्लान में सबसे ज्यादा तवज्जह इंडस्ट्री और ऐग्रीकल्चर पर दी जा रही है। सही है, ऐग्रीकल्चर को तो हम किसी वक्त भी भुला नहीं सकते, इसलिये कि वह तो हमारे देश का बैकबोन है और उस पर पिछले सालों में भी तवज्जह दी जाती रही है। लेकिन इंडस्ट्री बेशक एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ हमें बहुत खासी तवज्जह देनी है और इंडस्ट्री के साथ-साथ सिर्फ काटेज इंडस्ट्री ही देश की बीमारियों का वाहिद इलाज है। अगर हमने काटेज इंडस्ट्री को रीजनल तरीके पर फैलाने में और जापान की तरफ नजर रखते हुये वहां से मालूमात हासिल करके इस काम को आगे बढ़ाने में कामयाब हुये तो मैं समझता हूं कि आइन्दा ५ साल के अन्दर हमारी बहुत कुछ बहबूदी हो सकती है। मैं तो माननीय मंत्री से यह अर्ज़ करूंगा कि आप यहां से अपने कुछ लेजिस्लेचर्स और आफिसर्स को दूसरे मुल्कों में भेजें कि वे वहां जाकर उस मुल्क की इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करें।

अब वक्त कम है, लाल रोशनी हो गयी है, मुझे अपनी सीट पर अब बैठना पड़ेगा। एक दो बातें मैं तामील के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। दुनियां का कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां की तालीम उस मुल्क की ज़रूरतों के मुताबिक न हो! हमें तालीम को रिओरियंटेट करना है। हमें टेक्निकल और बेसिक एजूकेशन को आगे बढ़ाना है। हमें खासतौर पर महिलाओं के लिये टेक्निकल और बेसिक एजूकेशन आगे बढ़ाना है।

हमारी बहनें जो यहां बैठी हुयी हैं शायद वे मेरी इस बात की ताईद करेंगी। और हमें यह भी देखना है कि हम किस तरीके से प्रायोरिटी चीजों को दें? प्रायोरिटी बड़ी जरूरी चीज है, बगैर इसके काम नहीं चल सकेगा।

मेडिकल की बाबत में एक दो बातें कहूंगा। इस जमाने में जब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है तो हमारे नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स का काफी काम होना चाहिये। यहां रेडियम का कोई इन्तजाम नहीं है। हमको फीमेल डाक्टर्स, नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स नहीं मिलते। इसकी तरफ हमें खास तवज्जह करने की ज़रूरत है। चाहे इस सिलसिले में हमें पैसा ज्यादा खर्च करना पड़े, हमें उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ें, लेकिन हमें यह करना होगा। यह भी हो सकता है कि चूंकि फीमेल बहुत सी इस वजह से न आ सकती हों कि चूंकि वे फैमिली लाइफ रखती हैं और उनका तबादला होता है इसलिये आने के लिये तैयार न हों। तो मैं यहां तक कहूंगा कि अगर हमको नर्सेज़ और डाक्टरनियां नहीं मिलती हैं तो हमें उनकी सर्विसेज़ को नानट्रान्सफरेबिल बना देना चाहिये।

एक बात मैं और कह कर खत्म कर दूंगा, और वह यह कि इतनी बड़ी हमारी प्लानिंग हो रही है और हमने गल्ले और कपड़े के मसले को हल कर लिया है, लेकिन एक तीसरी चीज़ जो बहुत ज्यादा ज़रूरी है—मकान, उसका मसला हम अभी हल नहीं कर पाये। जो छोटे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, दरमियानी तबके के लोग हैं उनके पास मकान नहीं है। इसके लिये गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी योजना बनानी चाहिये और उसके जरिये से मकानों का इन्तजाम करना चाहिये। हमने तो यह बात उस वक्त भी कही थी कि जब हमारे यहां ट्रांसपोर्ट नेशलाइज़ हो रहा था। मैंने उस वक्त यह कहा था कि ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइज़ेशन बिलकुल सही है, लेकिन अगर प्रायोरिटी का मसला देखा जाय तो मैं इस बात को तरजीह दूंगा कि पहले हम मकानों के मसले को हल कर लें तब ट्रांसपोर्ट की तरफ कदम उठायें।

मैं समझता हूं कि मैंने जो चन्द बातें माननीय नियोजन मंत्री के सामने पेश की हैं उन पर वे गौर फरमायेंगे और साथ ही साथ उनकी इस तवज्जह और दिलचस्पी के लिये, जिससे उन्होंने इस महकमे के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)**—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान युग सर्वांगीण दृष्टिकोण से नियोजन का युग है, और इसी दृष्टिकोण से अगर आज हम इस प्रस्तुत विवाद पर विचार करते हैं तो यह सदन के इतिहास में सब से महत्वपूर्ण विवाद माना जा सकता है। हमारे सम्मुख विवाद के दो दृष्टिकोण हैं—प्रथम दृष्टिकोण तो यह है कि प्रथम पंचयवर्षीय योजना की प्रगति किस प्रकार हुई, और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि हमारी आने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सिद्धान्त क्या हैं और इस संबंध में हमारी नीति और योजना क्या हैं? मैं आपकी आज्ञा से प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर कुछ शब्द कहने का साहस करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसको "योजना" का शब्द देना बड़े बड़े आर्थिक जानकारों ने उचित नहीं समझा। श्री० टी० टी० कृष्णमचारी ने जब मद्रास कांग्रेस के लिये आर्टिकिल लिखा तो उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना को 'टेलर मेड बजट' माना है। आज जो सेन्ट्रल के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, उन्होंने यह शब्द इसके लिए इस्तेमाल किये हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना को आप लें तो आप देखेंगे कि यह ५१ से शुरू हुई बतलाई जाती है। लेकिन १९५१ के बजट में प्लानिंग का कोई जिक्र नहीं है। इसमें जिक्र है डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट स्कीम्स का। १९५२-५३ के बजट में एक लाइन लिख दी गई है कि योजना है, बाकी पता नहीं कि क्या योजना है, कैसी है? तीसरे साल में मालूम हुआ कि हमारी पंचवर्षीय योजना है वह काम कर रही है और मैंने बड़ी कोशिश की कि इसका शायद कोई ड्राफ्ट हो। लेकिन अभी तक पता नहीं कि वह क्या था? सिर्फ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इतना मालूम हो सका है कि पहले इसका खर्चा ८२ करोड़ का था और जैसे जैसे ग्रांट बढ़ती गई, योजना भी हमारी बढ़ती गई। असल में प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट विभिन्न विभागीय योजनाओं का एक समूह है और इस को प्रथम पंचवर्षीय योजना का नाम दे दिया गया है। अब इसकी प्रगति अवश्य हुई है, खर्चे में हुई है और विभिन्न निर्माण कार्य हुये हैं, उनमें प्रगति हुई है और कितनी प्रगति हुई है इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े नहीं है? अब मैं क्या कहूं, जो पुस्तिकाएं बांटी गयी हैं, तीन बांट गई हैं, और इन तीनों में विभिन्न आंकड़े हैं। मैं गुप्ता जी से कहूंगा कि या तो वह आंकड़ों का देना बन्द कर दें नहीं तो इस प्रकार के परस्पर विरोधी आंकड़े देना ठीक नहीं है। उनके आधार पर हम प्रगति को मान नहीं सकते हैं। मिसाल के लिये, जो रिपोर्ट १९५३ में बांटी गई उसमें टार्गेट फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन साढ़े ग्यारह लाख टन का रखा गया, लेकिन उसमें बाद को ९ लाख ८३ हजार टन कर दिया गया। टार्गेट घटाना ठीक नहीं है और इसका टार्गेट घट गया लेकिन खर्चा बढ़ा और उत्पादन घट गया। या फिर यह कहना चाहिये कि आपके आंकड़े सही नहीं हैं। इसी प्रकार से आप जूट के ले लीजिये। पहले आपका टार्गेट ५ लाख मन का था और बाद को उसे घटा दिया गया और आज आपकी रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि हमने जूट का उत्पादन बहुत बढ़ दिया है। यह समझ में नहीं आया कि पहले टार्गेट घटा दिया और अब कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ दिया? ५ लाख मन का जो टार्गेट था उसको घटा कर ३ लाख मन कर दिया गया और फिर भी कहा जाता है कि हमने ३·४ लाख मन पैदा कर दी है! इसी प्रकार रुई का है और इसमें कहा जाता है कि हमने १३,००० गांठे ज्यादा पैदा कीं। इसके संबंध में जो पहले का ड्राफ्ट है उसमें कहा गया है कि कपास के संबंध में उत्पादन स्टेशनरी रहा, यानी यहां पर शब्द "स्टेशनरी" प्रयुक्त हुआ है। इसके माने हैं कि उत्पादन न घटा और न बढ़ा लेकिन यहां पर कह दिया गया कि कपास की १३,००० गांठे ज्यादा पैदा कीं। इसी तरह से ऐनीमल हस्बैंडरी के १९५३ में ऐक्सपेंडीचर एक करोड़ ६३ लाख का था, वह घटकर ९९ लाख हो गया। तो किसी रिपोर्ट को पिछले तीन चार सालों की मिला लें, उसमें कोई हिसाब नजर नहीं आता कि क्या टार्गेट था और किस हिसाब से कितना खर्च होना था? एनीमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में तो चार बार खर्च करने की स्कीम बनाई गई और काटी गई। तो मैं इसको प्लान की संज्ञा नहीं देता। हां, यह मान सकता हूं कि जब सेन्टर से ग्रांट आई या कोई स्कीम आई या अपने यहां कोई स्कीम तैयार हो गई तो उस काम को जोर से करने लगे नहीं तो बस, कुछ काम नहीं हुआ। नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट आप लोगों ने देखी होगी, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है कि प्लान फ्लेक्सिबिल अवश्य होता है, लेकिन इतना लचीला नहीं होता कि उसकी सारी रूप रेखा ही बदल जाय। "Plan must not go out of points" (योजना विग्रथित न हो जाय।) यह नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट के शब्द हैं। लेकिन हमारे यहां प्रथम पंचवर्षीय योजना इतनी फ्लेक्सिबिल कर दी गई कि जिस की वजह से आप देखें कि हाउसिंग के संबंध में ९ करोड़ २३ लाख रुपये में से २ करोड़ ७० लाख केवल खर्च हुआ है, यानी एक चौथाई से कुछ अधिक। मेडिकल ऐण्ड पब्लिक हेल्थ में १४ करोड़ ७८ लाख एक्पेंडिचर में से इतना गिराने के बाद जो टोटल टार्गेट था, केवल ७ करोड़ १२ लाख रुपया खर्च हुआ है। इरीगेशन, पावर में भी ४१ करोड़ रुपया जो है वह अभी तक खर्च नहीं हुआ है! तो आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि टार्गेट्स को बराबर बदलने के बाद भी अभी तक हम रुपये को खर्च नहीं कर सके हैं और इसीलिये फाइव इयर प्लान की प्राग्रेस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि यू० पी० में केवल निर्धारित टार्गेट्स के एक्सपेंडिचर का केवल ५१ फीसदी खर्च किया जा सका है और बड़े बड़े प्लानिंग के एक्सपर्टस् को भी यह मानना पड़ा है कि जितना हमारे प्लान के संबंध में खर्च का ऐस्टीमेट था वह ओरिजिनल एस्टीमेट से अगल होने वाला नहीं है। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का पहला ड्राफ्ट था उतना ही खर्च होने वाला है। जितना हमने बाद को संशोधन किया उतना होने वाला नहीं है। तो यह तो रहा जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखना चाहता हूं।

कम्युनिटी प्रोजेक्टस् और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की काफी चर्चा है, और कुछ माने में वहां कार्य सराहनीय भी हुआ है। लेकिन आप देखें कि आखिर यह ब्लाक्स जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हुए हैं, उनकी कहानी भी अगर आप देखें तो कई जगह उनकी ह हालत है कि ब्लाक्स के हेडक्वार्टर्स भी नहीं बने हैं, और जितना खर्चा उनके संबंध में होना चाहिये था वह अभी तक नहीं हो पाया है! मैं, मिसाल के लिये, "कुरुक्षेत्र" एक अखबार है उसमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट में जो खर्च हुआ है वह दिया हुआ है, उसको पढ़ता हूं। अभी तक यू० पी० में सोशल एजूकेशन पर कुल १०० फीसदी खर्चा हो पाया है, केवल इस मद में। बाकी सारी मदों में बहुत कम खर्च हो पाया है, अंदाज से भी कम खर्च हो पाया है। जैसे हेल्थ और सेनीटेशन में केवल ४६ प्रतिशत, एजूकेशन में केवल ४७ प्रतिशत, ऐग्रीकल्चर एक्सटेंशन में केवल ५१ प्रतिशत खर्च हुआ है। आर्टस्, क्रैफ्ट्स, इंडस्ट्रीज में केवल ३३ प्रतिशत, कम्युनिकेशन में २९ फीसदी, इर.गेशन में, सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं में, केवल १६ प्रतिशत, रिक्लेमेशन में केवल ४ प्रतिशत खर्च हुआ है, बंजर भूमि को रिक्लेम करने में। तो इस तरह से इसका टोटल एवरेज जो है वह केवल ४७ प्रतिशत है। यह केवल यू० पी० का है, जो 'कुरुक्षेत्र' अखबार से कम्युनिटी प्रोजेक्ट की फीगर ली गई है। तो ५३ फीसदी जो रुपया खर्च बताया जाता है वह फर्स्ट फाइवइयर प्लान के अनुसार भी खर्च नहीं किया जा सका है। और फिर अगर माननीय गुलजारी लाल नन्दा ज: के स्टेटमेंट को देखा जाय तो स्वतः कहा है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के जो टार्गेट्स हैं क्या यह तीन साल के अंदर पूरे होने वाले हैं? नहीं होने वाले हैं। स्वतः कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के संबंध में जो आर्गेनाइजेशन बनाया गय है उसने भी यही कहा है कि तीन साल के अंदर जो हमने उद्देश्य बनाया है वह पूरा होने वाला नहीं है। यह ६ साल तक चलेगा या शायद ज्यादा चलेगा। लेकिन बजट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि सन् १९६१ तक सारे दे में एन० ई० एस० ब्लाक खोल दिये जायेंगे लेकिन रुपया जो उ: के लिये खर्च होने वाला है उसके लिये पता नहीं है कि वह होने वाला है या नहीं? इसलिये प्रोग्राम के मुताबिक काम हो सकेगा, इसमें मुझे संदेह मालूम होता है। मैं गोरखपुर की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि गोरखपुर में कम्युनिटी प्रोजेक्ट चलाने वाले लोगों को अपने लक्ष्य में एक बटा तीन से ज्यादा कमी करनी पड़ी। जितना लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था उससे एक बटा तीन लक्ष्य कम करना पड़ा। यह बात जरूर है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट और नेशनल एक्सटेंशन स्कीम में कुछ ए० डी० ओ० आदि अफसर जरूर बन गये औ: उसमें कुछ लोगों की नौकर: भी मिल गयी, लेकिन ज: उसका उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ।

पर कैपिटा इन्कम का बहुत चर्चा किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया तो उसमें उन्होंने हमारे यहां की पर कैपिटा इन्कम का प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १२ फीसदी बढ़ना बतलाया है। हमारी राष्ट्रीय आमदनी १२ फीसदी बढ़ी है। लेकिन मैंने देखा तो मालूम हुआ कि वह ५·३ से ज्यादा नहीं बढ़ी है। उसको कहा गया कि वह १२ फीसदी बढ़ी बजाय ५.३ के। यह कैसे बढ़ी है इसको भी देखें देहातों की पर कैपिटा इन्कम इतनी नहीं है जितनी कि सन् १९४७ में थी। सन् ४७ में पर कैपिटा इन्कम देहात की १९४·१ थी जो घटकर अ १९१·८ रह गयी है। सन् १९४७ के मकाबले में हमारे देहाती क्षेत्र की उत्तर प्रदेश में पर-कैपिटा इनकम घट गयी। जो आंकड़े पर-कैपिटा इन्कम के माननीय मंत्री जी ने दिए हैं कि हमारी पर-कैपिटा इनकम इतनी थी यह भी बिलकुल गलत है। यह परस्पर विरोधी हैं। इसके लिये वह एक कमेटी नियुक्त करें जो इन आंकड़ों की जांच करे। मैं इन आंकड़ों को पेश करने के लिये तैयार हूं। वह कहते हैं कि सन् १९४६–४७ में २१८·१ पर कैपिटा इन्कम थी, और अब वह २२३·६ हो गयी। जिन्होंने आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिये हैं वह गलत है और परस्पर विरोधी हैं। किसको सही मानें? इतना तो माननीय मंत्री जी भी मानते हैं कि इतना अवश्य है कि देहातों में पर कैपिटा इन्कम घटी है। शहर में कुछ बढ़ी है। किसकी बढ़ी है? मध्यम वर्ग की शहर के अन्दर भी नहीं बढ़ी है। कुछ व्यापारियों की बढ़ी है या जो कुछ पूंजीपति हैं उनकी आमदनी बढ़ी है, या

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

निम्न लोगों की बढ़ी है, इसको माननीय मंत्री जी ज्यादा जानते हैं कि किसकी बढ़ी है ? वह बता सकते हैं । लेकिन शहरी क्षेत्र में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो मेहनत करने वाले वर्ग है उनकी पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ी है । यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था उसके सिद्धान्त के बारे में जो बातें थी वह मैंने आपकी आज्ञा से प्रस्तुत की । इस सम्बन्ध में एक बात माननीय मंत्री गुप्ता जी से जानना चाहता हूं कि वह हमको यह बतायें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, या उसके पहले जितनी प्रगति हुई है उसके आधार पर एवरेज एक्सपेक्टेशन आफ लाइफ कितनी बढ़ी है ? यदि पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है और लोगों के रहन-सहन के स्तर में बढ़ोतरी हुई है तो क्या मनुष्य की औसत उमर जो मानी जाती है क्या वह भी कुछ बढ़ी है ? अगर आंकड़े देखे जायं तो इससे साबित यह होता है कि यू० पी० में मार्टेलिटी जो थी, यानी जितना एवरेज यू० पी० में सन् ४६-४७ में था उतना आज भी है या नहीं। बच्चों की मृत्यु की संख्या तो पहले के मुकाबले में बढ़ी है । सन् १९४९ में १ लाख २९ हजार बच्चे मरे थे और सन् ५३ में २ लाख के करीब बच्चे मरे । तो चिलड्रेन मार्टेलिटी उत्तर प्रदेश में बढ़ गयी । नेशनल प्लानिंग कमेटी में प्लानिंग के प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा आधार यह माना गया है कि मनुष्य की एवरेज एक्सपेक्टेशन आफ लाइफ कितना बढ़ता है । इसका दृष्टिकोण हम यह नहीं मान सकते हैं कि इतने समय में कोई चमत्कार हो जाय लेकिन कुछ आधा या दो एक परसेन्ट कुछ तो प्रगति होनी ही चाहिये वह प्रगति हमको दृष्टिगोचर नहीं हुई है ।

अब समय की कमी के कारण मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा । अब मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना को लेता हूं और शायद इसमें प्रथम पंचवर्षीय का भी जिक्र आ जाये तो मुझे आप क्षमा करेंगे । अब मैं इसके सिद्धान्तों की ओर आना चाहता हूं । ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस दिन माननीय मंत्री जी का प्रोपोज्ड ड्राफ्ट मंजूर हुआ उस दिन एक भारी दुर्घटना घट गयी । उसके मानी यही कि सारे राज्य की प्लानिंग उस दिन अस्त-व्यस्त हो गयी । महीनों से जो आशा बंधी हुई थी, उस पर पानी फिर गया । उसी का नतीजा यह मालूम होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है वह भी अस्त-व्यस्त है और उसमें कोई स्पष्ट सिद्धान्त मालूम नहीं होता है । इसी लिये कल माननीय गेंदा सिंह जी ने इसको "शेपलेस प्लान" कहा था । इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता कि इसके द्वारा समाज व्यवस्था को प्रायोरिटी दी गयी है, न यह स्पष्ट है कि इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी गयी है, न किसी और ही चीज की प्रायोरिटी इसमें दिखायी देती है । फिर क्या आप सब चीजों को इसमें प्रायोरिटी दे रहे हैं ? प्लानिंग में सब चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती । दूसरी बात यह है कि पहले २४९ करोड़ की योजना स्वीकृत हुई, फिर २६० करोड़ हो गये, फिर कुछ और मांगें भी मंजूर हुई और उनकी जानकारी समाचार-पत्रों के आधार पर हमें हुई कि वह ३२५ करोड़ हो गयी, और अन्त में होते-होते ३३८ करोड़ हो गयी । आफिशियल तौर पर हमारे सामने कोई सही फीगर नहीं रक्खी गयी । अब कौन सी फिगर को आधार मान कर चला जाय ? किस आधार पर निर्धारण करें यह इससे बिलकुल स्पष्ट नहीं है ?

जहां तक प्लानिंग फ्रेम का ताल्लुक है वह एक ही है, उसको महालानोबिस साहब ने बनाया था । अब आप अगर उस प्लानफ्रेम को देखें तो आपको उसकी शब्दावली बड़ी सुन्दर मालूम होती है लेकिन उसमें तथ्य कहां है ?

श्री सुल्तान आलम खां---प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट में तो मार्टेलिटी की रेट घट गयी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह पूरे भारत के लिये है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं । तो इस महालानोबिस प्लान फ्रेम में यह कहा गया है कि हमें बेकारी को १० साल में दूर करना चाहिये, यानी हमें १ करोड़ १० लाख आदमियों के लिए रोजगार मुहैया करना है ।

इस हिसाब से अगर हम उत्तर प्रदेश के लिये देखें तो हमें मालूम होगा कि उस अनुपात से हमें १८ लाख लोगों को रोजगार देना है। और इन १८ लाख लोगों को ही रोजगार देने के लिये ही हमें प्लान बनाना चाहिये। लेकिन इस योजना को देखने से ऐसा मुझे नहीं लगता। महालानोबिस प्लान फ्रेम को तो मंजूर किया गया लेकिन उसके आंकड़ों को मंजूर नहीं किया गया। मैंने अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ा उन्होंने कहा कि हम उसके प्लान फ्रेम और टार्गेट को तो मंजूर करते हैं लेकिन स्टेटिस्टिक्स को मंजूर नहीं करेंगे। लक्ष्य को तो मंजूर करते हैं लेकिन स्टेटिस्टिक्स को मंजूर नहीं करते। उस प्लान फ्रेम में १ करोड़ १० लाख लोगों को रोजगार दिलाने की बात कही गयी है। उसमें यू० पी० का १/६ भाग होना चाहिये यानी प्रोपोर्शन से हमें १८ लाख लोगों को रोजगार देना होगा। यू० पी० में माननीय मंत्री जी जानते हैं कि अन्डर एम्प्लायमेंट है। देहात के डेढ़ करोड़ व्यक्ति या किसान ऐसे हैं जिनको आधा रोजगार ही मिला हुआ है, वे अन्डर एम्प्लायड हैं। इसके अतिरिक्त ७-८ लाख लोग ऐसे हैं जिनको देहात में बिलकुल रोजगार है ही नहीं। अब फिर यह सब १० साल के अन्दर किस प्रकार होने वाला है, मेरी समझ में नहीं आता? मैं पूछना चाहता हूं उसकी रूप-रेखा क्या है? कहा यह गया कि बड़े बड़े उद्योग धंधों से प्रोड्यूसर गुड्स तैयार किये जायेंगे और कंज्यूमर गुड्स स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से तैयार होंगे। लेकिन अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि हैवी इंडस्ट्रीज कहां होंगी? कहा जाता है कि वह केन्द्र से निश्चित होंगी। मैं यह चाहता था कि यह डिबेट तब होती जब केन्द्र इस बात को तय कर देता, ताकि हमें पता चल जाता कि हमारे यहां कौन-कौन बड़े उद्योग हो रहे हैं और कहां-कहां वे होंगे? हम ही क्या, अभी तो माननीय मंत्री जी भी इसको नहीं जानते कि बड़े-बड़े उद्योग-धंधे कहां-कहां खोले जायेंगे। अतः इससे यह भी स्पष्ट नहीं है कि बड़े उद्योग धंधे कहां खोले जायेंगे और छोटे-छोटे उद्योग धंधे कहां खोले जायेंगे? कहा यह जाता है कि ऐतिहासिक आवश्यकता हो गयी है कि एक तरफ तो हम प्रोड्यूसर गुड्स बेसिक इंडस्ट्रीज के द्वारा पैदा करें औ कंज्यूमर्स गुड्स काटेज इंडस्ट्रीज के द्वारा पैदा करें, लेकिन अभी तक संतुलन करने की कोशिश नहीं की गयी है कि किन सेक्टर्स को हम चाहते हैं कि ये प्रोड्यूसर गुड्स के जरिये या कैपिटल इंडस्ट्रीज के जरिये करें? बड़ी इंडस्ट्रीज इसके जरिये करें और छोटी इंस्ट्रीज इसके जरिये करें यह बिलकुल स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इसलिये इस सिद्धान्त के पीछे यह नहीं है कि १० करोड़ रुपया हमने बड़ी इंडस्ट्रीज के लिये रख दिया या १० करोड़ छोटी इंडस्ट्रीज के लिये रख दिया। हमें एक निश्चित योजना निर्धारित करनी है उसके मुताबिक सेक्टर्स पर अपना कंट्रोल करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि हम प्राइवेट सेक्टर पर भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर कंट्रोल करने के लिये सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के लिये साधन जुटाने का क्या सुझाव दिया है, यह स्पष्ट नहीं है? माननीय मंत्री जी अवश्य मानेंगे कि जब तक हम साधनों का समाजीकरण नहीं करते तब तक हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को एचीव नहीं कर सकते हैं। रुपया कहां से आवे, इसकी बात जो बार-बार की जाती है, रुपया लेने की चेष्टा तभी हो सकती है जब साधनों का भी समाजीकरण करें। साधन के साथ ही मिक्स्ड इकोनोमी के सिद्धान्त को लेकर हम समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर सकते। जब आप नये उत्पादनों का समाजीकरण कर रहे हैं तो साधनों को भी समाजवादी कीजिये, पूंजी को समाजवादी करने से ही हम समाज को समाजवादी बना सकेंगे। यह सच है कि पूंजीवादी साधनों से जो योजना बनेगी उससे समाजवादी सामज की रचना नहीं हो सकती। तो इस पहलू पर भी हमको सोचना है, और इसीलिये हमको कहना पड़ता है कि चाहे प्रोफेसर महालानोबिज प्लान हो या कोई प्रोफेसर प्लान हो, वह प्लान कामयाब होने वाला नहीं है जब तक कि यह सिद्धान्त बदलता नहीं है, जब तक दृष्टिकोण बदलता नहीं है, तो यह तो इस योजना की बात रही।

जहां पर सेकेंड पंचवर्षीय योजना का सवाल है, इसमें आप यह देखेंगे कि जहां यह उद्देश्य घोषित कर दिया गया है कि हम बिजली के उत्पादन को दुगुना करेंगे यानी यह

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आब्जेक्टिव है सेकेंड प्लान का, लेकिन जो हमारी यह योजना है उसमें इस बात का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि ५ लाख किलोवाट बिजली हम उत्तर प्रदेश को दे सकेंगे। बल्कि दुगुने के बजाय २/३ की ही उम्मीद है। सीमेंट के लिये प्लान में है कि दुगुना सीमेंट पैदा किया जायगा। इसका मतलब कि साढ़े ४ लाख टन जब सीमेंट होगा तब यहां की आवश्यकता पूरी होगी, लेकिन इस प्लान के जरिये दो लाख पचास हजार टन सीमेंट की व्यवस्था ही की गयी है। इसी तरह से फ्रेम्ड प्लान में शिक्षा के लिये कहा गया है कि जो रुपया रखा गया है उसमें से ७५ फीसदी जो व्यय किया जायगा वह टीचर्स को अधिक पे आदि देने में तथा एजूकेशन के रिसर्च आदि के लिये है। शिक्षा के रिसर्च पर, हायर एजूकेशन पर अधिक खर्च होगा यह कहा गया है, कि लेकिन हमारे प्यान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार केवल २० फीसदी ही खर्च किया जायगा। आबजेक्टिव है ७५ फीसदी लेकिन खर्च के लिये २० फीसदी ही रखा गया है। हमारे हिन्दुस्तान के संविधान में स्टेट्स के लिये जो डाइरेक्टिव दिया गया है उसके अनुसार १० साल में कम्पल्सरी फ्री प्राइमरी एजूकेशन हो जाना चाहिये। अब आप समझें कि हमारा संविधान सन् १९५१ में स्वीकृत हुआ और सन् ६१ तक कम्पल्सरी प्राइमरी फ्री एजूकेशन कर देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि १०० फीसदी के लिये क्या कहा जाय, बीस या दस फीसदी के लिये भी गुंजाइश है कि वे किसी भी जिले में अनिवार्य प्राइमरी निःशुल्क शिक्षा कर दें? इस तरह से आप जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा करने जा रहे हैं वहां पर विधान की अवहेलना होती है। इसी तरह से सड़कों के सम्बन्ध में प्लान फ्रेम में जो बात थी उसके संबंध में हमारी सरकार केवल मांग करती रह गई। पहले नागपुर में जो फीच इंजीनियर्स कांफ्रेंस हुई थी, और वहां जो स्टार ग्रिड फार्मूला बनाया गया था, और जिसके अनुसार कहा गया था कि इस स्टेट में २६ हजार मील सड़कें बनना हैं और वह प्रोग्राम सन् ४७ से यहां लागू किया गया था, और उसके तीन फेज यहां बनाए गए थे। जो पहला फेज था वह सन् ४९ में रुक गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितनी सड़कें बनीं समें भी पहला फेज पूरा नहीं हुआ और २० प्रतिशत सड़कें अभी बनना बाकी हैं। जो हमारा महालानोबिस प्लान फ्रेम है उसमें कहा गया था कि हर राज्य को अपनी सड़कों का ५० प्रतिशत विस्तार करना होगा। अगर हम उनका विस्तार करने लगें और उस दृष्टिकोण से देखें तो हमारी उन आवश्यकताओं को भी यह पूरा नहीं करती।

श्रीमन्, कृपया आप मुझे आधा घंटा और देने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपको आधा घंटा दिया है, केवल २ मिनट बाकी रह गए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—थोड़ा सा समय और दिया जाता...

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको अधिक से अधिक २ मिनट और दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा दुर्भाग्य है कि समय की कमी के कारण जो महत्वपूर्ण बातें मैं यहां कहना चाहता था वह कहने से रही जा रही हैं। इसी प्रकार सिंचाई के सम्बन्ध में भी प्लान फ्रेम के अनुसार ४३ प्रतिशत व्यवस्था होनी चाहिये थी। लेकिन हमारी इस योजना के अनुसार केवल ३० प्रतिशत सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि हमारे प्लान फ्रेम में और जो राज्य की यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें, सके सारे उद्देश्य में और उसको प्रयोग करने के तरीकों में बड़ा भारी विरोधाभास है। या तो स्पष्ट कहा जाय कि हमने प्लान फ्रेम स्वीकार नहीं किया है और अगर किया है और उसके उद्देश्य को माना है तो हमें अपनी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उस आधार पर ढालना होगा और बड़े-बड़े उद्योग धंधों का प्रतिबन्ध करना होगा, आज हमारे प्रदेश में जो डेढ लाख हैन्डलूम बेकार पड़े हैं और जो हमारे उद्योग मृतप्रायः पड़े हुए हैं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए एक क्रांन्तिकारी प्रयास करना होगा। अगर आज हमारी योजना में जनता की भावनायें हैं उसकी इच्छाओं का समावेश

है उसकी प्रथम आवश्यकताओं की पूर्ति की बात है उस पर सब लोग विचार कर सकते हैं कि योजना को किस तरह से सफल बनाया जाय ? लेकिन अगर यह चीजें उसमें नहीं है तो वह योजना निष्प्राण रहती है, आंकड़ों का एक जालमात्र रहती है, और वह योजना केवल एक ग्लोरिफाइड बजट का रूप धारण करके रह जाती है, और इस तरह की योजना जनजीवन को अनुप्राणित नहीं कर सकती। इसलिए मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, और इस सरकार से और केन्द्रीय सरकार दोनों से कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश की जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझ कर, और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों के निर्माण के लिए और गृह उद्योगों के निर्माण के लिए जो धन दिया गया है और प्लान फ्रेम का आब्जेक्टिव पूरा करने के लिए धन दिया जा रहा है वह बहुत कम है, और वह प्लान फ्रेम की आवश्यकताओं को देखते हुए और दूसरी योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि धन की मात्रा पर्याप्त रूप से बढ़ाई जाय।

पर कैपिटा इन्कम के बारे में कहा गया कि वह २५ प्रतिशत बढ़ने वाली है, लेकिन जब कि ८८ करोड़ के बजट में वह ५.३ प्रतिशत बढ़ी तो साढ़े ३ अरब के बजट में . . .

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—थोड़ा सा समय और दिया जाय। मैं यह कह रहा था कि . . . .

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई स्पीच हो रही है तो क्या माननीय सदस्यगण खड़े रह सकते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस तरह से तो मैं अब समाप्त करता हूं।

***श्री पद्मनाथ सिंह** (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष की प्लानिंग और डेमाक्रेसी का जो परीक्षण हो रहा है पूरा संसार आज उसको उत्सुकता की दृष्टि से देख रहा है। बीसवीं शताब्दी में नियोजन का एक इतिहास है। सबसे पहले रूस ने इस शताब्दी के प्रथम दशम के अन्तिम वर्षों में प्लानिंग का परीक्षण करना आरम्भ किया था। रूस की एक योजना थी, और यह हमें मालूम है कि सोशलिस्टिक सोसाइटी के अन्तर्गत उसने एक योजना बनाई जो संसार के सामने एक रूप में उपस्थित है। उसके पश्चात् जब रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसीडेंट हुये तो उन्होंने न्यू डील पालिसी के अनुसार अमेरिका के विकास के हेतु एक योजना बनाई थी। अमेरिका और रूस की योजनाओं में दो विशेष अन्तर थे। एक तो जहां तक न्यू डील पालिसी बनी वह कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की योजना थी। उसमें केवल समाज और पूरे देश को डेवलप करने की स्कीम थी। उसमें नदियां भी, रिवर वैलीज भी, इंडस्ट्रीज भी, एजूकेशन और बहुत सी बातें डेवलप की गयी। लेकिन वह तो प्लानिंग नहीं थी, वह तो केवल डेवलप करने की स्कीम थी। रूस में जो योजना बनी वह प्लानिंग की योजना थी। आज इन्हीं दो बातों के अन्तर्गत भारत में जो योजना बनाई गई है उसको देखना है कि वह प्लानिंग की है या केवल डेवलपमेंट की है ? माननीय नारायणदत्त जी ने जो स्पीच दी उसे मैं प्लानिंग की स्पीच नहीं कह सकता, उसे बजट स्पीच मानता हूं, क्योंकि प्लानिंग की स्पीच में प्लानिंग की एनेलसिस में हम कुछ आंकड़ों को देख करके ही यह जस्टीफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश का नियोजन प्लानिंग के रूप में जा रहा है या नहीं ? वास्तव में हम आंकड़ों से इस बात का कोई निर्णय नहीं कर सकते कि कितनी देश की उन्नति हुई है ?

स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में पानिक्कर साहब ने उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जो आंकड़े अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किये हैं उसके हिसाब से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है लेकिन केवल इन पर ही हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में प्लानिंग है या नहीं। प्लानिंग और डेवलपमेंट में एक विशेष अन्तर है। देखना यह है कि हमने जो विशेष रूप दिया है प्लानिंग का, उत्तर प्रदेश या सारे देश के बारे में वह प्लानिंग के अन्तर्गत है या नहीं? हमें ध्यान रखना है कि यह हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आयी है क्या वह नियोजन का रूप है? बहुत कुछ तो वह केवल डेवलपमेंट से सम्बन्धित है, उसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। इस ऐतिहासिक समय में हमारे देश में जो प्लानिंग की योजना बनी है वह कई विभिन्नताओं पर बनी है। हमारा देश ऐसे ऐतिहासिक समय से गुजरा है जिसमें न तो हमारे मस्तिष्क, न हमारा अर्थ और न हमारा समाज एक नियोजित रूप में था। वास्तव में हमारे मनों में बहुत सी परेशानियां थीं, अर्थ के बहुत से संकट थे, और हमारा समाज बहुत सी परेशानियों से गुजरा है। वैसी हालत में हम केवल एक बात कर सकते हैं कि अपने देश में और अपने प्रदेश में एक ऐसी स्थिति ला दें जहां हम प्लान के कार्य को सहायता पहुंचाते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना केवल हमारी योजना को अच्छी बनाने के लिये ही थी और जो भी कार्य डेवलपमेंट के हुये हैं उसने हमें एक अनुभव दिया है कि जिसके कारण हमने एक ऐसी परिस्थिति पैदा करने के अनुकूल बनाया है जिसमें सेकेन्ड फाईव ईयर प्लान का रियल रूप बन सके। जब मैं फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की बात कहता हूं तो वह डेवलपमेंट की जो स्कीम रही है उसमें हमने प्रदेश को डेवलप किया है लेकिन उसमें कोई प्लानिंग सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के दृष्टिकोण से नहीं हुई है। मैं बिल्कुल यह नहीं कहना चाहता कि हमने बिल्कुल किसी सिद्धान्त पर इसे नहीं बनाया है और एक ऊबड़-खाबड़ स्कीम बना दी है, ऐसा नहीं था। जो कांग्रेस का शासन है वह कांग्रेस के सिद्धान्तों के अनुसार चलने की कोशिश करता है। मद्रास के अवाडी कांग्रेस सेशन ने उसकी रूपरेखा तै कर दी थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सब से पहला ध्यान हमारे देश में कृषि को और दिया गया है। हमारे प्रदेश ने जमींदारी एबोलीशन के साथ-साथ एक बड़ी भारी क्रान्ति की है लेकिन उस क्रान्ति में प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी रह गई। केवल इंटरमीडियरीज को हमारे प्रदेश के कानून ने दूर किया लेकिन देश में खेती प्लांड तरीके पर हो इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की। जितने खेतिहर हैं उन्होंने इस दृष्टिकोण से खेती नहीं की और न सरकार ने कोई व्यवस्था की कि खेती इस दृष्टिकोण से की जाय, इतना अनाज उत्पन्न हो, और इस दृष्टिकोण से उत्पन्न हो, और हमारे देश में और प्रदेश में उसका उत्पादन इतना हो और इस प्रकार इतना वितरण हो! मैं उदाहरण के लिये दो बातें पेश करना चाहता हूं। माननीय सदस्य राधा-मोहन सिंह ने सीलिंग फिक्स करने के सम्बन्ध में विरोध में बड़ी जबरदस्त दलील यह दे डाली कि हमारे प्रदेश में यह संभव नहीं है। तो एक तो आल इंडिया कांग्रेस सेशन अवाडी के सिद्धान्तों के प्रतिकूल यह भाषण हुआ, और प्लानिंग कमीशन ने जो निश्चय कर लिया है उसके विरोध में भी वह भाषण है। सीलिंग अगर निश्चित नहीं करते हैं तो परिस्थिति क्या होगी? एक तरफ तो एक हजार एकड़ लैण्ड है, दूसरी तरफ एक-एक या डेढ़ एकड़ लैंड है। १ हजार एकड़ लैंड में अगर ट्रेक्टर से खेती की जाती है तो सरकार की तरफ से ट्रेक्टर की मरम्मत आदि के लिये, उसके पुर्जे सप्लाई करने के लिये या उसे रेगुलेट करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और वह अपनी जगह पर प्रतिक्षण क्षीण होता जा रहा है। फिर एक हजार एकड़ में एक आदमी अच्छी तरह से खेती नहीं कर सकता, एक आदमी के लिये उसका कंट्रोल करना गैर-मुमकिन है, वह कर नहीं पाता और न कर सकेगा। दूसरी तरफ जिनके पास एक या डेढ़ एकड़ लैंड हैं

उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, साधन नहीं हैं, पूंजी नहीं है और न सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि उनको इतना साधन सम्पन्न बना दे, चाहे कोआपरेटिव से या बैंक से, ताकि एक व्यवस्थित ढंग से वे खेती की उन्नति कर सकें। हमने इंटरमीडियरीज को जरूर एबोलिश कर दिया लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की है केवल उत्पादन के दृष्टिकोण से खेती की जा सके। जिनके पास ज्यादा जमीन है वे परेशान हैं कि वह बनी रहे और जिनके पास कम है वे असुविधा के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह चीज लैक करती है—जो उसकी विशेषता है, जो मुख्यता है—या जिसे प्लानिंग कहना चाहिये। मैं जानता हूं कि सरकार इस बात से बेबारा नहीं है। सरकार के दृष्टिकोण में यह बात है लेकिन दुःख तब होता है जो नन्दा साहब का एक नोट है सेकेंड फाइवईयर प्लान की रूपरेखा के बारे में उसमें इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं है, सीधा सा सिद्धान्त है कि सीलिंग फिक्स करनी चाहिय। वह सिद्धान्त कब लागू होगा, किस रूप में लागू होगा? एक केवल पायस विश की तरह हमने इस सिद्धान्त को मान लिया है लेकिन उसे इम्पलीमेंट करने के बारे में न कोई उपाय है, न कोई इशारा मिलता है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। मैंने जैसा निवेदन किया प्रारम्भ में प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद मद्रास सरकार ने इस बात को महसूस किया कि एक दिशा की ओर हमको देश को ले जाना है और उसी सिद्धान्त के अनुसार हमें देश की प्लानिंग करनी है। और इसीलिये अवाडी में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात कही गई और कहा गया कि हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया जायगा। हैवी इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में सरकार ने, प्लानिंग कमीशन ने, और प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की घोषणा की कि इंडस्ट्रीज स्टेट ओंड या स्टेट कंट्रोल होंगी। लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद, चाहे जिस तरह से भी एक कम्प्रोमाइज हो गया, और वह यह हुआ कि प्राइवेट सेक्टर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा। और आज मैंने इसको माननीय मंत्री जी के भाषण में भी देखा कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ, उद्योगपतियों की तरफ सरकार का ध्यान कुछ विशष जाने लगा है। परिणाम यह होगा कि जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में भी व लोग जो कि योजनाओं से सरकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुतों ने रुपये लिए और उसको काटेज इंडस्ट्रीज में नहीं लगाया, किसी दूसरे पब्लिक यूटिलिटी में नहीं लगाया, बल्कि अपनी पर्सनल यूटिलिटी में लगा कर खत्म कर दिया। उसी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर में सरकार का रुपया लगगा, सरकार का ध्यान लगेगा वह एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर देगा जो कि प्लानिंग और प्राफिटियरिंग में एक कम्प्रोमाइज की गुंजायश पैदा कर देगा। और अगर प्लानिंग और प्राफिटियरिंग में कम्प्रोमाइज हो गयी तो कोई प्लानिंग नहीं हो सकती और न सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की ही बात हो सकती है। यह विशेष परिस्थिति प्रत्येक समाज में रहती है, विशेष कर ट्रांजिटरो पीरियड में, हमारे देश में, हमारे देश में ही नहीं पूरे संसार में और प्रत्येक युग में प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में एक प्रतिस्पर्धा रहा करती है। अगर सरकार ने बिल्कुल निश्चित रूप से और दृढ़ हो करके एक निश्चित रेजोल्यूशन बना करके प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एक ऐसा फर्क नहीं दिया तो यह प्रतिस्पर्धा इस रूप में बढ़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर पर हावी हो जायगा। मैं यह नहीं कहता कि प्राइवेट सेक्टर न रहे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का एक पूरक मात्र है तो ठीक है। अगर इस दिशा में प्लानिंग का संचालन किया जाय तो हमारे देश में प्लानिंग का कार्य आगे बढ़ सकता है और पूरा हो सकता है। अन्यथा वह उसको इतना दूषित बना देगी कि हमें स्वयं बचना पड़ेगा।

मैं एक दूसरी दिशा में भी देखता हूं कि हमारी प्लानिंग में एक बड़ी जबरदस्त कमी है, मैंने यह नन्दा साहब के नोट को देखा। इसमें हमारी आबादी के बारे में आंकड़े

[श्री पद्मनाथ सिंह]

दिये गये हैं। १९७१ में उनके हिसाब से ४५ करोड़ भारत की आबादी हो जायगी और १९८१ में ५१ करोड़ हो जायगी। उस नोट में एक ही बात कही गयी है कि हमारे देश में जो आबादी ४५ करोड़ होगी वह १९८१ में ५१ करोड़ हो जायगी तो उस आबादी को कैसे खिलायेंगे? उत्पादन पर उन्होंने केवल ध्यान दिया है कि इस हिसाब से उत्पादन किये जायं। बहुत सी बातें करनी हैं, बहुत से साधन इकट्ठे करने हैं, ताकि इतने लोगों को खिला सकें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी और सरकार से कि इस दृष्टिकोण से न प्लानिंग हो सकती है और न हम खिला सकते हैं। जिस हिसाब से जन संख्या बढ़ती है उस हिसाब से उत्पादन किसी भी विज्ञान के रूप से नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इस पूरी प्लान में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि बढ़ती हुई आबादी को हम कैसे रोकें? फैमिली प्लानिंग की जो योजनाएं हमारे देश में बनायी गयी हैं वे ड्रेसिंग टेबिल की योजनाएं हैं। वे कुछ परिवारों और शहरों तक सीमित हैं। जहां पर कि कुछ बहुत ही कल्चर्ड और डेवलप्ड फैमिलीज ही उसका फायदा उठाती हैं। लेकिन उन गांवों और गांवों के उन हिस्सों में जहां आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, और बढ़ कर पूरी डेमोक्रेसी को भी खतरे में डाल देती है और हमारे पूरे जीवन को खतरे में डाल देती है, वहां पर उसकी व्यवस्था नहीं की गयी। तो न हमारी प्लानिंग कामयाब हो सकेगी, न हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि बढ़ती हुई आबादी इतनी खतरनाक है जो कि समस्त देश और संसार भर की पूंजी खाकर भी नहीं संतुष्ट हो सकती है और न पूंजी इतनी बढ़ सकती है। मैं जोर देकर इस पर कहूंगा कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर न मैं केवल इस सरकार से बल्कि इस सरकार के द्वारा भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसी बात है जिसकी तरफ अगर प्लानिंग में ध्यान नहीं दिया गया तो न केवल यह कि हमारी प्लानिंग अधूरी रह जायगी बल्कि खतरनाक भी हो जायगी। एक दूसरी दिशा की तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, बढ़ती हुई आबादी के सम्बन्ध में। हमारे इस प्रदेश में और हमारे भारतवर्ष में कुछ ऐसे पिछड़े हुए हिस्से हैं जहां कि आबादी बढ़ी अधिक है, उत्पादन कम। प्लानिंग में इस बात की भी गुंजायश होनी चाहिये और हो सकता है कि जहां आबादी ज्यादा हो, और जहां कम हैं लेकिन उत्पादन के साधन अधिक हैं वहां से पापुलेशन शिफ्ट करने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। मैं पूर्वी जिलों की बात जानता हूं उत्तर प्रदेश के, जहां कि जनसंख्या न केवल ज्यादा है बहुत तेजी से ज्यादा होती जा रही है और जीवन के साधन बहुत ही कम हैं। तो सरकार चाहे वहां पर जितने कर्ज चला दे यह परेशानी सरकार की प्रतिवर्ष रहेगी, और तकावी के रूप में या कर्ज या दान के रूप में उसे प्रतिवर्ष लाखों रुपया व्यय करना पड़ेगा। तो फिर इस बात का हल निकालने के लिये सरकार को जमींन को जरखेज बनाने में इस बात की व्यवस्था पर जरूर सोचना पड़ेगा कि बढ़ती हुई संख्या को कैसे कम किया जाय और शिफ्ट किया जाय? चाहे उसे शिफ्ट करने में निर्दयता करनी पड़े लेकिन अगर ऐसी निर्दयता नहीं करेगी तो मेरा विश्वास है कि प्रत्येक प्रयत्न करने पर भी, और प्लानिंग की सम्पूर्ण योजनायें जो संसार के अनुभव में हैं और हमारे अनुभव में हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी अनुभव से लाभ उठा सकती हैं फिर भी हमारी समस्यायें हल नहीं कर सकते हैं।

मैं एक तीसरी बात कहना चाहता हूं और यह बात कई बार माननीय राधामोहन सिंह जी और बहुगुणा जी ने कही। वह शिक्षा के सम्बन्ध में है। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई थी और आज जब दूसरी योजना की रूप-रेखा प्रस्तुत की जा रही है, इस बात का कोई भी इंडीकेशन नहीं है हमारे सामने कि शिक्षा के सम्बन्ध में आज जो अराजकता की परिस्थिति है वह परिस्थिति दूर हो सकेगी। आज हमारे देश के प्रधान मंत्री कहते फिरते हैं कि हमको बी० ए० और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं चाहिये, बल्कि

हम चाहते हैं ओवरसीयर्स, इंजीनियर्स। लेकिन हमारा दोष क्या है ? दोष तो उनका है जिन्होंने हमारे कालेजों को यूनिवर्सिटी की शिक्षा पद्धति को वैसा ही छोड़ दिया जैसा कि वह स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले थी। दोष तो हमारे नेताओं का है और प्लानिंग बनाने वालों का है जिन्होंने इन शिक्षा संस्थाओं को स्वतन्त्रता के बाद बदला नहीं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश का पूरा सर्वे होना चाहिये, हमारी आवश्यकताओं का, कि हमें मालूम हो जाना चाहिये कि कितनों को हमको ओवरसियर्स के लिये भेजना है और कितनों को इंजीनियर्स बनाना है, कितनों को पोलीटीशियन बनाना है, कितनों की ऐडमिनिस्ट्रेटिव एजूकेशन हो और उनको फौरन निकलने के बाद जौब मिल जाना चाहिये। पर इस दृष्टिकोण से नहीं कि केवल अपने जीवन का निर्वाह कर सकें बल्कि इस दृष्टिकोण से कि पूरे देश को और मानव जीवन को कितना हरा भरा बना सकें और देश की प्रगति को कितनी दूर ले जा सकें। वास्तव में हम देखते हैं कि एक दिशा में हम सब लैक करते हैं, डेवलपमेंट और प्लानिंग में। जब शिक्षा संस्थायें जो काम करती हैं इस बात को हम देखते हैं कि हमने फलां विषय का एक्सपर्ट आदमी निकाला और हम उसे ढूंढ़ते फिरते हैं, लेकिन पूरे समाज और पूरे देश की आने वाली पीढ़ी इस दिशा में शिक्षित हो रही है या नहीं ? आज देश उसके सामने है और देश के पीछे वह है, इस बात की बड़ी कमी है। मैं चाहता हूं कि अगर प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाना है और यह समस्या सर्वदा के लिये निपटाना है, तो सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा इस शिक्षा संस्थाओं को दुरुस्त करने के लिये और उस कदम को उठाने में हमको शिक्षा पद्धति की शक्ल बदलनी पड़ेगी, एक बड़ा भारी क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा। जो डेमोक्रेसी के नाम को ऐब्यूज करते हैं उन क्लासेज में, उसको तो आज भी बन्द कर देना पड़े और कुछ दिनों के लिये बन्द कर देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। प्लानिंग और अटोनौमी की बात कही जाती है, मैं समझता हूं कि सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी में इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि आप यूनीवर्सिटी में आटोनामी भी रखें और उसी के आधार पर आप अपनी शिक्षा पद्धति भी बदलें। इसको भूलना चाहिये। सिस्टम आफ एजूकेशन जो होगा, अगर आपको एजूकेशन देनी है और प्लान्ड एजूकेशन देनी है, और वह सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी के अन्तर्गत देनी है तो वह डाइरेक्टेड और कन्ट्रोल्ड होगी और वहां पर 'आटो' नाम की कोई गुंजायश नहीं रह जानी चाहिये। इसमें मेरा विश्वास है, इसमें किसी भी दिशा में दो रायें नहीं हो सकतीं। जब रशिया में प्लानिंग चली तो वहां डिक्टेटरशिप थी। हम डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हैं। हमने इसीलिये कहा कि भारतवर्ष में प्लानिंग और डेमोक्रेसी साथ-साथ रहेगी और और देश बड़ी ही उत्सुकता से, संसार जांच-पड़ताल करना चाहता है कि कैसे ये प्लानिंग और डेमोक्रेसी को कामयाब बनाते हैं ? डेमोक्रेसी के मानी अगर आप ब्यूराक्रेसी में शामिल कर देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा और वह चीज डेमोक्रेसी में इस तरह से बाकी रहेगी जहां कोई कुछ भी करे, वह चीज अराजकता का रूप धारण कर लेगी। मैं इस दिशा में यह कहना चाहूंगा कि यह एक सब से बड़ा गूढ़ विषय है, और अगर इस पर प्लानिंग का काम करना है तो उसको प्रथम स्थान देना होगा और एक बड़ा परिवर्तन करना होगा। मैं समझता हूं कि पूरी स्कीम तभी चल सकती है जब कि हमारी सरकार और देश इस काम के लिए प्राथमिकता देगा। यह जो नन्दा साहब का नोट है, अगर इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ें जो कि ऐड किया गया है वह महत्वपूर्ण है, और मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आदमी जब अथ रिटी में आता है तो अथारिटी में आ जाने के बाद "ही बिकम्स चैरी इन सपोर्ट आफ दि पब्लिक"। आथारिटी में आने वाला मिनिस्टर चैरी हो जाय, उदासीन हो जाय। यह सदन देख चुका है कि जो हमारी सर्विसेज के लोग हैं वे जरूर उदासीन हो जाते हैं, और जो प्लानिंग स्कीम गांव में जाती हैं

[श्री पद्मनाथ सिंह]

तो गांव की जनता उस स्कीम से दूर हट जाती है। माननीय कमलापति त्रिपाठी या नियोजन मंत्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त गांव में जाते हैं, या जिलों का दौरा करते हैं तो पब्लिक हजारों की संख्या में आती है। लेकिन जब उनके बताये हुए सिद्धान्तों के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या प्लानिंग अफसर वहां जाकर उस काम को कराते हैं तो पता नहीं क्यों लोग भाग जाते हैं? मैं निवेदन करूंगा कि एक खतरा है हमारे देश में इस बात का कि जनता को ब्यूरोक्रेसी से अलग रखने का। वह हमारी इस तमाम प्लानिंग को बेकार बना सकते हैं। करोड़ों रुपया सरकार का मंजूर होता है और पब्लिक के पास उसका एक अंश नहीं पहुंचता है। तो यदि पूरी योजना हमें पब्लिक तक पहुंचा देनी है तो हमें दो दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। वह दृष्टिकोण होगा यह कि पहले तो यह योजना जनता के हृदय में स्थित कर दी जाय और वह समझ जाय कि यह उसकी योजना है। दूसरा यह कि हमें सर्विसेज में और पब्लिक में एक ऐंथुजियाज्म पैदा करना होगा। मैं समझता हूं कि इसके पश्चात् कई योजनाएं आएंगी और मैं समझता हूं कि यह सेकेंड फाइव ईयर प्लान हमारे देश के सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को सही रूप में देश में स्थापित करने, तरक्की की तरफ इस देश को ले जाने में सफल होगी और देश को एक लीड देगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—श्रीमन् माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुनें, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की सफलता और सेकेंड फाइव ईयर प्लान के श्रीगणेश के ऊपर इस सदन में भाषण सुने। मैंने हर एक तरफ देखा और महसूस किया कि बहुत से माननीय सदस्यों का जो दृष्टिकोण प्लानिंग के ऊपर था वह इतना अधूरा था और इतनी कमियों से भरा हुआ था कि वह उस प्लान को जो मुल्क में चल रही है, अगर सही नजर से देखेंगे भी तो देख नहीं सकते थे। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हम प्लानिंग मुल्क की करने जा रहे हैं। आखिर को जब आप प्लानिंग करते हैं आपको बताना है कि मुल्क के पास विकास के क्या क्या साधन हैं और उन उपलब्ध साधनों को लेकर आप किस दिशा में पहला प्लानिंग का कदम उठाना चाहते हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे मुल्क के अन्दर अनाज की बहुत भारी कमी थी और दूर दूर के देशों से हमारे मुल्क को अनाज मंगाया जाता था। तो सब से पहला अगर किसी और प्लानिंग का कदम बढ़ाया जाना चाहिये था तो ठीक ही कदम सरकार ने बढ़ाया कि अनाज की पूर्ति के लिए हमारे देश के अन्दर प्लानिंग किया गया, और जितने भी साधन जुटाये जा सकते थे सरकार ने कभी साधनों के जुटाने में कोई कमी नहीं की। और आपको यह स्पष्ट मालूम है कि आज हमारे मुल्क के अन्दर अनाज की कमी बहुत हद तक दूर हो चुकी है। इसलिये फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, जिसको भाई गेंदासिंह ने "शेपलेस प्लान" बताया, और नारायणदत्त जी ने कहा कि इसकी कोई सूरत नहीं दिखाई देती, उसका कारण यही है कि जिस सूरत को वह देखना चाहते थे वह आइना उनके पास था नहीं, उनके दिमाग से वह लेंस मिसिंग था। चूंकि उनके ख्याल शरीफ में उस लेंस की रोशनी उनके दिमाग में नहीं पड़ी इसलिये उसकी कोई तस्वीर उनके दिमाग के अन्दर उतर नहीं सकती थी। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने मुल्क की परिस्थितियों को नहीं देखा, जिन्होंने प्लान को मुल्क की जरूरतों की दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं की वे इस प्लान को किस प्रकार समझ सकते थे। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इसमें कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। मैं कांग्रेस की गलत बातों का हामी नहीं हूं। मैं केवल सोशलिस्टों की बातों का समर्थन करने के लिये और उनको खुश करने के लिये इस सदन में भाषण नहीं देता। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि जो बात हमारे मुल्क के अन्दर चल रही है और जिस हद तक हमारी सरकार ने उसमें सफलता प्राप्त की है, वह किसी से छिपी नहीं है और उसको इस सफलता के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। अगर कोई साहब कहें

कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अन्दर हमारे प्रांत में चारों तरफ बिजली क्यों नहीं दौड़ाई गयी, तो मैं कहूंगा कि ठीक है, अगर बिजली के ऊपर सारा रुपया सरकार ने खर्च कर दिया होता तो भूख से मरे हुये आदमियों की लाशें उस बिजली की रोशनी में जगमगाती हुई दिखाई देतीं। इस वास्ते जो सबसे पहले जरूरी चीज थी उसकी ओर सरकार ने अधिक से अधिक ध्यान दिया। सरकार ने अधिक से अधिक अनाज पैदा करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि जब हम सेकेंड फाइव ईयर प्लान को देखते हैं तो हमें उसमें जानवरों का प्लान नजर आता है, खेती का प्लान नजर आता है, दूसरी दूसरी चीजों का प्लान नजर आता है, परन्तु इन्सान का प्लान नजर नहीं आता है ! इन्सान का प्लान क्या है, मैं उसको बताना चाहता हूं। खेती के विकास के लिये, जानवरों के विकास के लिये, और बातों के विकास के लिये करोड़ों की पूंजी रखी गयी है, मगर इन्सान, जिसकी एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों और गलियों में पड़ी सड़ रही है उसके उठाने का कोई प्लान हमारी इस प्लानिंग में नहीं दिखाई देता ! न तो उसके अन्दर कोई जिक्र है कि इस बढ़ती हुई मानवता को कब हम अपने देश से खत्म कर सकेंगे, कब हम ऊपर उठा सकेंगे। उसके लिये कोई पीरियड होता कि १०,२०,२५ साल के अन्दर हम इसको कर सकेंगे। उसका कोई नक्शा इस सदन में उपस्थित किया जाता। ऐसा नहीं हुआ उसका मुझे खेद है। मैं बताना चाहता हूं कि जबकि हम बूढ़े जानवरों के लिये गोशालायें खोला करते हैं, और उनके लिये चारे वगैरह की व्यवस्था करने के लिये हमारी यह सरकार और इस सदन के सदस्य तैयार हैं और उसके लिये बिल लाते हैं तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे इन्सान, जिनके पास न रहने के लिये जगह है, न खाने के लिये अनाज है और न इलाज के लिये दवा है उनके लिये कौन-सा प्लान और कौन-सा कानून आपने बनाया है ? इसकी कोई झांकी सेकेंड फाइव ईयर प्लान के अन्दर आपने नहीं दी है। यह आपको करना है जो कि इस मुल्क की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिये बैठे हैं, यह उनका फर्ज है और जब तक आप यह नहीं करते तब तक मैं समझता हूं कि कोई प्लान हमारी सफल नहीं हो सकती।

इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि आप कितने ही बड़े-बड़े प्लान्स क्यों न बनायें, आप कितने ही बड़े-बड़े प्लान्स को मैटीरियलाइज क्यों न कर लें, लेकिन जब तक आप अपने प्रदेश के अन्दर बढ़ती हुई आबादी को ठीक पैमाने पर नहीं रखते तब तक सफलता मिलना बहुत कठिन है। इसलिये मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कौन सा कदम उठाया है, कौन से स्टेप्स लिये हैं और उन पर कितना रुपया व्यय किया है इस बढ़ती हुई आबादी को लिमिट करने के लिये, और उस पर काबू रखने के लिये आपने कौन-कौन से उपाय किये हैं ? क्या-क्या प्रयास किया है, क्या-क्या कदम बढ़ाये हैं और कौन-सी व्यवस्था की है और कौन से तरीके अखतियार किये गये हैं ? इसलिये मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि इन बड़े-बड़े प्लान से हमारा तथा हमारे प्रदेश का उत्थान कदापि नहीं हो सकता है, और उस समय तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता है जब तक कि हम अपने यहां की बढ़ती हुई आबादी को इंसान का प्लान बनाकर रोक नहीं देते हैं तब तक अपने मुल्क का हम हित करने नहीं जा रहे हैं।

दूसरी बात मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आप लोग भी घबराइये नहीं। अब आपके प्लान की बारी भी आ रही है, और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि बहुत से हमारे भाई बड़े-बड़े भाषण देकर नुक्ताचीनी करने में ही अपना फख्र समझते हैं और मशहूर होते हैं और उनसे अगर प्लान मांगा जाय तो फिर खामोश रह जाते हैं। मैं उनको निमंत्रण देता हूं और मैं तैयार हूं कि जिससे वह कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उस प्लान की झांकी इस सदन में क्यों नहीं रखते ? क्या वह इस प्लान की खामियां बतलाकर ही अपने प्लान की झांकी रख देते हैं ? हरगिज नहीं। आज तक मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टिव प्लान किसी भी माननीय सदस्य को इस आदरणीय सदन में रखते हुये नहीं देखा है। इसका कारण यही है कि उनके दिमाग के अन्दर किसी भी प्लान की कोई तस्वीर नहीं है और उन्होंने अपने दिमाग में प्लान की तस्वीर बनाने का प्रयास भी नहीं किया है। आप सरकार की कमियों को बतला सकते हैं। लेकिन

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

अगर आपके पास कोई सही प्लान होता तब आपकी नजर आती और आप देखते कि यह प्लान आपके प्लान से मेल खाता है या नहीं, और इसमें क्या कमी रह गई है।

इसलिये मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार को ऐसी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिये। हमें अपने यहां के नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स का, तथा कम्युनिटी प्रोजेक्टस का तजुरबा है। इसमें कोई शक नहीं है अगर हमें दूसरे देशों से इम्दाद मिली है या लोन मिला है तो इसके माने यह नहीं हैं कि उनके बनाये हुये नकशे पर अगर हमारा मुल्क यहां के वातावरण के अनुसार नहीं पनप सकता है, या हमारे यहां इस तरह की मजबूरी है जिसके सफल बनाने में हम असमर्थ हैं तो हमें अपनी जरूरियात के मुताबिक उस प्लान को परिवर्तित करना होगा। हम अधिकतर देखते हैं कि जो नक्शा वहां से आया है उसको जब हम कार्य-रूप में परिणत करते हैं तो हम देखते हैं कि वह हमारे यहां सफल नहीं हो सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि हम अपने मुल्क की जरूरियात के मुताबिक इसको सफल बनाने के लिये इसमें बहुत से कट फिट करने होंगे। इसलिये हमको चाहिये कि जहां कम करना हो वहां कम करें और जहां बढ़ाना हो वहां बढायें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन एक्सटेंशन ब्लाक्स के लिये जो चार-साढ़े चार लाख रुपया रखा गया है, इसके संबंध में यह है कि जब तक यह रुपया एड में कंवर्ट नहीं की जाती है तब तक आपको सफलता कदापि प्राप्त नहीं हो सकती है। उसका कारण यह है कि जो यह साढ़े सात लाख रुपया है उसमें से डेढ़ दो लाख रुपया तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में ही चला जाता है और मुश्किल से डेढ़ लाख रुपया पब्लिक कार्य करने के लिये रह जाता है। इसलिये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस रुपये को एड में कंवर्ट कर देते हैं तो जनता को कार्य करने में आप बड़ी भारी इम्दाद देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यह एक्सटेंशन ब्लाक्स सफलता प्राप्त करेंगे, वरना यह टोटल फेल्योर होंगे।

जो लोग केवल अपनी प्रशंसा के लिये गीत गाते हैं, मैं उनके दिमाग के मापदंड को अच्छी तरह से जानता हूं, उनकी विद्वता और निश्चितता को अच्छी तरह से जानता हूं। और हमने इंसान को पढ़ाना सीखा है, हमने केवल किताबें ही नहीं पढ़ी हैं बल्कि चरित्र को रीड करना सीखा है। हमने केवल थर्मामीटर, मिल्कोमीटर आदि नहीं देखे हैं बल्कि मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अगर आपको मुल्क का ख्याल है तो उसकी परिस्थितियों को देखें और जो आप बात करते हैं केवल मंत्री महोदय को खुश करने के लिये वह हमारे मुल्क के लिये अहितकर साबित हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि अखबार वाले आपकी तारीफ निकालें और पायनियर और लीडर आपकी स्पीच छापें तो आपको अपना रास्ता बदलना होगा। मुझे इसका महान् खेद है। मैं चाहता हूं कि आपके भाषण से हमारा मुल्क बने, परिस्थितियों को प्रगति मिले और आपके उस भाषण में इसके लिये दृढ सुझाव हों। तब हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने में सफलता मिल सकती है। इसके लिये मैं अदब के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे फाइव ईयर प्लान से सब से अधिक ध्यान एजूकेशन विभाग की ओर देने की जरूरत है। मुझे खेद है, जैसी कि मैं पहले भी इस सदन में दरख्वास्त कर चुका हूं, कि हमारे एजूकेशन में सब से कम प्लानिंग हमारे देश में हुई है। शिक्षा के लिये बड़े बड़े कमीशन बैठाये गये और उनकी रिपोर्ट आज किताबों में हैं, लेकिन जहां तक शिक्षा को चालू करने का प्रश्न है उसके लिये मुझे खेद है और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि न तो मेरी माननीय मंत्री जी से दुश्मनी है और न दोस्ती ही है। किन्तु मुल्क के विकास के लिये अपनी बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक हम दृढता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक नीति को नहीं अपनाते, उस नीति को जो कि भविष्य में हमारे मुल्क को डिस्आर्डर से बचाये, उस समय तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। आज हजारों और लाखों विद्यार्थी बेकार साबित हुये हैं। मैं बताऊंगा कि हमारी शिक्षा की सफलता हमारे देश में उस समय दिखाई देगी जब कि स्कूल से या यूनिवर्सिटी से

विद्यार्थी पास होकर मुल्क के उत्थान के कार्य में जुट पड़ेगा। आज हमारे विद्यार्थी मधुमक्खियों की तरह से नजर आते हैं जो लखनऊ के होटलों और काफी हाउसेज में भिनभिनाया करते हैं। इनको देख कर मुझे महान् दुख होता है और मैं चाहता हूं कि हमको इसमें अवश्य ही अपनी नीति स्पष्ट कर देना चाहिये, और हम बहुत दिनों तक इस अनिश्चितता के साथ शिक्षा के विभाग में अपना काम चालू नहीं रख सकते। मुझे दुख है कि बार बार कमीशन्स बैठाई जाती हैं और उन कमीशनों पर रुपया खर्च किया जाता है। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इन कमीशनों में बहुत अधिक सदस्य इस तरह के हैं कि जो देश को बना नहीं सकते। उनकी शिक्षा दीक्षा उस शिक्षा पद्धति के मुताबिक हुई है जो कि हमारे देश के लिये कलंक रही है, जो हमारे देश को कुचलने के लिये, हमारे देश को पददलित करने के लिये अपनायी गयी थी। जब कभी कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा हमारे भविष्य का नक्शा देखता है जो उसके दिमाग में इटली, जर्मनी, स्वेटजरलैंड, इंग्लैंड आदि मुल्कों की तस्वीर उतर आती है, और हमारे इस देश में जिसका प्रोडेक्शन इतना पिछड़ा हुआ है, जिस मुल्क के लोग इतने गरीब हैं, जिसमें इतनी अशिक्षा और बेकारी है, उसमें, उन सारे देशों के एम्बिशश प्लान लागू करना चाहता है, और वह चाहता है कि उन प्लानों को इस देश में जो कि इतना पिछड़ा हुआ है, यहां लागू किया जाय। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जिस मुल्क की आर्थिक हड्डी टूटी हुई हो वह कैसे इन प्लानों को चालू कर सकता है ? आप मेरा खंडन करें इससे मुझे कोई डर नहीं है। मैं सब बातों को सहन करने को तैयार हूं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी बातों के ऊपर जब तक आप ध्यान न देंगे उस समय तक आप सत्यता को ठुकराएंगे, सत्य बात को आपको मानना पड़ेगा, और जब तक आप ऐसा नहीं कर पाते उस समय तक आप अपने इस देश का उत्थान नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी भारी कोशिश की, बड़ी बड़ी नहरें बनवाईं, बड़ी-बड़ी जमीनों को तोड़ा है, बड़े-बड़े जंगलों को काटा है और इतने कामों को किया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यह सब चीजें होते हुये भी हमारे अन्दर कमियां हैं, और सबसे बुरी बात तो जो है वह मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो एक सबसे बड़ी कमी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है वह यह है कि मैं देखता हूं कि हमारा प्लान आज सफल नहीं हो रहा है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं अगर माननीय मंत्री जी बुरा न माने और सरकार बुरा न समझे तो मैं उनको न्योता देता हूं कि वह एक एन० ई० एस० ब्लाक को एक सरकारी अफसर के अधिकार में दे दे और एक मेरे अधिकार में दे दे। मैं आपको यह विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि मैं अकेला कुछ थोड़े से रुपये में उतना काम कर सकता हूं जितने आपके अफसर नहीं कर सकते। आप आज वैल्थ के बांटने का काम जनता के हाथ में छोड़ दीजिये। यह बात सच है कि जनता को सरकार अपना समझती है लेकिन सरकार इस बात को जानती है कि जनता से उसको इस काम में सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारे कई भाइयों ने इस बात को कहा है कि जब तक जनता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता है, उनका इन कामों में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। वह लोग यह समझते हैं कि जितना रुपया प्लानिंग में रखा जाता है वह सब सरकारी नौकरों की तनख्वाह में ही चला जाता है और गरीब किसान देखते रह जाते हैं कि उनके यहां कुछ काम होगा, और वह रुपया उनको नहीं मिल पाता है। कुछ रुपया चन्द्रसिंह रावत को दिया जाय और उस काम से मैं इतना काम कर सकता हूं कि जितना काम आपके अफसर कभी नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको गरीब किसान लोगों का सहयोग नहीं मिलता है तब तक आपको इस काम में सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि आप मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे तो हमारे इस पूरे भारत में और हमारे मुल्क के राजनैतिक जीवन में जनता के स्तर को उठाना एक आसान काम हो जायगा। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सफलता हमने प्राप्त की है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। और जो सुझाव मैंने इस सदन में दिये हैं मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उनके ऊपर ध्यान देंगे और आंख मूंदकर नहीं बैठ जायेंगे। जो छोटे कार्यकर्ता हैं वही वहां की दशा को अच्छी तरह से जानते हैं। याद रखिये कि असलियत

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हम लोग ही जानते हैं। ऊपर के लोग तो आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं। अगर चन्द्रसिंह के चार-चार पट्टियां बांध दी जायं तो वह फिर भी देख सकता है। मगर जो ऊपर के लोग पट्टी बांधे रखते हैं उनको तो दुनिया में पीला ही पीला नजर आता है और उनको कोई देश में गरीब नजर नहीं आता है। लेकिन हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिये मैं एक बार फिर उनको धन्यवाद देता हूं और यह आशा करता हूं कि हमारी बातों पर हमारे मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे और हमारी जनता को कान्फिडेंस में लेकर उसको राष्ट्र निर्माण के काम में पार्टिसिपेट करने के लिये जितने भी उपाय हो सकते हैं, जितने भी सक्रिय कदम उठा सकते हैं उसको उठाने में कमी नहीं रखेंगे।

श्री रामलाल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं आपके जरिये से प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में यह बताना चाहता हूं कि जो प्लानिंग का काम और निर्माण कार्य हो रहा है उससे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और उससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हुआ। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू होने जा रही है उससे भी आशा है कि बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी।

अब मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उन खेतिहर मजदूरों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो देहात के रहने वाले हैं।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, जितना निर्माण कार्य हुआ है वह सराहनीय जरूर है लेकिन वह उन्हीं के लिये हुआ है जो इस मुल्क के किसान हैं। किसानों का बहुत बड़ा लाभ हुआ है, उनकी पैदावार बढ़ी, उससे मुल्क को फायदा हुआ, लेकिन जो देहात के खेतिहर गरीब मजदूर लोग हैं वह अभी अपनी जगह पर ज्यों के त्यों कायम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बतला देना चाहता हूं कि उन खेतिहर मजदूरों में ९०–९५ प्रतिशत वह लोग हैं जो हरिजन कहलाते हैं, वे गरीब लोग केवल मजदूरी का पेशा करते हैं और अभी तक मजदूर के मजदूर ही बने हुये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार निर्माण कार्य पर दरिया की तरह रुपया बहा रही है उसी तरह से एक समस्या यह भी बहुत बड़ी है कि जो देहात के खेतिहर मजदूर हैं वे अभी तक गरीब अपनी जगह पर कायम हैं! उनके लिये उद्योग-धंधों के लिये, उनके पानी के कुओं के लिये, उनके मकानों के लिये ज्यादा से ज्यादा तवज्जुह देनी चाहिये क्योंकि वे वही खेतिहर मजदूर हैं जो बहुत दिनों से यह आशा लगाये हुये थे कि जब मुल्क आजाद होगा तब हम गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा सुख होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की निन्दा तो नहीं कर सकता क्योंकि जो काम सरकार कर रही है वह मुल्क के फायदे के लिये सरकार कर रही है, और यह भी नहीं है कि गरीबों के लिये कुछ काम न कर रही हो। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं बतला देना चाहता हूं कि जो काम सरकार के जरिये से गरीबों के हो रहे हैं वे नहीं के बराबर हैं। न तो उनके रहने-सहने के लिये अच्छे रूप से कोई काम हो रहा है और न उनकी कोई उन्नति हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देहात के उन गरीब किसानों और मजदूरों की बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा उनके कुओं के लिये, उनके घर निर्माण के लिये मदद दें। वही किसान मजदूर पहले यह जानते थे कि हमको जमीन मिलेगी, जब मुल्क आजाद होगा तो जमीन का बटवारा होगा, हमें सुख होगा। लेकिन जमीन का बटवारा खैर अपनी जगह ज्यों का त्यों कायम है, कभी वह योजना भी लागू होगी। लेकिन इधर जो निर्माण कार्य हो रहा है इस निर्माण कार्य में कम से कम सरकार को गरीबों की तरफ ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजनों की जो समस्या है वह किसी से छिपी नहीं है कि उनकी क्या आर्थिक अवस्था है, क्या

उनका रहन-सहन है और क्या उनका सामाजिक ढांचा है ? वह कहने की बात नहीं है, मैं समझता हूं कि सभी उसको जानते हैं । परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें ।

जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के गरीब मजदूर हम लोगों से सवाल करते हैं कि स्वराज्य होने के बाद यह जो सारा कारबार हो रहा है तो उसमें हम लोगों के लिये क्या हो रहा है ? जो विरोधीदल के लोग हैं वह लोग भी जाकर उनको मंत्र देते हैं कि यह जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनमें तुम्हारा क्या हित है ? बात तो दरअसल है । वह लोग भी हम लोगों से शिकायत करते हैं, कि आप लोग जाते हैं, असेम्बली में बैठते हैं तो क्या हम लोगों की बात आप लोग वहां कहते हैं, क्या हम लोगों की गरीबी की बात सरकार के सामने रखते हैं या नहीं रखते ? हम लोग भी उनको समझाते हैं और संतोष दिलाते हैं कि सरकार जो कर रही है थोड़ा बहुत काम हमें आशा है कि वह ज्यादा से ज्यादा काम करेगी । चूंकि इस वक्त सरकार के सामने अन्न की समस्या बहुत जोरों के साथ है, उधर बाढ़ की समस्या है, उधर पत्थर की समस्या है, उधर सूखे की समस्या है । इस तरह से सरकार के सामने बहुत बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आयीं जिससे सरकार निर्माण कार्य और अन्न उत्पादन के कार्य में लगी हुई है । उससे सरकार को जहां थोड़ी सी फुरसत मिली कि वह गरीबों की गरीबी दूर करने का जल्द से जल्द प्रयत्न करेगी । वे लोग भी आशा लगाये हैं कि हमारी गरीबी जल्द से जल्द दूर होगी, सरकार इसको दूर करेगी । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम सरकार कर रही है वह बहुत मामूली सा काम कर रही है क्योंकि गरीब जो हैं वे अपनी जगह पर ज्यों के त्यों कायम हैं । भले ही जमींदारी खतम हुई, उससे उनकी बेगारी छूटी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी भी गरीबी और अमीरी का संबंध है । गरीब अभी भी अपनी जगह पर ज्यों का त्यों कायम है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार तमाम निर्माण कार्य करने में रुपया बहा रही है उसी तरह से सरकार देहात की झोपड़ियों में रहने वाले गरीब खेतिहर मजदूरों के लिये मकान बनवाने का प्रबन्ध करे । बाढ़ में उनके मकान गिर गये, पस्त हो गये, अब वे अपने परिवार का तथा अपना पेट भरने के लिये मजदूरी करें या मकान बनायें ? तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे गरीबों के मकान बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने की कृपा करें, ताकि वे भी समझें कि मुल्क आजाद हुआ और हमको सुख हुआ । तो मैं बहुत नम्रता के साथ अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब तबका है वह आशा लगाये हुये है कि हमारी भलाई का काम होगा । परन्तु इस वक्त जो हो रहा है वह नहीं के बराबर है । इसलिये मैं साफ आपके सामने बतला देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर जाना चाहिये और जो गरीब हरिजन या पिछड़ी जाति के गरीब देहातों के रहने वाले हैं उनकी पढ़ाई लिखायी के लिये, उनकी सहायता के लिये, उनके स्कालरशिप के लिये काफी से काफी तवज्जह सरकार को देनी चाहिये । क्योंकि वे जानते थे कि स्वराज्य के बाद हमको जमीन मिलेगी, हमको सुख मिलेगा । तो अब वह दिन आज उनके सामने है और वे देख रहे हैं रास्ता कि कांग्रेस सरकार के जरिये उनकी भलाई होगी । तो इसलिये मैं बड़ी नम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन गरीबों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें । इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गरीबों के लिये जो अनुदान रखा गया है वह बहुत कम है, इसलिये माननीय मंत्री जी उधर ध्यान देने की कृपा करें ।

*राजा वीरेन्द्रशाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा था कि नियोजन या डेवलपमेंट के सम्बन्ध में हमें चीजों को दलबन्दी या दलों की नीति से नहीं देखना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं और आपके द्वारा मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विरोध रहते हुए भी मैं हर प्रकार से कोई भी सरकार चाहे प्रान्त में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

इस काम को करे उसकी सहायता करने को मैं तैयार हूं, और हमेशा आगे रहने के लिये तैयार रहता हूं। लेकिन मैं सरकार को आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि हमारी एक बड़ी कठिनाई है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम देखते हैं कि देहात में जो राजनैतिक पार्टियां हैं, जो देहाती कार्यकर्ता हैं, उनमें इतनी लगन और उत्साह है। लेकिन इस नियोजन के कार्य में अगर वह सहयोग नहीं करते तो उसका भी कोई कारण है। अव्वल तो जो कमेटियां सरकार ने जिलों में बनाई हैं, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए, मैं मानता हूं कि उनमें सरकार को कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने चाहिए। लेकिन उनके साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि देहात में दूसरी राजनैतिक पार्टियां हैं उनके देहात के कार्यकर्ताओं से भी कुछ न कुछ काम लेना चाहिए, और उनके भी एक दो मेम्बर इन नियोजन कमेटियों में होने चाहिए। मैं जानता हूं क्योंकि मैं नियोजन कमेटी में अपने जिले में कार्यकर्ता हूं, और वहां यह होता है कि बहुत से काम होते हैं और हमने इस नियोजन के काम में पिछले चार-पांच वर्ष से काम किया और उसमें हमें सफलता भी हुई। और उस सफलता में हमें प्रान्त में उन्नति भी दिखाई पड़ी। उसके लिये मैं सरकार को बधाई भी देता हूं। जैसे कि सिंचाई के साधनों में नहर और डैम बनाने में और मैं अपनी केन्द्रीय सरकार को भी इसके लिए बधाई देता हूं। हमारे यहां बुन्देलखंड में भी ललितपुर में डैम तैयार हो गया और झांसी में भी माताटीला डेम बनाया जा रहा है और उससे हमारे प्रान्त का लाभ होगा।

इसी वजह से हमें मालूम होता है कि हमने अपने यहां की अन्न की समस्या को हल किया और सरकार ने उससे छुटकारा पाया। हम अन्न की समस्या को हल कर चुके हैं और माननीय मंत्री जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस बात को माना है कि जिन किसानों ने या फार्म होल्डर्स ने कोशिश करके नए-नए फार्म बना कर और रुपया लगा कर इस प्रदेश की अन्न उपजाने में सहायता की है उसको उन्होंने भवन में स्वीकार किया है। उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने नियोजन में यह उत्साह दिला कर फार्म तो बनवा दिए लेकिन दूसरी ओर सरकार की जो अनिश्चित नीति है, जो उसकी नीयत है उससे फार्म होल्डर्स को जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं उनको बड़ा भय है। उनकी स्थिति को साफ करना चाहिए, माल मंत्री जी की स्पष्ट नीति होनी चाहिए यदि वह कोई फार्म की लिमिटेशन करना चाहते हैं। अगर उनका ऐसा इरादा है तो उनको जिस तरह से यह प्लान बनाई है उसके लिए स्पष्ट प्लान बनाना चाहिए और साफ कहना चाहिए कि हम जोतों का स्केलिंग करेंगे, जिससे फार्म होल्डर्स उसी प्रकार से रुपया लगा कर अपने यहां प्रबन्ध करें। यह न हो कि उधर तो मंत्री जी कहते हैं कि छोटी होल्डिंग्ज से लाभ होता है और बड़ी से कोई लाभ नहीं है। ठीक है उनकी राय ठीक हो सकती है। लेकिन इस तरफ तो वह ऐसा कहते हैं और दूसरी तरफ मेकेनाइज्ड फार्मिंग के बहुत से काम वह कलों से कराते हैं और बढ़ाते जाते हैं, तो इस तरह से समझ में नहीं आता कि वह किस नीति पर चलना चाहते हैं? पता नहीं वह ३० एकड़ की जोत रखेंगे या दस एकड़ की रखेंगे, कुछ पता नहीं चलता? उनको इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट नीति घोषित करना चाहिए और बताना चाहिए कि इतने तक हम स्केलिंग करना चाहते हैं जिससे अन्न की समस्या जो किसी तरह हल हुई वह आगे बिगड़ने न पाये।

अब श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि सरकार जहां लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करने जा रही है वहां हम लोगों के टेकनीकल एक्सपीरियेंस से फायदा उठाना चाहिये। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। जहां, श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड बन गया है वहां अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की क्या जरूरत है? ५ वर्ष के लिये जो प्लान बनेगा वह काम तो सारा का सारा प्लानिंग बोर्ड करेगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अब क्या करेगा? वहां ८ साल पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है जिसका न कोई चुनाव हुआ है न कोई काम है। सिर्फ इतना काम रह गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट ढाई सौ रुपया तनख्वाह पावे, और कहीं कुछ मास्टरों का और

कहीं कुछ लड़कों का प्रबन्ध देखता है। सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० बनावे, शिक्षा का प्रसार शिक्षा विभाग करावे, और पंचायतों का चुनाव पंचायत विभाग करे। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की क्या जरूरत है ? हमें यह अवश्य सोचना चाहिये, जब हम प्लानिंग करना चाहते हैं तो जो बेकार के विभाग हैं और जो बेकार की चीजें हैं उनको हटा देने की जरूरत होगी।

श्रीमन्, मैं यहां यह भी बतलाना चाहता हूं कि देहातों की तरक्की करने के लिये जरूरी है कि हम यातायात के साधनों का अच्छा प्रबन्ध करें। पैदावार में तरक्की देने के लिये और उद्योग धंधों को तरक्की देने के लिये, सहकारिता की तरक्की के लिये, यानी सब कार्यों के लिये आवश्यक है यातायात के साधन, और उनके बग़ैर कोई कार्य नहीं हो सकता। श्रीमन्, मैं अपने जिले की हालत जानता हूं। वहां सारे सूबे से कम पक्की सड़कें हैं। मैं क्या बतलाऊं श्रीमन् कि सड़कें जो श्रमदान से तैयार होती ह उनकी क्या हालत है। श्रमदान के लिये कोई प्राथमिकता आप देते नहीं हैं और जब श्रमदान द्वारा किये हुये कार्य में आप प्राथमिकता दें तब तो लोग उसके लिये तैयार होते हैं। श्रमदान ऐसे नहीं हो सकता कि आपके कलेक्टर साहब ने और आफिसर ने हुक्म दे दिया कि शुरू कर दो और वादा कर दिया और जब काम हो गया तो उसके बाद सुनवाई नहीं है ! मैं अपने जिले की हालत बतलाता हूं। एक सड़क पांच मील की है, जिलाधीश ने आदेश दिया कि अगर आप कच्ची बना देंगे तो हम पक्की करा देंगे। उस पर श्रमदान किया गया और समय से पूर्व सारा काम हो गया। सौभाग्य से डिप्टी मिनिस्टर पी० डब्ल्यू० डी० भी यहां बैठे हुये हैं वह स्वयं जानते हैं कि उन्होंने पक्की करने के लिये भी मंजूरी दी और जितनी और सारी कार्यवाही थी उसको कराने का प्रयत्न किया गया। और जो आधा खर्चा नियमतः जरूरी होता है वह भी हम लोगों ने जमा कर दिया और आर्डर हो गया। लेकिन श्रीमन् मुझे दुःख से साथ कहना पड़ता है कि विभाग के इतने जटिल कानून बने हुये हैं कि आज तक उस सड़क पर कार्य नहीं हुआ है ! बावजूद मिनिस्टर साहब के और नियोजन के कमिश्नर साहब के आदेश के, सबने अपनी आज्ञा दे दी लेकिन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब झांसी ने उस काम को नहीं लिया और इस तरह से जो काम वहां हुआ था वह सब खत्म हो गया और इस प्रकार श्रमदान करने वालों का उत्साह खत्म हो गया। श्रीमन्, इस साल बरसात भी बहुत ज्यादा हुई और वहां उस सड़क पर एक ढेला मिट्टी का नहीं बचा है और सारी मिट्टी बह गयी और इस प्रकार हम लोगों का उत्साह खत्म कर दिया गया है। अब मेरा कोई मुंह नहीं है कि मैं लोगों के पास जाऊं और कहूं कि श्रमदान करो। तो इस तरह मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां ऐसा कार्य हो वह पहले लिया जाय। सरकार चाहती है कि देहातों में अस्पताल खुलें। तो मैं यह कहूंगा कि देहातों में अस्पताल तभी कामयाब हो सकते हैं, जब आप वहां इन्डोर पेशेंट्स वार्ड्स बनायेंगे। अगर आपने सिर्फ अस्पताल खोल दिया, लोग दूर-दूर से आते हैं, और दवा लेकर चले गये, लेकिन जो दरअसल पीड़ित लोग हैं तो गांव में कोई धर्मशाला तो होती नहीं जिसमें ठहर कर इलाज करा सकें। जब इतना रुपया खर्च करते हैं तो देहाती अस्पताल के लिये यह अनिवार्य रखें कि वहां पर इन्डोर पेशेंट वार्ड अवश्य होना चाहिये। अगर नहीं है तो आपके अस्पताल को कोई महत्व नहीं। मेरे जिले में जगमनपुर में एक अस्पताल खोला गया, वहां तो सरकार को कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ा। सारी बिल्डिंग यों ही मिल गई है। जालौन जिले में एक दूसरी जगह जो अस्पताल है उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि सरकार हर जिले की नियोजन कमेटी के पास एक लाख रुपया इसलिये छोड़ दे कि वहां की नियोजन कमेटी जिस काम में उसे लगाना चाहे वह लगा सके, और उससे उसे उत्साह होगा कि कुछ रुपया हमारी मंशा के मुताबिक खर्च हो रहा है। यह न होना चाहिये कि सारा प्लान यहीं से निर्धारित कर दिया जाय कि इतना इसके लिये और इतना इसके लिये।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

श्रीमन्, प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो हमने काम एक साथ जल्दी में किया था और जो बड़े बड़े काम थे उनको ले लिया। उसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में यह कहूंगा, कि जैसा कि कहा गया कि अभी ये टेनटेटिव प्रोपोजल्स हैं, लिहाजा डिवीजनल कान्फ्रेंसेज हों और हर डिवीजन में लोगों से यह पूछा जाय कि हम आपके यहां ५ साल में यह विकास करने जा रहे हैं वह आपको पसन्द है या नहीं? या वे कुछ तब्दीली चाहते हैं तब शायद आपके पास कुछ ऐसे सुझाव आवें जिन पर कि सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता पड़े।

सरकार ने किसी जिले में जो अनिवार्य शिक्षा फैलायी है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये और उसके मातहत जो २५ हजार स्कूल खोले गये हैं मैं आपके द्वारा यह कहूंगा कि शिक्षा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो स्वयं शिक्षा विभाग उनका प्रबन्ध करे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि वहां शिक्षा सम्बन्धी कोई काम नहीं होता सिवा इसके कि प्रेसीडेंट द्वारा उस काम में अड़चन डाली जाय और मास्टरों का वेतन नहीं मिलता, रोजाना तबादला होता है। अगर आप शिक्षा अनिवार्य करना चाहते हैं तो प्रारम्भिक शिक्षा को सरकार को स्वयं अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से उसका इन्तजाम कराया गया तो दिक्कतें सामने आती हैं।

मैं अब यह अर्ज करूंगा कि जो चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य है ये दोनों एक कर दिये जायं। अगर सिविल सर्जन के अन्डर में हेल्थ आफिसर काम करेगा तो नियंत्रण अधिक होगा। मेरे जिले में हालत यह है कि चेचक के टीके तीन साल से नहीं लगे...

श्री अध्यक्ष---अब आप प्लान पर आ जाइये।

राजा विरेन्द्रशाह---मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि प्लानिंग में हम इन-इन योजनाओं पर खर्च करने जा रहे हैं---इतना सड़कों पर, इतना शिक्षा पर, इतना अस्पतालों पर। तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उसमें आप खर्च करें तो यह देख लें कि जो वहां के लोगों की राय है और जनता की राय है उसको देख कर और उनके विचारों को साथ में लेते हुए तब आप गौर करें। मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि सरकार को यह भी चाहिए कि जो कर्मचारी या नियोजन कमेटी के अधिकारी इंडेपेंडेंट तरीके से काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। उनको तरक्की मिलनी चाहिए जो अच्छा काम करते हों। हमारे जिले में डेढ़ साल में जो कार्य निजोयन कमेटी के डेवलपमेंट आफिसर ने किया, जो कि बीच में बदल दिये गये, जो काम उन्होंने डेढ़ साल में किया वह तीन साल में भी नहीं हुआ। इस तरह से बीच में अधिकारियों को बदल देने से उत्साह गिरता है और काम में गड़बड़ी पड़ती है।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)-- अध्यक्ष महोदय, पहली फाइव ईयर प्लान और दूसरी फाइव ईयर प्लान के मुताल्लिक इस हाउस में करीब-करीब हर तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। मुझे तो बहुत थोड़ी सी बातें कहनी हैं और मुझे उम्मीद है कि चूंकि मैं बहुत थोड़ी बातें अर्ज करूंगा सरकार के सामने तो वह दिमाग़ में रख ही लेगी। ज्यादा बातें अर्ज करने में मुमकिन है कि कोई बात भूल भी जाय।

आज जो मामला जेरे बहस है मैं उसका मतलब यह नहीं समझता कि वह इसलिए है कि उसमें किसी खास किस्म की नुक्ताचीनी इस नुक्तेनजर से की जाय कि जैसे बजट पर की जाती है और क्रिटिसाइज किया जाय। हमारे सामने यह जो मामला रखा गया है वह इसलिए रखा गया है कि हमारी नोटिस में यह बात आ जाय कि दूसरे पंचसाला प्रोग्राम में क्या-क्या चीजें आने वाली हैं और कितना रुपया किस दिशा में सर्फ किया जाने वाला है?

एक बात और दूसरी बात यह है कि जो आब्जेक्ट हमारा है उसकी प्राप्ति के जो साधन हैं उन साधनों में कोई कमी तो नहीं है ? अगर इस नुक्तेनिगाह से हम इस बहस मुबाहसा में कुछ हिस्सा लेंगे तो हमारा ख्याल यह है कि हम बहुत दूर तक इस प्वाइंट को कवर कर सकेंगे ? लेकिन अगर पहले पंचसाला प्लान में जो तजुर्बात लोगों को हासिल हुए हैं और उनमें जो खामियां नजर आयी हैं अगर उनको ही हम बताते रहें तो जो अच्छे सजेशन हम सरकार को दे सकते हैं वह दे नहीं पायेंगे। और सरकार ने जो इस हाउस में इस दूसरे पंचसाला प्रोग्राम को रखा है वह इसी नुक्ते निगाह से रखा है कि पहले पंचसाला प्रोग्राम से जो तजुर्बे हांसिल हुए हैं उनकी लाइट में नयी बातें सामने रखी जायं। अभी अपोजीशन की ओर से तिवारी जी का जो भाषण हुआ वह भी करीब करीब इसी किस्म का था। उन्होंने बहुत सी खामियां बतलायीं। पहले पंचशाला प्रोग्राम की। उन्होंने यह भी जाहिर किया कि नया प्लान जो सामने आने वाला है उसका वर्किंग भी कमोवेश उसी तरह से होगा जैसा कि पहले प्लान का हुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच में कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशंस इस हाउस को नहीं दिये जिससे दूसरे पंचसाला प्रोग्राम में अमल में लाते वक्त फायदा उठाया जा सके। जहां तक पहले पंचसाला प्रोग्राम का ताल्लुक है वह पहला पंचसाला प्लान था। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि किसी भी प्लान को अमलदरामद करने का हमें तजुर्बा नहीं था, और हमारे पास टेक्निकल हैंड्स भी इतने नहीं थे जो उस प्लान को सही तरीके से सौ फीसदी कामियाबी की तरफ ले जाते। लेकिन बावजूद इसके, बावजूद इन शार्ट कमिंग्ज के जो नतीजा पहले पंचसाला प्रोग्राम से निकलता है वह इतना डिस्करेजिंग नहीं है जिससे हमारा उत्साह ही खत्म हो जाय। हमें बहुत बड़ी कामयाबी उसमें हासिल हुई है और हमें फक्र है और जिन लोगों ने उस प्लान को चलाया है वे धन्यवाद के मुस्तहक़ हैं भी। दूसरी पांचसाला प्रोग्राम के सिलसिले में जितना रुपया और जितनी स्कीमें इस गवर्नमेंट ने रखीं दुख की बात है कि सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन ने उसे स्वीकार न करके उस हौसले को पूरा होने में कुछ थोड़ी सी बाधायें पैदा कर दीं ! फिर भी जो दूसरा पांचसाला प्लान हमारे सामने आने वाला है वह कुछ अच्छा है और अगर उस पर सही तरीके से अमल किया गया तो हमारा सूबा बहुत बड़ी तरक्की कर जायगा।

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने दूसरा पांचसाला प्लान को देखा तो मुझे एक सबसे बड़ी कमी नजर आयी, और वह कमी यह है कि इस बात की प्लान बनाते वक्त कोई कोशिश खास तौर से नहीं की गई कि इस आइन्दा पांचसाला में जितना रुपया हम सर्फ करना चाहते हैं सेकेंड प्लान के मुताल्लिक वह रुपया सही तरीके से एक एक पाई तक खर्च हो जाय। और यह सबसे बड़ी बात है जिसका हमें दूसरे पांचसाला प्रोग्राम में ध्यान रखना है। हम जो आइन्दा पांचसालों में काम करना चाहते हैं उतना कर दें तो हम वाकई मुस्तहक हैं तहसीन के। उससे ज्यादा कर दें तो और भी ज्यादा मुस्तहक हैं। लेकिन जो काम हम करना चाहते हैं अगर उस काम से कुछ कम भी कर लें तो ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए कोई मजाक उड़ाएगा। तो इसलिये मैं गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि दूसरे पांचसाला प्रोग्राम में जितना रुपया और फंड्स खर्च हों गवर्नमेंट को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि जो फंड्स खर्च होंगे सही सही खर्च होंगे और उसका मिस-यूज नहीं होगा। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं इसी सिलसिले में और वह यह है कि हमें पहले पांचसाला प्रोग्राम में काम करने के सिलसिले में इस बात का तजुर्बा हुआ होगा कि पी० डब्ल्यू० डी० ने जितने काम किये उनका कोई चैक और उनके कामों को दुबारा कोई देखने भालने वाला एजेन्सी इस किस्म की गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी कि जिसका यह काम होता कि जो काम किया गया है और जो रुपया सर्फ किया गया है वह काम उतने ही रुपये में हो सकता था या कम में हो सकता था ? या जो मौडल्स स्वीकार किये

[श्री खूबसिंह]

गये हैं या काम किया गया है वह गलत तो नहीं किया गया है ? एक बात, और दूसरी बात यह कि जितना मसाला और जो गवर्नमेंट चाहती थी वे तमाम बातें उस हद तक लगाई गई हैं या नहीं ? असल में जहां तक इंजीनियर्स का ताल्लुक है उनके काम में आसानी से कोई नुक्ताचीनी निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात हो सकती है और वह यह कि एक एजेन्सी सूबे में सिर्फ इसी काम के वास्ते कायम की जाय जिसका काम निर्माण कार्य नहीं होगा, नक्शा बनना नहीं होगा, कोई काम करना नहीं होगा, केवल एक काम होगा और वह यह होगा कि वक्तन फवक्तन जा करके निर्माण के जितने काम इस सूबे में हो रहे हैं उन्हें एक्जामिन करे, और यह देखे कि जिनके हाथ में नक्शा बनाना था उन्होंने सही बनाया है, और जिनके हाथ में अमली शक्ल देने का काम था वह ठीक दी है ? और जितना रुपया उन्होंने सर्फ किया है या हो रहा है इससे कम में हो सकता था या नहीं, और ऐसा तो नहीं किया है कि ज्यादा खर्च दिखाया हो और कम पैसा लगाया हो ? अगर इस किस्म की एजेन्सी हो गई तो निश्चय ही बहुत बड़ी धनराशि हमबचा सकते हैं। सूबे की और जितनी हमें कमी महसूस हो रही है इस वक्त जो सात सौ कुछ करोड़ रुपया लगेगा दूसरे फाइव ईयर प्लान के अन्दर मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह से एकोनामी करते तो निश्चित काम करने के बाद भी हम इतना पैसा बचा सकते थे। मिसाल के तौर पर मैं एक बात बतलाना चाहता हूं। मैंने एक सड़क देखी जो पी० डब्ल्यू० डी० की बनायी हुई थी। उसमें मैंने कई पुलियां ऐसी देखीं कि जब वे बनायी जा रही थी तो जो मामूली आदमी भी वहां के रहने वाले थे उन्होंने कहा कि ये पुलियां छोटी हैं, पानी यहां से ज्यादा आता है और पानी का निकास इन पुलियों में कम है। उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ आदमी हो, हम इंजीनियर हैं, हम इस काम को ज्यादा समझते हैं। ये पुलियां सिउहोरा, सूरजनगर रोड जो बिजनौर जिले में है उस पर हैं। नतीजा उसका यह हुआ कि पहली बरसात में ही वे पुलिया पानी के निकास को बर्दाश्त नहीं कर पायीं और टूट गयीं। अभी तक उनकी मरम्मत नहीं हुई है। अब देखना यह है कि उन्होंने जो डिजाइन्स बनाये थे गलत थे यह बात साबित हो गई। दूसरी बात यह है कि जितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया था चार्ज उन्होंने उतना ही कर लिया। इसके देखने वाले कौन थे ? उसी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव और चीफ इंजीनियर। तो उसी डिपार्टमेंट के आदमी जिसके जरिये यह काम हुआ है उसको बुरा कह ही नहीं सकते। इस वास्ते यह जरूरी है कि कोई दूसरे लोग ऐसे कामों को देखने के लिये हों। तो इसको कोई व्यवस्था इस प्लान में नजर नहीं आती है।

एक दूसरी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त हम प्लांस बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उस वक्त हमारा ध्यान जिस चीज पर रहता है वह यह है कि जो प्रोजेक्ट बनाने के लिये दिया गया है वह बना दिया जाय। लेकिन उस प्रोजेक्ट के बनने से जो उस जगह के रहने वाले लोगों को दिक्कतें और परेशानियां होती हैं उसकी ओर गवर्नमेंट का मुतलक भी ध्यान नहीं जाता। मिसाल के तौर पर जिला बिजनौर में एगरैनी डैम है। वहां एक पम्पिंग स्टेशन है। उस डैम से उस पम्पिंग स्टेशन में पानी लाने के लिये पिछले तीन साल से इर्रीगेशन डिपार्टमेंट मुसलसल कोशिश कर रहा है और एक बांध बांधता है। लेकिन उस बांध के बंधने से जो आबादी नदी के दूसरी तरफ है उसमें पानी भर जाता है और लोगों के घरों में भर जाता है। तो बराबर तीन साल से वहां के आदमी बरसात में उस बांध को काटते हैं तब जाकर उनका गांव बचता है, और कभी इर्रीगेशन डिपार्टमेंट वालों ने इस तरफ तवज्जह नहीं की। उसमें मेरे ख्याल से २–४ लाख नहीं बल्कि एक करोड़ से ज्यादा रुपये का इस तरह से अपव्यय हुआ है। काश कि उस गांव की हिफाजत के लिये भी सरकार ने लाख दो लाख रुपये खर्च कर दिये होते तो वह बांध बराबर चलता रहता। तो पब्लिक के सुख दुख की ओर

डिपार्टमेंट के आदमी ज्यादा तवज्जह नहीं करते, एक खास प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट देती है उसको करने की धुन में। यह एक बहुत बड़ी कमी है। इस तरफ खासतौर से गवर्नमेंट को तवज्जह करनी चाहिये।

जहां तक इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है उसमें भी यह बात है और पी० डब्ल्यू० डी० के लिये तो ओपेन लाइसेंस है। २०–२५ फीसदी तो वैसे ही उनका बंधा रहता है। सब जानते हैं उसको और आज तक गवर्नमेंट इसे चेक नहीं कर पायी है। तो अगर इसी तरह से यह ओपेन लाइसेंस रहा तो मैं जानता नहीं कि इस सेकेंड फाइव ईयर प्लान का क्या हश्र होगा? जो काम इसके अन्दर बनने हैं वे कैसे पूरे होंगे, और अगर पूरे भी होंगे तो आज इस बात का पता आपको नहीं लगेगा कि जो काम हुये हैं उनकी उम्र क्या है, क्योंकि उस वक्त तक हम जिन्दा नहीं रहेंगे। जिस काम की उम्र आप १०० साल की समझे बैठे हैं मुमकिन है कि उसकी उम्र २५ साल की ही निकले। तो इसकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस किस्म की कोई एजेंसी कायम कर लेगी।

इसके बाद मैं गवर्नमेंट की तवज्जह उत्तर प्रांत के बनों की ओर ले जाना चाहता हूं। वन उत्तर प्रदेश के उत्तर में काफी लम्बा चौड़ा चला गया है, उससे बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है और कई नये उद्योग और काम ऐसे निकल सकते हैं जिससे लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता है और हमारे सूबे की इकानामी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। लेकिन हमने उस तरफ तवज्जह नहीं की। मिसाल के तौर पर दवाइयों के ही इतने कारखाने वहां पर खुल सकते हैं जिसमें हमारे प्रांत का जो करोड़ों रुपया बाहर दवाइयों को खरीदने में जाता है वह रोका जा सकता है, बल्कि बाहर से ही काफी धन सूबे में आ सकता है और उस रुपये से हमारे इस प्रांत में यहां के लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बहुत ऊंचा हो सकता है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन कई कारखाने दवाई तैयार करने के बन सकते हैं।

एक बात की तरफ और तवज्जह दिलाता हूं कि अनएम्पलायमेंट को दूर करने के लिये गवर्नमेंट ने बहुत सा काम किया और करने जा रही है और उस दिशा में बहुत काफी तजुर्बा कर रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री सूबे की तरफ से खोलकर अनएम्पलायमेंट को कम करने की कोशिश की जा रही है और अपनी तरफ से माल तैयार भी करा रही है। लेकिन एक बात गवर्नमेंट ने दूसरे पंचसाला प्रोग्राम में नहीं की। मैं चाहता था कि यह जो काटेज इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम चाहते हैं कि इंडिवीज्वल लोग खुद करें, मैं चाहता हूं कि हर जिले में गवर्नमेंट शुरू साल में दो दो हजार आदमियों को कुछ दस्तकारियों पर लगाये, उस उद्योग पर सरकारी सुपरवीजन हो और वह सरकारी पैसे से ही चलाया जावे। मिसाल के तौर पर करघा है, लकड़ी या शीशे का काम है। गवर्नमेंट दूसरे पंचसाला प्रोग्राम के पहले साल से ही दो दो हजार लोगों को लेकर, उनमें समितियां बना कर अपने जरिये से पैसा लगा कर सामान तैयार करायें और उसकी बिक्री भी खुद करायें, और अगर उसमें नुक्सान हो तो उसको गवर्नमेंट भरें। इस तरह से तजुर्बा होगा गवर्नमेंट को कि काटेज इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट गवर्नमेंटल लेविल पर चला सकती है या नहीं?

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम सरकार का इसलिये शुक्रिया है कि सरकार ने हमें यह अवसर दिया कि हम एक महत्वपूर्ण समस्या के ऊपर अपने विचारों को सदन के सामने प्रगट कर सकें। जिस समय कि मैं प्लानिंग की बात सोचता हूं, और आज की डिबेट्स का मुझे स्मरण आता है तो मेरे दिल में एक ख्याल पैदा होता है कि वास्तव में प्लानिंग की बहस तो कम है, एक बजट के ऊपर डिस्कशन ऐसा है, और मुझे यह भी प्रतीत होता है कि जिसको हम प्लानिंग कहने जा रहे हैं ५ वर्ष का, वह भी एक ५ वर्ष का बजट ही है और उस बजट के ऊपर एक डिस्कशन सा चल पड़ा है। पिछले साल के ५ वर्ष का प्लानिंग

[श्री नौरंगलाल]

जो कि सदन के सामने प्रस्तुत किया गया, उसके लिये तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि न तो किसी देश ने पहली मर्तबा कोई प्रथम प्लानिंग की है, बल्कि प्लानिंग हमेशा ही कुछ समय बीतने पर ही हुआ करती है। एक भूखा इंसान होता है, वह खाना खाता है, उसके बाद सोचता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से रोजगार करना है? वही हिसाब गवर्नमेंट का हुआ करता है। इसलिये प्रथम प्लानिंग के लिये किसी माननीय सदस्य को इस नुक्ते निगाह से नहीं देखना चाहिये कि वह एक प्लानिंग थी, वह तो एक नेसेसरी बजट था ५ साल का। हमारे देश के अन्दर भुखमरी थी, नंगापन था और गवर्नमेंट को इनको पूरा करना था और उसने पूरा किया जिस तरह से भी हो सके। इसलिये इसको क्रिटिसाइज न करते हुये इसकी दूसरी साइड को अवश्य देखना है कि प्लानिंग जो हम अब करने जा रहे हैं, अब हम इस स्टेज पर आ गये हैं और अब हम योजना या प्लानिंग को समझ सकते हैं। इसलिये अब हमें देखना यह है कि जो कदम हम उठाते हैं वह प्लांड है या नहीं या फुटकर है ? इस दृष्टि से हमें अगले पंचवर्षीय योजना के प्लानिंग को देखना है। पिछली बातों की तरफ मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा।

एक बात और है और वह यह है कि जब हम डेवलपमेंट और प्लानिंग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। एक चीज डेवलपमेंट हो सकती है लेकिन वह प्लानिंग नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया, फूड प्रोडक्शन बढ़ाया और इंडस्ट्रीज को बढ़ाया लेकिन हमें देखना यह है कि वह प्लांड थी या नहीं, इसमें संदेह है। डेवलपमेंट और प्लानिंग में केवल एक अन्तर है जिसको शुरू में ही समझ लेना चाहिये, और वह यह है कि हम एक बाग को देखते हैं और हम एक जंगल को देखते हैं। जंगल एक डेवलपमेंट है और बाग जो हम देखते हैं वह एक प्लांड डेवलपमेंट है। यही डिसटिंक्शन प्लानिंग और डेवलपमेंट में हुआ करता है। हमेशा किसी सोसायटी का जो प्लानिंग हुआ है वह उसके रिजल्ट को देखकर कह सकते हैं कि आया वह प्लानिंग प्लांड था या फुटकर था ? हर आदमी की कृति हम उसके कार्य से जान सकते हैं।

आज हम देखते हैं कि प्लानिंग को चाहे प्लानिंग कहा जाय या बजट कहा जाय। शिक्षा में, इंडस्ट्रीज में और आबकारी में और कहीं भी जायं उसके नतीजे को देखें कि कामयाबी हुई है या नहीं ? सच बात कहने में किसी को किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिये। हम देखते हैं कि हमने शिक्षा के ऊपर कई करोड़ रुपया व्यय किया है, सही है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ ? शिक्षा का एक ही तात्पर्य था कि अपने प्रदेश में डिसिप्लिन कायम करें और अपने प्रदेश में ऐम्पलायमेंट लोगों को पैदा करें, लेकिन हम आज देखते हैं कि हमारी शिक्षा से न तो हमारे यहां डिसिप्लिन ही पैदा हुई और न इम्पलायमेंट ही पैदा हुआ। इसी तरह से हम अपने यहां इन्डस्ट्रीज की हालत को देखते हैं। उनका प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ, नई इंडस्ट्रीज खुलीं और घर-घर स्कूल खुले, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। इसी तरह से आबकारी को लीजिये। शराब बन्दी की गई लेकिन घर-घर शराबखाने खुल गये। इससे इसके रिजल्ट से मालूम होता है कि कहीं कुछ न कुछ गल्ती है। इसलिये हमें देखना है कि कहां गल्ती है ? लेकिन समझ में नहीं आता है कि कहां गल्ती है और जब तक इस गल्ती को समझ नहीं पाते हैं तब तक हम प्लांड सोसाइटी नहीं बना सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारे सामने उद्देश्य साफ नहीं है। लेकिन हमारे सामने यह उद्देश्य है कि हम सोशेलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करें यह उद्देश्य है और इसके मातहत हमें काम करना है। इसलिये सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें किसी न किसी तरह से प्लांड सोसाइटी कायम करना है इसके लिये हमें देखना है कि क्या कमियां हैं और इनको दूर करने का क्या तरीका है ? जब तक हम यह सजैशन न दे दें तब तक हमारा यहां व्याख्यान देना बेकार हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट की भी डिफिकल्टीज हैं और गवर्नमेंट के लिये यह इम्पौसीबिल टास्क है और मैं समझता हूं कि इसमें गवर्नमेंट की कोई विशेषता भी नहीं है। प्लानिंग हमेशा योनेट्री टाइप बेसिज पर हुआ करती है, फिडरल पर नहीं।

यूनेटरी प्लानिंग को हम सोचते नहीं हैं लेकिन हम गवर्नमेंट के पीछे फेडरल प्लानिंग के लिये पड़ जाते हैं। इससे दुनिया में कामयाबी हो नहीं सकती है और न हुई है। इसलिये पहले तो इस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है कि हमें कोई भी स्टेप जो उठाना है वह सेंट्रल के डाइरेक्शन में जो कि वहां का प्लानिंग कमीशन है, उसके मातहत हमें उठाना पड़ेगा और जो डाइरेक्शन वह हमें देंगे उस प्लानिंग के मातहत ही हमें इस काम को करना पड़ेगा। जब तक हम इस तरीके पर नहीं चलते और फेडरल प्लानिंग को नहीं छोड़ते और यूनिटरी प्लानिंग को नहीं अपनाते, उस समय तक हमें इसको फाइव ईयर प्लान कहने का कोई हक नहीं है।

इस तरह से यह पहली दिक्कत थी जो कि हमारे सामने आई। लेकिन इसके अलावा और भी डिफिकल्टीज हैं। कुछ नेचुरल हैं और कुछ आदमी की बनाई हुई हैं। वह स्टेट जहां भी प्लानिंग हुई है वहां, अगर यह तीन दिक्कतें हैं तो वह सारा काम मिस्मार कर देते हैं सब सत्यानाश कर देती हैं। वह दिक्कतें अंग्रेजी के एक शब्द एफ से निकलती हैं। वह हैं फैमीन, फ्लड और फैमली। यह तीनों दिक्कतें सबके सामने आ कर पड़ जाती हैं। हम चाहे कुछ भी करते रहें, चाहे नहरें खोदें या कुयें बनवायें, हम प्रोडेक्शन बढ़ाते हैं लेकिन एक हमला होता है नेचर का और इतना डिवास्टेशन हो जाता है कि सब किया कराया बेकार हो जाता है। कभी फ्लड हो जाता है और कभी फैमली। फैमिली शब्द से चौंकिये नहीं, उसके माने यह हैं कि हमारी फूड की समस्या दिनों दिन तंग होती जाती है। फूड की जरूरत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि पर कैपिटा इन्कम कम हो गई। एक एकोनामिस्ट ही समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ और कैपिटा इन्कम कम हो गई। यह तो एक थ्योरी है कि फूड प्रोडेक्शन पापुलेशन के साथ साथ बढ़ नहीं सकता। फूड बढ़ता है अर्थमेटिकली और पापुलेशन बढ़ती है ज्योमेट्रीकली। तो उससे पर कैपिटा इन्कम कम हो जायगी यह नेचुरल है। इसके लिये फैमली की प्लानिंग जरूर किसी न किसी तरह से हमको करनी चाहये। जो पापुलेशन हमारी बढ़ रही है उसको रोकना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो हमारा प्लानिंग करना बेकार होगा।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें। मैं सदन को दो सूचनायें देना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सूची

श्री अध्यक्ष—यह चेयरमैन, विधान परिषद की तरफ से सूचना इस सदन को आई है विधान परिषद की नियमावली के नियम ११८ (३) के अन्तर्गत मुझे आपको यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १८ अक्तूबर, १९५५ की बैठक में राजस्व मंत्री का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।"

विधान परिषद ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त संयुक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है :

१—श्री शिवप्रसाद सिन्हा
२—श्री नरोत्तमदास टंडन
३—श्री प्रतापचन्द्र आजाद

४--श्री तेलूराम
५--श्री बृजलाल वर्मन, हकीम
६--श्री बंशीधर शुक्ल
७--श्री बालकराम वैश्य
८--श्री ज्योतिप्रसाद गुप्त

तो इसमें इस सदन की तरफ से १६ सदस्य निर्वाचित होना है। इसलिये मैं समझता हूं कि कल के रोज इस विषय पर प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ले आयेंगे।

प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--प्राक्कलन समिति के दो रिक्त स्थानों के लिये ८ सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। इसलिये दो सदस्य रह गये हैं और दो ही सदस्य चुने जाने हैं, तो मैं उनको विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूं। उनके नाम यह हैं:--

१--श्री प्रेमकृष्ण खन्ना
२--श्री मलखान सिंह

आजमगढ़ जिले में लउआसाथ ताल तथा अन्य मीनाशयों के ठेके से सम्बन्धित १२ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३१ और १० अक्तूबर, १९५५ के तारांकित प्रश्न ७ व ८ के विषय पर विवाद

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जमींदारी समाप्ति के बाद मीनाशयों का प्रबन्ध जब भूमि प्रबन्धक समिति को सिपुर्द किया गया और भूमि प्रबन्धक समिति के लिये प्रान्तीय सरकार की ओर से मौके-मौके कुछ आदेश जारी होते रहे, उन आदेशों का संकलन माननीय मंत्री जी सन् १९५३ में किया। मैं सदन की जानकारी के लिये कुछ नियमों का वर्णन करना आवश्यक समझता हूं जिससे साफ हो जायगा कि भूमि प्रबन्धक समिति ने इन मीनाशयों के सम्बन्ध में जो अवैधानिक काम किये हैं, उनकी बाबत नियम ४१ (२) में यह साफ लिखा हुआ है कि "जब १३५९ फसली की खतौनी में किसी आदमी के बारे में यह दर्ज हो कि यह किसी तालाब या पोखरे या उसके किसी भाग में मछली पकड़ने के लिये रकम सिवाय या लगान देता है तो ऐसे आदमी का अधिकार बना रहने देना चाहिये। किन्तु ठेका एक ही साल के लिये होगा और हर साल उसे फिर से नया करना चाहिये। लगान पिछले पांच वर्षों के औसत में उसका १० प्रति सैकड़ा जोड़ कर निश्चित किया जायेगा। यदि उस औसत और उसके दस प्रतिशत सैकड़े का जोड़ १३५९ फसली की खतौनी में लिखी हुई रकम से कम हो, तो ठेका खतौनी में लिखी रकम पर ही दिया जाना चाहिये।" श्रीमन, इसके अलावा आप यह देखेंगे कि "मछली पकड़ने के अधिकारों के नीलामों में सबसे ज्यादा रकमों की बोलियां स्वीकार की जायंगी, चाहे ऐसे नीलाम भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किये जायं या कलेक्टर द्वारा। किन्तु यदि सबसे ज्यादा रकम की बोली बोलने वाला आदमी स्थानीय पेशेवरों (मल्लाह या धीमर इत्यादि) के वर्ग का न हो और ऐसे वर्ग के किसी दूसरे बोली बोलने वाले की ऐसी बोली हो जिसकी रकम सबसे बड़ी रकम बोली की रकम के ७५ प्रतिशत से कम हो तो उसी को मछली पकड़ने के अधिकार का पट्टा दे दिया जायगा।" यह इसी गांव समाज मैनुअल में छपा हुआ है। इनसे श्रीमन् साफ मालूम होता है कि जिस व्यक्ति का नाम १३५९ फसली की खतौनी में दर्ज होगा उसी की मालगुजारी दर्ज होगी और उसी को ठेका मिलेगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर किसी का नाम दर्ज नहीं है और मालगुजारी लिखित नहीं है तो २५ फीसदी कम करके उस व्यक्ति को ठेका मिलेगा

जो पेशेवर हैं। मैं जब इस उत्तर को इस कसौटी पर कसता हूं तो समझ यह बात आती है कि यह बिलकुल जवाब गलत है। माननीय मंत्री जी ने और उनके उप मंत्री महोदय ने जो वहां के सभापति हैं और उन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है उस पर परदा डाला है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसी गांव समाज मैनुअल के पेज ३१ में यह लिखा हुआ है कि:"भूमि प्रबन्धक समिति को अपने कामों के बारे में सरकार की आज्ञाओं और हिदायतों का पालन करना होगा।" इसी के पेज ३२ में यह लिखा हुआ है कि "भूमि प्रबन्धक समितियों के काम की देख भाल"। उसमें यह है कि "हाकिम परगना का यह कर्त्तव्य होगा कि वह खुद निरीक्षण करके और तहसीलदार, नायब तहसीलदार या सुपरवाइजर कानूगो द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कराकर भूमि प्रबन्धक समिति के कामों की देख-रेख करे। यदि निरीक्षण नोटों में हाकिम परगने द्वारा दिये गये आदेशों की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा बराबर अवहेलना होती रहे तो ऐसी समिति धारा १२७ के अन्तर्गत तोड़ दी जायगी।" श्रीमन्, यह गांव समाज मैनुअल जो माननीय मंत्री जी के हुकुम के जरिये प्रकाशित हुआ है, मैं जब इनको पेश करता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि परगना हाकिम इस गांव समाज के कामों को देखता नहीं रहा है, या देख कर अपने दल का होने के कारण जान-बूझ कर उपेक्षा करता रहा है। श्रीमन्, इसकी बिलकुल अवहेलना की गयी है। अगर आप इसमें नम्बर ३१ के उत्तर को देखें तो इसमें साफ इंकार किया गया है कि सितम्बर सन् ५४ में भूमि-प्रबन्धक-कमेटी ने ठेका दिया। मैं इसको कह देना चाहता हूं कि यह जिस गांव की चर्चा है वह मेरे घर से ४ फर्लांग पर है। इस ठेके को देकर भूमि-प्रबन्धक-कमेटी ने बिलकुल गैर कानूनी कार्य किया है। मैं आपके सामने १३५९ फसली की खतौनी पेश कर सकता हूं जिसमें उन धीमरों का नाम दर्ज है जिनको ठेका दिया जाना चाहिये था, लेकिन उनको ठेका न देकर एक व्यक्ति को ठेका दिया गया जो पेशेवर नहीं है। ठेका उस गांव के एक सम्पन्न व्यक्ति को दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने परगना हाकिम को हुक्म दिया लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ५३ में भी मौके पर जाकर ठेके को कैंसिल किया। सन् ५४ में भी परगना हाकिम ने फिर उन्हीं लोगों को ठेका दिलवा दिया जो पेशेवर नहीं थे। आप देखेंगे कि मैंने सवाल किया था कि परगना हाकिम की रिपोर्ट देरी से आने के कारण ही ठेका देने में विलम्ब हुआ, जिसका उत्तर मिला कि ऐसा नहीं हुआ। श्रीमन्, यह अवैधानिक काम गांव-समाज मैनुअल के खिलाफ है, भूमि-प्रबन्धक-कमेटी और उसके निरीक्षक परगना हाकिम ने किया है। जब दो सालों से गांव समाज के प्रधान ने गैर कानूनी काम किया तो उन्हीं मल्लाहों ने परगना हाकिम के पास और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास मेरे जरिये से दरख्वास्त दी। लेकिन परगना हाकिम उन लोगों के साथ में है जो कि गांव के भूतपूर्व जमींदार हैं या गांव के गैर पेशेवर हैं। और जिनके पक्ष में गांव समाज के प्रधान ने ठेका दे रक्खा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ठेके के खिलाफ दरख्वास्त देने के कारण उनके विरुद्ध धारा ३७९ और १०७ के तहत मुकदमा चलाया गया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष---अब आप संक्षेप में कह दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, आपके जरिये से मैं सदन से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह का अवैधानिक कार्य भूमि-प्रबन्धक-समिति ने और परगना हाकिम ने किया है और माननीय मंत्री जी को गलत उत्तर देकर उनकी आंखों पर परदा डाला है, इसलिये उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय।

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुन्दर जी पांडेय इस मजमून को सन् ५४ से पीस रहे हैं। बिलकुल इन्हीं तालाबों का ठेका दिये जाने के सिलसिले में मेरे पास ५ मिसालें हैं, उनमें बराबर यही सवाल है। फाइल नं० ५/५४, जिसमें

[श्री चरणसिंह]

पहली बार सवाल पूछा गया, फाइल नं० ४६/५४ जिसमें दुबारा सवाल हुआ, फाइल नं० २१/५५, जिसमें इसी ठेके की बाबत फिर सवाल पूछा गया। फिर फाइल नं० ३५/५५ में वे ही तालाब हैं, वे ही मछेरे हैं और वे ही मछलियां हैं।

श्री अध्यक्ष---मछलियां तो बहुत से लोग खा गये होंगे ?

श्री चरणसिंह---मछलियां तो मोटी-मोटी पड़ी होंगी जो तीन साल से नहीं पकड़ी गयी होंगी। तो अध्यक्ष महोदय मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी की निगाह में ये पोखर, ये तालाब और ये मछलियां बहुत बड़ा महत्व रखती हैं और इन मछेरों तथा तालाबों से माननीय रामसुन्दर जी को बड़ा मोह है, यह तो साबित हो गया। अब देखना यह है कि आखिर क्या भूमि-प्रबन्धक-समिति से कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है ? आपका जो सवाल था जिसके सिलसिले में यह बहस हो रही है वह यह था। उसका जवाब भी मैं सुना देता हूं।

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत कितने ऐसे मीनाशाय हैं जिन पर १३५९ फसली की खतौनी में मछली मारने वालों का नाम एवं मालगुजारी दर्ज है ? इसका जवाब यह था.....

"खतौनी में तालाबों का सिर्फ नम्बर और रकबा लिखा होता है। जो आमदनी शिकारमाही से जमींदार को होती थी उसकी रकम और देने वाले का नाम और उनकी नौइयत खतौनी की जिमन १३ में दर्ज होती है। तहसील घोसी जिला आजमगढ़ में कुल ८ ऐसे मीनाशयों का पता लगा है जिनसे शिकार माही की आमदनी जमींदार को होती थी और वह खतौनी की जिमन १३ में दर्ज थी।"

अध्यक्ष महोदय, इसके सिलसिले में मेरे माननीय मित्र ने गांव समाज मैनुअल के पैराग्राफ ४१ की तरफ इशारा उसका ध्यान खींचा है। नियम यह है कि मछली का ठेका देने में जैसे जमींदार लोग मछली का ठेका देकर आमदनी लेते थे वैसे ही गांव समाज, भूमि-प्रबन्धक-कमेटी या गांव समाज की विलेज-कम्युनिटी भी, आगे उनसे आमदनी हासिल कर सकेगी, फायदा उठा सकेगी। कोई वजह नहीं है कि जमींदार जब उनसे आमदनी करते थे, मछेरों से पैसा लेते थे, मल्लाहों से पैसा लेते थे, तो उससे गांव समाज ही क्यों महरूम रहे ? हमने यह रखा है कि १३५९ फसली में खतौनी में जिनका नाम दर्ज हो उन्हीं को ठेका दिया जाय। पांच साल का औसत लगाया जाय जो जिमन १३ में दर्ज है कि कितने का ठेका उन्हें पहले देते थे, कितना जमींदारों को पैसा मिलता था? गांव समाज उससे दस प्रतिशत बढ़ा सकता है, ज्यादा नहीं। जहां तक मछली मुफ्त में मारने देने की बात है कि जमींदार लोग कोई पैसा नहीं लेते थे और कुछ लोगों को मुफ्त में ही मछली देते थे तो क्या गांव समाज भी उस आमदनी से वंचित हो जाय ? मैं तो समझता हूं कि गांव समाज को उससे आमदनी होनी चाहिये। दूसरा पहलू हमारे सामने यह था कि अगर जमींदारी एबालिशन से पहले मछेरे या कोई भी वर्ग ऐसा था जिनके ऊपर कम्युनिटी का कोई भार नहीं था और उनको पैसा देना पड़े तो वे कहेंगे कि यह अच्छी जमींदारी का एबालिशन हुआ, और यह अच्छी गांव पंचायत हुई ! इस चीज को भी हमें सोचना था। इसलिये हमने तय यह किया कि अगर लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी यूनानिमसली यह तय करे कि यद्यपि जमींदार पहले कुछ नहीं लेता था परन्तु हम आगे को ठेका देंगे, और उस पर तमाम बातों को देख कर कलक्टर एप्रूवल दे दे तो ऐसी जगहों पर भी जहां मछली मारने का ठेका नहीं होता था, लैंड मैनेजमेंट कमेटी नीलाम से ठेका दे सकती है। परन्तु अगर यूनानिमसली तय न हो, यानी एक आदमी भी डिफर करे तो नहीं दिया जा सकता, और माही बिला कुछ दिये मछली का शिकार करते रहेंगे। और क्योंकि वह पब्लिक बाडी है इसलिए उसमें भी आगे सहूलियत रखी है कि अगर नीलाम की आखिरी बड़ी बोली गैरमाही की है जिनका यह पेशा नहीं है, और उस काम को नहीं करता तो फिर किसी मल्लाह को अधिकार होगा कि अगर वह ७५ प्रतिशत बोली बोलने को तैयार है तो ठेका उसके नाम छूट जायगा। यह हमारी स्कीम थी। इस तरह से यह तीन चीजें थीं कि अव्वल तो यूनानिमस

राय सब की होनी चाहिए, एक भी उसके खिलाफ अगर होगा तो ठेका नहीं दिया जा सकता। दूसरे उस पर कलेक्टर का एप्रूवल होगा और अगर वह भी सब बात देखकर एप्रूवल दे दे तो नीलाम होगा फिर भी अगर सब से अधिक बोली गैर माही की होगी कोई भी माही उस अधिकतम बोली से २५ प्रतिशत कम पर ठेका ले सकता है। यह सब हमने गांव समाज को हिदायत दे दी है। अब रामसुन्दर जी पांडेय यह कहते हैं कि घोसी तहसील में जो ऐसे ८ मीनाशय हैं वहां दूसरे लोगों को ठेका दिया गया है। कलक्टर का कहना यह है कि हमने ठेका दिया बेशक, लेकिन जिन लोगों का नाम दर्ज था उनको भी दिया और तहकीकात से मालूम हुआ कि जिनके नाम दर्ज नहीं थे लेकिन जो हमेशा जमींदार को उसका पैसा दिया करते थे, और जो ठेका लिया करते थे लेकिन जिनका नाम किसी वजह से खतौनी में दर्ज नहीं होता था, उनको भी दिया है। जिनका नाम दर्ज था उनको भी दिया है और उनको भी दिया जो ठेका लिया करते थे और जमींदारों को पैसा दिया करते थे लेकिन जिनका नाम दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई भी तालाब ऐसा नहीं है जिसमें उनको ठेका दिया हो जिनके नाम दर्ज थे बल्कि उनको दिया गया है जिनके नाम दर्ज नहीं थे। लेकिन दरअसिल मछेरो का काम वह करते थे। उनका कहना यह है कि उनको क्यों दिया? अध्यक्ष महोदय, देखना यह है कि उस "रेकर्डेड" शब्द को पकड़ रहे हैं, अगर उनका यह खयाल है तो मैं अबके बार "रेकार्डेड" शब्द को निकाल दूंगा। वह इसलिए रख दिया था कि हमको नहीं मालूम था कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो "रेकर्डेड" न होंगे। लेकिन कलक्टर का कहना यह है कि हमने तहकीकात कर ली और उससे मालूम हुआ कि ऐसे भी माही है जो रेकर्डेड नहीं थे, लेकिन असिल में वह जमींदार को पैसा देते थे, इस लिये उनको भी शामिल कर लिया। देखना यह है कि कौन सा बड़ा भारी अन्याय हो रहा है? कोई ऐसा मामला है कि जिस को बार बार-यहां उठाया जाय, या कोई ऐसा मामला यह है कि जिसको सन् ५४ से अब तक ४ बार उठाया जाय। यह जो पखड़ी का तालाब है जो ८ तालाब....

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री अध्यक्ष—मालूम होता है कि लोगों को मछली में दिलचस्पी नहीं है।

(कुछ देर तक घंटी बजने के अनन्तर)

श्री अध्यक्ष—अब कोई आने वाला नहीं दिखाई देता। तो अब हम उठते हैं और कल फिर ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद कोरम के अभाव में सवन ५ बज कर २२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

राधेरमण सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१९ अक्तूबर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

१९५४ में मिले और व्यय किये गये अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	अनुदान का नाम	१९५४ के प्रारम्भ में धनराशि	१९५४ में व्यय की गई धनराशि	१९५४ के अन्त में धनराशि	विवरण
१	फिजिकल कल्चर-ग्रांट	२,७००-०-०	६५०-०-०	२,०५०-०-०	
२	सेल्फ हेल्प	८९,८७३-८-३	३६,९७८-०-०	५२,८९५-८-३	
३	वन विभाग के लिए अनुदान	५,०००-०-०	१८-०-०	४,९८२-०-०	
४	शिक्षण अनुदान	९९००-०-०	९,९००-०-०	..	
५	छुआछूत दूर करने के लिए अनुदान	१,०००-०-०	१२५-०-०	८७५-०-०	
६	डिश्क्रीशनरी ग्रांट	१६,३५६-१३-०	१०,१७०-३-६	६,१८६-९-६	
७	लोकल डवलपमेंट अनुदान	८६,८६२-०-०	८,८५०-०-०	७८,०१२-०-०	
८	हरिजनों के मकानों के लिए अनुदान	२,२२४-१-०	७५०-०-०	१,४७४-१-०	
९	हरिजन कुटीर उद्योग के लिए अनुदान	८,२००-०-०	५५०-०-०	७,६५०-०-०	
१०	हरिजनों के पीने के पानी के लिए अनुदान	१०,२००-०-०	५,८६०-०-०	४,३४०-०-०	
११	हरिजन सहायक अनुदान	२०,८०-१०-६	३७५-९-३	१,७०५-१-३	
१२	सैकंशड वर्क्स अनुदान	१,६०,५२७-०-०	..	१,६०,५२७-०-०	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

सूची नम्बर २

सामुदायिक योजना क्षेत्र बहादुरपुर को छोड़ कर किसी अन्य क्षेत्र में नियोजन विभाग द्वारा घरेलू उद्योग-धंधे चालू नहीं किये गये हैं। सामुदायिक योजना क्षेत्र बहादुरपुर के निम्नलिखित स्थानों पर जो उद्योग चलाये जा रहे हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है।

(अ) बहादुरपुर, तहसील बस्ती---रंगाई-छपाई की ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र

(ब) नगर तहसील बस्ती---सिलाई की ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र

उपर्युक्त उत्पादन केन्द्र सामुदायिक योजना कोष से कुटीर उद्योग विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१० पर)

सूची नं० १

क्रम-संख्या	स्कूल का नाम जिसके लिये अनुदान स्वीकृत किया गया	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत अनुदान	एडवांस की तिथि	दिया हुआ एडवांस
१	अकबरपुर	२२-३-५५	५००	२६-५-५३	२५०
				६-६-५३	२५०
२	कुरौनटी	"	२००	२६-५-५३	१००
				६-६-५३	१००
३	कसबा	"	२००	२६-५-५३	१००
		१-१०-५३	२००	६-६-५३	१००
				२१-१०-५३	३००
४	लहरगांव	२३-३-५३	२००	२६-५-५३	१००
		१-१०-५३	३००	६-६-५३	१००
				२१-१०-५३	३००
५	मनपुरा	२२-३-५३	२००	२६-५-५३	१००
		१-१०-५३	३००	६-६-५३	१००
				२१-१०-५३	३००
६	छोंका	२२-३-५३	२००	२६-५-५३	१००
		१-१०-५३	३००	६-६-५३	१००
				२१-१०-५३	३००
७	ओंका	२२-३-५३	५००	२६-५-५३	२५०
				६-६-५३	२५०
८	घूसिया	२२-३-५३	३५०	५-६-५३	३५०
		१-१०-५३	१५०	२१-१०-५३	१५०
९	लोना	२२-३-५३	३५०	५-६-५३	३५०
		१-१०-५३	१५०	२१-१०-५३	१५०
१०	पांचोपुरी	२२-३-५३	२००	५-६-५३	२००
		१-१०-५३	३००	२१-१०-५३	३००
११	कुंडा	२२-३-५३	१५०	५-६-५३	१५०
१२	कुंडा बुजुर्ग	२२-३-५३	१५०	५-६-५३	१५०
		१-१०-५३	३००	२१-१०-५३	३००
१३	अटाटोप	२२-३-५३	१५०	५-६-५३	१५०
		१-१०-५३	३००	२१-१०-५३	३००
१४	धामोरी	२२-३-५३	१५०	५-६-५३	१५०
		१-१०-५३	३००	२१-१०-५३	३००
१५	गुलाओपुरा	२२-३-५५	१५०	५-६-५३	१५०
		१-१०-५३	३००	२१-१०-५३	३००

अध्यक्ष विधान सभा

क्रम-संख्या	स्कूल का नाम जिसके लिये अनुदान स्वीकृत किया गया।	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत अनुदान	एडवांस की तिथि	दिया हुआ एडवांस
१६	महाराजपुर	२२-३-५३	१५०	५-६-५३	१५०
		१-१०-५३	३००	२१-१०-५३	३००
१७	गोपालपुरा	२२-३-५३	१५०	५-६-५३	१५०
		१-१०-५३	३००	२१-१०-५३	३००
१८	पीपरी केलिया	२२-१-५३	१५०	५-६-५३	१५०
		१-१०-५३	३५०	२१-१०-५३	३५०
१९	जुगराजपुरा	२२-३-५३	१५०	५-६-५३	१५०
२०	मानेचा	२२-३-५३	५००	२६-५-५३	२५०
				६-६-५३	२५०
२१	गुधेला	२२-३-५३	२५०	२६-५-५३	१२५
				६-६-५३	१२५
			८,८५०		८,८५०

सूची नं० २

स्थानीय जांच से निम्नलिखित स्थिति पाई जाती है (बाकी स्थानों की जांच की जा रही है)

नाम स्कूल		सामान जो दिया गया	नकद रुपया
१—घुसिया	..	२५ बोरी सीमेन्ट	
२—लोना	..	२५ बोरी सीमेन्ट	१०० रुपया
३—पचीपुरी	..	४३ लट्ठा	
४—कुंडा	..	..	१५० रुपया
५—कुदरा बुजुर्ग	..	४३ लट्ठा	
६—जटाटोपुर	..	४२ लट्ठा	
७—घुमरी	..	४५ लट्ठा	
८—पिपी केलिया	..	२२ लट्ठा	

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३११ पर)

तालिका

	वेतन-क्रम	स्थानों की संख्या
(१)	२५०—२५—४००—ई० बी०—३०—७००—ई० बी०—५०—८५०	१
(२)	२००—१०—२५०—ई० बी०—१०—३१०—ई० बी० १४—४५० रु०	४
(३)	१२०—८—२००—ई० बी०—१०—३०० ..	१५
(४)	१००—८—१४०—१०—१७० ..	२
(५)	८५—५—१५०	१
(६)	८०—५—१५०	६
(७)	८०—५—१००—६—१३० ..	५
(८)	७५—५—१५०	१
(९)	६०—३—९०—४—११० ..	१६
(१०)	६०—४—८०—ई० बी०—४—१०० ..	३०
(११)	४०—२—वाई—५०—ई० बी०—३ वाई—६५ ..	१८
(१२)	२५—१—३५	५७
(१३)	२२—१/२—२७ या २७—१/२—३२ ..	३४
	योग ..	१९०

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

क्रमांक	डाक्टरों के नाम	परीक्षण काल के आरम्भ होने की तिथि	परीक्षण काल के समाप्त होने की तिथि	विशेष विवरण
१	डा० सुशीलकुमार सक्सेना	२०-४-१९५४	१९-४-१९५५	
२	,, बालकृष्ण भरद्वाज	२०-४-१९५४	१९-४-१९५५	
३	,, बालकान्त चन्द्र सन्गल	,,	,,	त्याग-पत्र दे दिया,
४	,, गोपाल शंकर भटनागर	,,	,,	देहान्त हो गया।
५	,, चूड़ामनि अग्रवाल	,,	,,	
६	,, कृष्णलाल अरोरा	,,	,,	
७	,, उमानाथ मेहरोत्रा	,,	,,	
८	,, नरेन्द्र वर्मा	,,	,,	
९	,, द्वारिका नाथ मुकर्जी	,,	,,	
१०	,, प्रेम किशोर पांडे	,,	,,	
११	,, सहदेव बिरमानी	,,	,,	
१२	,, गोपाल कृष्ण मिश्रा	,,	,,	
१३	,, मेहरवान सिंह	,,	,,	
१४	,, सुरेशचन्द्र मेहरोत्रा	,,	,,	
१५	,, चक्खन लाल	५-७-१९५४	४-७-१९५५	
१६	,, बलवन्त सिंह यादव	२०-४-१९५४	१९-४-१९५५	
१७	,, अमरनाथ जोतशी	,,	,,	
१८	,, देवप्रकाश मन्चन्दा	,,	,,	
१९	,, ब्रिजनारायण गुप्ता	,,	,,	
२०	,, राम रञ्जन भट्टाचार्या	,,	,,	
२१	,, निशिरंजन कर	,,	,,	
२२	,, अजितकुमार दास गुप्ता	,,	,,	
२३	,, गुनेन्द्र नारायण घोष	,,	,,	
२४	,, भूपेन्द्र चन्द्र पाल	,,	,,	
२५	,, निरंजन दत्ता	,,	,,	
२६	,, विष्णुदत्त दुबे	,,	,,	
२७	,, कुंवर कृष्ण कौल	,,	,,	
२८	,, एस० सी० जी० भाखे	,,	,,	
२९	,, आर० सी० भाटिया	,,	,,	
३०	,, एस० डी० लुम्बा	,,	,,	
३१	,, सैयद हब्बीब अहमद	,,	,,	
३२	,, मोहनलाल	,,	,,	
३३	,, हष्नु अम्बवानी	,,	,,	
३४	,, बी० सी० सक्सेना	,,	,,	
३५	,, देवराज सलोजा	,,	,,	
३६	,, रामदेव वर्मा	,,	,,	
३७	,, नरेन्द्रपाल सिंह	,,	,,	

संसद विधान सभा

क्रमांक	डाक्टरों के नाम	परीक्षण काल के आरम्भ होने की तिथि	परीक्षण काल के समाप्त होने की तिथि	विशेष विवरण
३८	डा० आर० एस० नारंग	२०-४-१९५४	१९-४-१९५५	
३९	,, के० पी० दीक्षित	१५-८-१९५४	१४-९-१९५५	
४०	,, एच० एन० अध्योलिया	२०-४-१९५४	१९-४-१९५५	
४१	,, एच० डी० शुक्ला	,,	,,	
४२	,, डी० एन० निगम	,,	,,	
४३	,, जे० पी० चतुर्वेदी	,,	,,	
४४	,, जी० पी० माथुर	,,	,,	
४५	,, डी० एस० तिवारी	,,	,,	
४६	,, जी० एन० भार्गव	,,	,,	
४७	,, एन० एम० गुरमानी	,,	,,	
४८	,, एस० एस० गुप्ता	,,	,,	
४९	,, एम० सी० श्रीवास्तव (प्रथम)	,,	,,	
५०	,, एम० एम० राय	,,	,,	
५१	,, आर० के० मिश्रा	,,	,,	
५२	,, जी० एल० दुआ	,,	,,	
५३	,, बी० आर० आनन्द	,,	,,	त्याग-पत्र दे दिया।
५४	,, एम० एस० राजपूत	,,	,,	
५५	,, के० एन० हसन	,,	,,	
५६	,, के० सी० गुप्ता	,,	,,	
५७	,, आर० एन० मिनोचा	,,	,,	
५८	,, एम० सी० श्रीवास्तव (द्वितीय)	,,	,,	
५९	,, जे० एस० खत्री	,,	,,	
६०	,, एस० एस० पांडे	,,	,,	
६१	,, एम० आई० खान	,,	,,	
६२	,, जे० पी० जैन	,,	,,	
६३	,, एस० आर० सिंह	,,	,,	
६४	,, ज० एस० पन्चर	,,	,,	
६५	,, जे० एन० श्रीवास्तव	,,	,,	
६६	,, जे० सी० मल्होत्रा	,,	,,	
६७	,, एच० के० डी० पैरिक	,,	,,	
६८	,, जे० एम० आर० व्यास	,,	,,	
६९	,, जे० सी० चान्दना	,,	,,	
७०	,, बी० डी० मिश्रा	,,	,,	
७१	,, पी० पी० अग्रवाल	,,	,,	
७२	,, के० ए० पांडे	,,	,,	
७३	,, सी० डी० सिंह	,,	,,	
७४	,, के० बी० वर्मा	,,	,,	
७५	,, शेख अशर्फुल जमन	,,	,,	
७६	,, बी० के निगम	,,	,,	
७७	,, एम० एम० लाल	,,	,,	
७८	,, डी० एस० कपूर	,,	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक		डाक्टरों के नाम	परीक्षण काल के आरम्भ होने की तिथि	परीक्षण काल के समाप्त होने की तिथि	विशेष विवरण
७९	डा०	एम० आर० धमेजा	२०-४-५४	१९-४-५५	
८०	,,	योगेन्द्र कुमार	,,	,,	
८१	,,	टी० आर० ग्रोवर	,,	,,	
८२	,,	सी० एल० पटने	,,	,,	
८३	,,	जे० सी० गोविल	,,	,,	
८४	,,	वी० एल० ओनेजा	,,	,,	
८५	,,	पी० सी० शर्मा	,,	,,	
८६	,,	बी० एल० गुप्ता	,,	,,	
८७	,,	के० के० मुडगल	,,	,,	
८८	,,	एच० एम० एल० सक्सेना	,,	,,	
८९	,,	जगदीश्वर चन्द्र	,,	,,	
९०	,,	बी० एल० कटियाल	,,	,,	
९१	,,	बी० पी० गुप्ता	,,	,,	
९२	,,	एम० सी० खांडपुर	,,	,,	
९३	,,	एस० पी० नन्दा	,,	,,	
९४	,,	तुलसी चरण दास	,,	,,	
९५	,,	ए० एम० गुप्ता	,,	,,	
९६	,,	बी० एम० एल० गुप्ता	,,	,,	
९७	,,	के० सी० टंडन	,,	,,	
९८	,,	आर० पी० गुल्हाटी	,,	,,	
९९	,,	एस० के० डी० अग्रवाल	,,	,,	
१००	,,	आई० एस० माथुर	,,	,,	
१०१	,,	ए० के० गुप्ता	,,	,,	
१०२	,,	जी० सी० गुप्ता	,,	,,	
१०३	,,	एन० सी० पांडे	,,	,,	
१०४	,,	बी० बी० अहुजा	,,	,,	
१०५	,,	वाई० के० भूषन	,,	,,	
१०६	,,	बी० पी० सिंह	,,	,,	
१०७	,,	एस० डी० ओहरी	,,	,,	
१०८	,,	यशपाल	,,	,,	
१०९	,,	सी० पी० सिंह	,,	,,	
११०	,,	पी० के० आर० चौधरी	,,	,,	
१११	,,	टी० एस० तलवार	,,	,,	
११२	,,	आर० पी० श्रीवास्तवा	,,	,,	
११३	,,	राम सिंह	,,	,,	
११४	,,	के० के० मल्होत्रा	२६-७-५४	,,	त्याग-पत्र दे दिया।
११५	,,	जे० जी० जवली	२०-४-५४	१९-४-५५	
११६	,,	एस० एन० मल्होत्रा	२०-४-५४	१९-४-५५	
११७	,,	सन्तोष सिंह	,,	,,	
११८	,,	के० के० गर्ग	२०-४-१९५४	१९-४-५५	
११९	,,	आर० एन० चौधरी	,,	,,	

विधान सभा

क्रमांक	डाक्टरों के नाम	परीक्षण काल के आरम्भ होने की तिथि	परीक्षण काल के समाप्त होने की तिथि	विशेष विवरण
१२०	डा० आर० पी० जैन	२०-४-१९५४	१९-४-५५	
१२१	,, एस० डी० शर्मा	,,	,,	
१२२	,, के० सी० मल्होत्रा	,,	,,	
१२३	,, जी० एन० टंडन	,,	,,	
१२४	,, एस० पी० श्रीवास्तवा	,,	,,	
१२५	,, के० एन० श्रीवास्तवा	,,	,,	
१२६	,, आर० एस० चौहान	१४-१-५५	२३-१-५६	
१२७	,, जय नारायण	१२-४-५५	११-४-५६	

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए०पी० १२० एल० ए०--१९५६-७९६ ।